चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 24 अगस्त–30 अगस्त 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो–प्रभात पाण्डेय

असली प्रधानमंत्री अरुण जेटली

[समस्याएं गहराती जा रही हैं. लोग परिणाम चाहते हैं. भाजपा में भी बेचैनी है. वरिष्ठ नेताओं एवं वरिष्ठ सांसदों का प्रधानमंत्री से न संपर्क है और न संवाद. दूसरी तरफ सरकार की कार्यप्रणाली के पीछे कुछ रहस्यमयी चेहरे हैं, कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हैं और कुछ रहस्यमयी विचारधाराएं हैं. प्रधानमंत्री के भक्त कहते हैं कि इस साल, बिहार चुनाव के बाद समस्याओं का हल होना प्रारंभ हो जाएगा. सवाल यह है कि भाजपा के भीतर विश्वास बहाली का अभियान कब शुरू होगा.]

संतोष भारतीय

नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं. जब व्यक्ति सर्वशक्तिशाली होता है, तब कुछ अंतर्विरोध भी पैदा होते हैं. अगर वे अंतर्विरोध सामान्य हों, तो उन्हें सतह पर आने में देर लगती है, लेकिन अगर असामान्य हों, तो बहुत जल्दी सतह पर आ जाते हैं. कुछ अंतर्विरोध इस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में अब अंदाज़ा लगाया जाने लगा है कि वे असामान्य ढंग से क्यों आगे बढ़ रहे हैं. श्री नरेंद्र मोदी की संपूर्ण कार्यप्रणाली के पीछे कुछ रहस्यमयी चेहरे हैं, कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हैं और कुछ रहस्यमयी विचारधाराएं हैं. जब किसी देश को नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिलता है, तब यह माना जाना चाहिए कि इस तरह के रहस्यमयी घटनाक्रम पर विराम लगेगा. पर यह संयोग है कि विराम लगने की जगह रहस्यमयी घटनाक्रम पूरी तेजी से घटित हो रहा है. संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी एक अनोखे संशय में घिर गई है. जो कभी नहीं हुआ, आज वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है.

मंत्रियों का संवाद अपने प्रधानमंत्री से नहीं है, सांसदों का संवाद अपने मंत्रियों से नहीं है और कार्यकर्ताओं का संवाद अपने सांसदों से नहीं है. पिछली बार संसद सत्र के आख़िरी दिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कई लोगों ने भाषण दिए. सबसे आख़िर में वेंकैय्या नायडू ने पूछा कि क्या और किसी को कोई सुझाव देना है? बलिया से सांसद भरत सिंह उठे और उन्होंने कहा कि यहां जितनी बातें हो रही हैं, उनका ज़मीन से कोई लेना–देना नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और हम जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं. पचास प्रतिशत समय हम जनता से अपना चेहरा छिपाने में खर्च करते हैं, क्योंकि हम कहें, तो क्या कहें? भरत सिंह के आठ मिनट के भाषण ने संसद के केंद्रीय कक्ष में सन्नाटा तो फैलाया ही, लेकिन जैसे ही भरत सिंह का भाषण समाप्त हुआ, तेजी के साथ बहुत सारे सांसदों ने अपनी मेजें थपथपाईं. यह देखकर प्रधानमंत्री चौंक गए और बैठक का संचालन कर रहे वेंकैय्या नायडू भी. और, उन्होंने तत्काल कहा कि अब यह मीटिंग समाप्त होती है, प्रधानमंत्री जी को काम है. बैठक समाप्त हो गई. लेकिन, यह संकेत बताता है कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली से उनकी पार्टी ही खुश नहीं है. संघ पूर्णतय: खामोश है, नज़र रखे हुए है. कुछ–कुछ बातें बाहर आती हैं, पर वे ऐसी नहीं हैं, जिन्हें हम निर्णायक मानें. पहली बात अंडरलाइन होकर यह बाहर आई कि संघ ने अपने बीच में कहा था कि हम साल भर तक मोदी सरकार के कार्यकलापों के बारे में कोई विश्लेषण नहीं करेंगे और

सुरेश सोनी

सुरेश सोनी ने एक साल की छुट्टी ली है और अब संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने, सलाह देने और पार्टी के समाचार संघ तक पहुंचाने का काम डॉ. कृष्ण गोपाल शर्मा को सौंपा गया है.

न कोई राय देंगे. वह समय सीमा मई समाप्त होते–होते पूरी हो गई. अब संघ में थोड़ी बेचैनी है और वह रहस्यमय ढंग से होने वाली घटनाओं, रहस्यमयी चेहरों, रहस्यमयी गतिविधियों एवं विचारों को लेकर चिंतित हो गया है. अगर इस सबको समझना है, तो हमें शुरुआत से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के समय से घटी घटनाओं का विश्लेषण करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि यह सब क्या हो रहा है.

सुरेश सोनी की जगह कृष्ण गोपाल शर्मा

जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या कहें कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए देश में अपना अभियान शुरू किया, तब कई घटनाएं एक साथ घट रही थीं. भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ के प्रतिनिधि का काम सुरेश सोनी कर रहे थे. वह संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच संदेश वाहक का काम करते थे. उन्होंने यह काम अचानक बंद कर दिया. अब अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया, ताकि वह नरेंद्र मोदी

मंत्रिमंडल के गठन में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्हें देखकर भाजपा के नेता चौंक गए. अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा चुनाव हार गए. हक़ीक़त यह है कि जेटली आज तक कभी भी कोई चुनाव नहीं जीते. लेकिन, जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लिया, तो भाजपा के लोगों को थोड़ी चिंता हुई. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके सर्वाधिक विश्वस्त दो व्यक्ति चुनाव हार गए थे. पहला नाम प्रमोद महाजन का था और दूसरा जसवंत सिंह का. अटल जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया. वे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन बहुत बाद में. नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को न केवल मंत्री बनाया, बल्कि देश के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंप दिए, वित्त और रक्षा.

और संघ के बीच या दूसरे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच एक खालीपन की स्थिति पैदा (वैक्यूम क्रिएट) कर सकें. वह एक केंद्रीय मंत्री के बहुत नज़दीक थे. इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस मंत्री को मदद करने के लिए सुरेश सोनी ने यह वैक्यूम क्रिएट किया. एक तरफ़ वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ़ संघ के बीच भी हलचल हो रही थी. संघ ने सुरेश सोनी जी की जगह कृष्ण गोपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य संदेश वाहक या मुख्य कार्यपालक के रूप में भेज दिया. कृष्ण गोपाल के संबंध और समीकरण नरेंद्र मोदी से वैसे नहीं थे, जैसे सुरेश सोनी के थे. सुरेश सोनी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कड़ी का काम कर रहे थे. इसलिए उनके देश के सभी राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से रिश्ते थे. कृष्ण गोपाल अब तक नॉर्थ–ईस्ट का काम देख रहे थे. इसलिए उनके सबसे संबंध थे नहीं. उन्हें अचानक यहां पर भेजा गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच एक नई स्थिति पैदा कर दी. संघ ने देखा कि जितने बड़े बहुमत और जनसमर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें उसे कैबिनेट फॉरमेशन या सरकार बनाने की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ सूचनाएं मंगानी चाहिए, जिसके लिए कृष्ण गोपाल बिल्कुल सही व्यक्ति थे, जो सूचनाओं में न हेराफेरी करते और न अपनी निजी पसंदगी को कोई मुद्दा बनाते.

मंत्रिमंडल के गठन में जेटली की भूमिका

मंत्रिमंडल के गठन में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्हें देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चौंक गए. अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए. हक़ीक़त यह है कि अरुण जेटली आज तक कभी भी कोई चुनाव नहीं जीते. लेकिन, जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ी चिंता हुई. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके सर्वाधिक विश्वस्त दो व्यक्ति चुनाव हार गए थे. पहला नाम प्रमोद महाजन का था और दूसरा जसवंत सिंह का. अटल जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया. वे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन बहुत बाद में. नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को न केवल मंत्री बनाया, बल्कि देश के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंप दिए, वित्त और रक्षा. इतना ही नहीं, आर्थिक विषयों से जुड़े जितने भी मंत्रालय थे, उनके मंत्री वे बनाए गए, जो अरुण जेटली के सर्वाधिक नज़दीक थे या जिनकी उन्होंने सिफारिश की थी. उन मंत्रियों के चयन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि क्या वे उस पद के साथ न्याय कर सकते हैं, उस विषय को जानते हैं या उस मंत्रालय को चला सकते हैं? सिर्फ़ यह ध्यान रखा गया कि अरुण जेटली ने उनके नाम लिए हैं और वे उनके विश्वासपात्र हैं. इसलिए देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सुप्रीम कोर्ट को सरकार भ्रमित कर रही है | P-4

ओडिशा : हिसिबुरु से होकर जाता है उलिबुरु माइनिंग घोटाले का रास्ता | P-6

जब नीरा से मेरी मुलाकात हुई... | P-7

असली प्रधानमंत्री अरुण जेटली

पृष्ठ 1 का शेष

मंत्रालय हैं, वे उन्हें दे दिए गए. पहला उदाहरण निर्मला सीतारमण का है. उन्हें इकोनॉमी का न कोई अनुभव है, न कोई ज्ञान है. उन्हें इतना बड़ा मंत्रालय दे देना भाजपा के उन लोगों को, जो पार्टी का भला चाहते हैं, चौंका गया. निर्मला सीतारमण का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा देश में कोई राजनीतिक कद भी नहीं था.

दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, जो अब तक सिर्फ़ पार्टी के काम में व्यस्त रहते थे. उन्हें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री दे दी गई. अब तक यह मंत्रालय उन्हें दिया जाता रहा है, जो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं और जिन्हें देश की सबसे बड़ी आवश्यकता पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का महत्व पता हो. कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय पीयूष गोयल को दे दिया गया. अब तस्वीर उभरी कि निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वित्त मंत्री वह (जेटली) खुद. और, ये सारे लोग राज्यसभा के! इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी की नई बनी सरकार के ऊपर उन लोगों का कब्जा हो गया, जिनका रिश्ता राज्यसभा से है और जो कभी ज़िंदगी में लोकसभा या जनता के बीच सीधे संवाद के अनुभवी नहीं रहे. मैं इसे राज्यसभा का गैंग नहीं कहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे राज्यसभा का गैंग कहते हैं. उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने मंत्रालय थे, वे सब अरुण जेटली के हाथ में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आकलन करते हुए बताते हैं कि यह नरेंद्र मोदी से पहली बड़ी ग़लती हुई.

सारे देश में क़ानून से जुड़े लोगों की नियुक्तियां भी अरुण जेटली की इच्छानुसार हुईं. राम जेठमलानी इसे पसंद नहीं करते थे. राम जेठमलानी को यह भ्रम था कि नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनेंगे. इसके पीछे एक कारण था. जब तक राम जेठमलानी ने नरेंद्र मोदी के केस अपने हाथ में नहीं लिए थे, तब तक अदालतें उन्हें परेशान कर रही थीं. लेकिन, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के केस राम जेठमलानी के पास आए, तब उन्हें अदालतों से काफी राहत मिली. इसलिए राम जेठमलानी को लगता था कि वह अगर नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि यह चीज ग़लत हो रही है, इसे सुधारें, तो नरेंद्र मोदी सुधारेंगे. पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो अरुण जेटली ने कहा, उसे उन्होंने माना. अंत में राम जेठमलानी को नरेंद्र मोदी के यहां औपचारिक विरोध दर्ज कराना पड़ा और उन्होंने एक लंबी चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी कि अरुण जेटली की वजह से क्या-क्या गड़बड़ियां हो रही हैं. लेकिन, वह चिट्ठी भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूड़ेदान में फेंक दी, क्योंकि उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ. नरेंद्र मोदी के केस पहले मुकुल रोहतगी एवं स्वयं अरुण जेटली देख रहे थे और उनके जमाने में नरेंद्र मोदी को कई झटके लगे थे. राम जेठमलानी का इसीलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर अधिकार भी था. उनका यह भ्रम टूट गया कि नरेंद्र मोदी सच बात को सुनेंगे.

पहला संदेश देश में यह गया कि पूरा मंत्रिमंडल अरुण जेटली की पसंद का, अरुण जेटली केंद्रित, अरुण जेटली के फ़ैसले मानने वाला और अरुण जेटली को रिपोर्ट करने वाला मंत्रिमंडल है. इसमें सिर्फ़ एक नाम अरुण जेटली की पसंद का नहीं है, वह हैं स्मृति ईरानी. अरुण जेटली चाहते थे कि स्मृति ईरानी को राज्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जेटली की बात नहीं मानी और स्मृति ईरानी को सीधे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाने का फ़ैसला किया.

जिन लोगों को अरुण जेटली पसंद नहीं करते थे या जिनसे उनकी मित्रता नहीं थी, उन्हें उन्होंने दूसरी तरह से उनकी हैसियत बताई, जिनमें पहला नाम अनंत कुमार का है. अनंत कुमार का शपथ ग्रहण 13वें नंबर पर हुआ. अनंत कुमार अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं. उन्हें 13वें नंबर पर सदानंद गौड़ा के बाद शपथ दिलवाना यह संदेश देना है कि अगर आप अरुण जेटली के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, तो कैबिनेट में प्रभावशाली मंत्रालय नहीं पा सकते. और, उन्हें अप्रभावी मंत्रालय दिया गया. उन दिनों या उस समय नरेंद्र भाई का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि पार्टी में किसी को भी उन्हें यह सब बताने या इसके ऊपर असंतोष जाहिर करने का न अवसर मिला और न किसी की हिम्मत हुई. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित सभी लोग खामोशी के साथ निरीह ढंग से यह प्रक्रिया देखते रहे.

क्यों निशाने पर आए राजनाथ सिंह

जो लोग नरेंद्र मोदी के कद के नेता थे, जिनमें पहला उदाहरण राजनाथ सिंह का है, उनकी सार्वजनिक छवि धूमिल करने या उनका कद छोटा करने की कोशिश हुई. राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पूरी ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी-जान लगा दी, पर नरेंद्र मोदी को उनसे संवाद करने वाले लोगों ने समझाया कि राजनाथ इसलिए यह सब कर रहे हैं, ताकि यदि उनके (नरेंद्र मोदी) प्रधानमंत्री बनने में कोई अड़चन आए, उनके ख़िलाफ़ कहीं से कोई आवाज़ उठे या अदालत कहीं कोई रोक लगाए, तो वह (राजनाथ) नेचुरल च्वॉइस के रूप में उभरें और प्रधानमंत्री बन जाएं. इस कानाफूसी ने राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच वह समीकरण नहीं बनने दिया, जिससे देश का भला होता. राजनाथ सिंह, जिनका कद नरेंद्र मोदी के बराबर था, को उनकी इच्छानुसार स्टाफ नहीं रखने दिया गया. उनके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय बैठ गया और उसने राजनाथ सिंह को संदेश दिया कि वह फलां-फलां सज्जन को अपने स्टाफ में नहीं रख सकते. आम तौर पर सरकार में जो बराबर के कद के लोग होते हैं, उन्हें उनकी इच्छा का स्टाफ दिया जाता है, उसमें कभी कोई रोक नहीं लगती. पर भारत सरकार में ऐसा पहली बार देखा गया कि देश का गृहमंत्री अपना ही स्टाफ अपनी मर्जी का नहीं रख सकता. अगर यह करना भी था, तो प्रधानमंत्री चुपचाप राजनाथ सिंह से कह सकते थे कि वह अपना स्टाफ बदलें.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कभी भी आडवाणी जी का कोई प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि अटल जी और आडवाणी जी समकक्ष नेता थे. पूरी भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्य हुआ कि राजनाथ सिंह, जो पार्टी अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी के समकक्ष नेता थे, को सार्वजनिक रूप से यह ख़बर मिली. बजाय इसके कि चुपचाप प्रधानमंत्री उनसे संवाद कर लेते.

देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे कद्दावर नेता पर सबसे बड़ा हमला उनके पुत्र पंकज सिंह को लेकर हुआ. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कहीं पर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत

सच्चाई हो और उसमें 70, 80, 90 प्रतिशत बात मिलाई जाए, तो समझ में भी आता है. लेकिन, जहां कोई सच्चाई न हो, उसे डिसइनफॉरमेशन कैंपेन के तहत अपने नज़दीकी पत्रकारों के ज़रिये सारे देश में इस तरह फैला देना, जिससे राजनाथ सिंह का कद बौना हो जाए, यह बड़ी सफाई के साथ किया गया. भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस सबके पीछे अरुण जेटली का दिमाग बताते हैं. वे कहते हैं कि दरअसल, अरुण जेटली बहुत सारे अख़बारों और टीवी चैनलों के अनाधिकारिक ब्यूरो चीफ हैं. उनके यहां महफिलें लगती हैं. वह हर हफ्ते, दस दिन में पत्रकारों को खाना खिलाते हैं और ऑफ दि रिकॉर्ड कान में कुछ कह देते हैं. जेटली में एरोगेंसी इतनी बढ़ गई है कि जब वह पत्रकारों को अपने यहां खाने पर बुलाते हैं, तो उन मंत्रियों, जिन्हें उन्होंने अपनी सिफारिश से प्रभावशाली विभाग दिलवाए हैं, को न केवल दरकिनार करते हैं, बल्कि लोगों के सामने यह बताते भी हैं कि उन मंत्रियों की हैसियत उनके सामने कुछ नहीं है.

राजनाथ सिंह के साथ हुई इस घटना से कैबिनेट के बाकी सभी मंत्री डर-सहम गए. राजनाथ सिंह के साथ दूसरी बड़ी घटना सरकार में उनका कद छोटा करने की हुई. आम तौर पर अब तक यह होता आया है कि एसीसी का मेंबर होने के नाते गृहमंत्री से होकर फाइल प्रधानमंत्री तक जाती थी और तब नियुक्ति होती थी. लेकिन, अब प्रधानमंत्री के यहां से फाइल गृहमंत्री को जाने लगी है, बिना उनकी राय लिए नियुक्ति होने लगी है और उन्हें कमेटी का मेंबर होने के नाते सिर्फ़ उस पर दस्तखत करने होते हैं. यह स्थिति आज भी है. इससे यह बात कैबिनेट में फैली कि नियुक्तियों में गृहमंत्री की भूमिका शून्य कर दी गई है. राजनाथ सिंह के पास फाइलें न जानकारी और न संवाद के लिए, बल्कि सिर्फ़ सूचनार्थ जाने लगीं. देश के प्रशासन में सबसे बड़ा रोल गृह मंत्रालय का होता है. पूरे देश में, सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ संघ में संदेश गया कि यह अरुण जेटली केंद्रित कैबिनेट है और देश में जो भी होगा, उनकी मर्जी से होगा. राजनाथ सिंह ने यह स्थिति स्वीकार कर ली और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वह स्वभाव से ऐसे हैं कि पार्टी या सरकार के भीतर चलने वाले विवादों में कभी भी युद्ध नहीं करते.

सरकार के बाद संगठन पर कब्जा जमाने की रणनीति

सरकार के बाद संगठन का सवाल आया. भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि राजनाथ सिंह सरकार में जाना ही नहीं चाहते थे. वह मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि पार्टी अध्यक्ष के नाते अपना काम करना चाहते थे. लेकिन, व्यापक रणनीति में यह बात कुछ लोगों को समझ में आ गई कि अगर ऐसा होगा, तो चूंकि राजनाथ सिंह दो बार पार्टी अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने हर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां देखी हैं, ऐसे में वह सत्ता का एक केंद्र हो जाएंगे और पॉवर बैलेंस का काम करेंगे. इसलिए राजनाथ सिंह को यह ख़बर पहुंचाई गई कि संघ चाहता है कि वह अध्यक्ष पद छोड़ें, किसी और को दें और तत्काल मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं. उधर संघ को ख़बर पहुंचाई गई कि राजनाथ सिंह खुद मंत्री बनना चाहते हैं और पार्टी अध्यक्ष पद के लिए किसी और को लाने में रुचि दिखा रहे हैं. इस स्थिति में अमित शाह का चुनाव स्वाभाविक था, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने विश्वस्त व्यक्ति को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे. अरुण जेटली ने कहा कि उनसे (अमित शाह) विश्वस्त इस वक्त और कौन हो सकता है. हालांकि, अमित शाह के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पचा नहीं पा रहा था. उसका सिर्फ़ एक कारण था. उन्हें लगता था कि इससे शक्ति संतुलन या सत्ता संतुलन में असंतोष आ जाएगा और पार्टी एवं सरकार, दोनों मिलकर पार्टी की स्वतंत्र पहचान खो देंगी. पार्टी के बड़े नेता चाणक्य का एक कथन कहते हैं कि हमेशा सत्ता संतुलन बना रहना चाहिए और दूसरे शब्दों में, आग को पानी का और पानी को आग का डर बना रहना चाहिए. जब दोनों एक ही धरातल पर आ जाते हैं, तो वह स्थिति प्रशासन और राजनीति के संचालन के लिए विनाशकारी होती है.

वह विजय का दौर था, हरियाणा और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो फ़ैसले हुए, उनमें अनुभव की कमी दिखी. उदाहरण के तौर पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर मनोहर लाल खट्टर की नियुक्ति और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला. अकेले चुनाव लड़ना तो ठीक था, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह शिवसेना के साथ सार्वजनिक संवाद हुए, आरोप-प्रत्यारोप हुए, ख़बरें लीक की गईं और जिस तरह का फ्लर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी की नैतिक ताकत में बहुत कमी आई. यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ नैतिकता की बात करती है, वास्तव में उसका नैतिकता से कोई लेना-देना नहीं है.

दिल्ली पर एकाधिकार स्थापित करने की राजनीति

दिल्ली हमेशा से अरुण जेटली की जागीर रही है. उन्होंने हमेशा दिल्ली पर अपना एकाधिकार माना है. 2013 में उन्होंने विजय गोयल को हटाकर डॉ. हर्षवर्धन को दिल्ली सौंपी. फिर उन्होंने चांदनी चौक से सुधांशु मित्तल को सीन से हटाने के लिए उनका नाम काटकर डॉ. हर्षवर्धन का नाम उम्मीदवारों में जुड़वाया. अगर डॉ. हर्षवर्धन को लड़ाना ही था, तो उन्हें पूर्वी दिल्ली से लड़ाया जा सकता था, जहां उनका कार्य क्षेत्र रहा है. पर, चूंकि सुधांशु मित्तल को हटाना था और इसलिए हटाना था, क्योंकि वह प्रमोद महाजन के बहुत नज़दीक थे. सो, उनकी जगह डॉ. हर्षवर्धन लाए गए. सुधांशु मित्तल के बारे में यह माना जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं, व्यवसाय करते हैं और पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर साधनों की व्यवस्था भी करते हैं. इसलिए लंबा भविष्य देखकर दिल्ली से उन सारे लोगों को दाएं-बाएं किया गया, जो कभी भविष्य में अरुण जेटली के लिए चुनौती बन सकते थे.

भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बताते हैं कि जब इतने बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनी, तो तत्काल दिल्ली विधानसभा का चुनाव करा लेना चाहिए था, लेकिन अरुण जेटली इसके पक्ष में नहीं थे. वही पुलिस कमिश्नर और वही उप-राज्यपाल बरकरार रखे गए, क्योंकि दोनों ने अरुण जेटली के यहां अपने विश्वासी होने का संदेश सफलतापूर्वक भेज दिया था. भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यह भी कहते हैं कि जब सत्ता बदलती है, तो लोग चेहरों को भी बदला हुआ देखना चाहते हैं, पर अरुण जेटली ने ऐसा नहीं होने दिया. सात महीने तक पुलिस कमिश्नर एवं एलजी का न बदलना, आलस्य करना और दिल्ली में कोई काम न होना आदि ने भारतीय जनता पार्टी की साख पर बड़ा बट्टा लगाया. पार्टी के भीतर लगभग इस बात पर सहमति है कि यह सब अरुण जेटली की वजह से हुआ.

इतना ही नहीं, डॉ. हर्षवर्धन को पहले स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और जब उन्होंने केतन देसाई को मदद करने वाली लाइन पर अमल नहीं किया, तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर एक महत्वहीन मंत्रालय में भेज दिया गया. इसने भी पार्टी के भीतर अरुण जेटली को लेकर शंकाएं उत्पन्न कीं. लोगों को लगा कि अरुण जेटली का अपना कोई अलग एजेंडा है. लेकिन, बहुमत बहुत बड़ा था, नरेंद्र मोदी अब किसी के संपर्क में आ नहीं रहे थे. उनके संपर्क में केवल अरुण जेटली और अमित शाह थे. अन्य किसी में नरेंद्र मोदी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी. लोगों को पहला डर यह था कि नरेंद्र मोदी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और, दूसरा डर यह कि अरुण जेटली अगर नाराज़ हो गए, तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? हर्षवर्धन के इस डिमोशन ने यह सवाल पैदा कर दिया कि जो शख्स छह महीने पहले पार्टी को जिताने के लिए लाया गया और चार महीने पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था, वह अचानक इतना बुरा कैसे हो गया?

जब विजय गोयल को हटाया गया, उस समय वह दिल्ली में जी-जान से मेहनत कर रहे थे और पार्टी को उन्होंने नए सिरे से खड़ा किया था. लेकिन, जब उन्हें हटाने का फ़ैसला लिया गया, तो नरेंद्र मोदी से राय-मशविरा करके उनसे दो वादे किए गए. पहला यह कि उन्हें राज्यसभा में लाया जाएगा और दूसरा यह कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी. पार्टी के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई कि हर्षवर्धन को मंत्री इसलिए बनाया गया, ताकि विजय गोयल को मंत्री न बनाना पड़े. एक ही प्रदेश से दो कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकते और वैश्य समाज से दो हो ही नहीं सकते. यह एक मोटा सिद्धांत है. इसी सिद्धांत का सहारा लेकर विजय गोयल से वादाख़िलाफ़ी की गई और उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया.

पार्टी के भीतर इन सभी घटनाओं को अरुण जेटली के निजी एजेंडे के तौर पर देखा गया. कार्य आवंटन में अरुण जेटली की राय चली, मंत्रिमंडल के फेरबदल में उन्होंने खुद सूचना प्रसारण मंत्रालय ले लिया और रविशंकर प्रसाद को विधि मंत्रालय से हटा दिया. प्रसाद को इसलिए हटाया गया, क्योंकि उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्री के नाते इंडिपेंडेंट एजेंडा लागू करने की कोशिश की, जो अरुण जेटली को पसंद नहीं आया.

आर्थिक विकास के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय निष्क्रिय क्यों

पार्टी में एक नई चर्चा शुरू हो गई कि आप अपने विश्वासपात्र लोगों को अवश्य रखिए, लेकिन अंत में वे जिस सिस्टम को चलाने के लिए लाए गए, उन्हें उस सिस्टम को डिलीवर करना पड़ेगा. अगर आप ऐसे लोगों को विश्वासपात्र बनाते हैं, जो देश को अपने कामों से कोई नतीजा नहीं दे पाते हैं, तो यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा. आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को लग रहा है कि इस स्थिति ने पार्टी के ख़िलाफ़ देश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है. पार्टी के भीतर यह मानना है कि जितनी भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज (आर्थिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय) हैं, जो देश के विकास के लिए काम करके नतीजे ला सकती हैं, उनमें से कोई भी कामयाब नहीं है. पार्टी में एक आम राय बनी हुई है कि इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज का पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन हो गया है. देश और नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक रिफॉर्म (आर्थिक सुधार) ही है.

आज सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक फ्रंट है. लोगों ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उनके वादों को सच माना और अपेक्षा कर रखी थी कि खुशहाली आएगी. नरेंद्र मोदी बिजनेस को समझते हैं, इसलिए बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आर्थिक विकास होगा. लेकिन हुआ क्या? डेवलपमेंट की जगह फोकस काले धन पर हो गया. पार्टी के लोग कहते हैं कि नौकरी है नहीं. व्यापारियों का धंधा चल नहीं रहा है और सरकार डंडे दिखा रही है. सरकार को पता नहीं है कि वह काला धन कितना वापस ला पाएगी. लेकिन जो नए क़ानून बनाने की बात हुई, उससे सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को तलवार दे दी. आज देश में हालत यह है कि इनकम टैक्स विभाग के हर अधिकारी ने पैसा वसूलना (एक्सटार्शन) शुरू कर दिया है. हर छोटे-बड़े बिजनेसमैन के पास फोन जाते हैं या दलाल जाते हैं और वे परेशान हैं. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट मानना है कि कोई भी आर्थिक बदलाव (इकोनॉमिक चेंज) नहीं आने वाला. जिस फेरा को एनडीए सरकार ने ही

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 25
दिल्ली, 24 अगस्त-30 अगस्त 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इस सवाल पर कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी की इस गहरी मित्रता का क्या राज है? भारतीय जनता पार्टी के कम से कम तीन नेताओं ने हंसकर कहा, दिस इज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री (अनसुलझा रहस्य). जब मैंने पूछा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने दो दिनों में शपथ लेने से पहले, पूरे मंत्रिमंडल का खाका अगर अरुण जेटली ने बनाकर रखा, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उसे ध्यान से देखा नहीं? इन भाजपा नेताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी रहस्य का पता चल जाता, तो फिर क्या बात थी! पर इन नेताओं ने एक बात कही कि अरुण जेटली पार्टी के बहुत बुद्धिमान, समझदार, होशियार एसेट (संपत्ति) हैं, लेकिन वह अर्थशास्त्री नहीं हैं.

असली प्रधानमंत्री अरुण जेटली

पृष्ठ 2 का शेष

फेमा में तब्दील किया था, उसे मौजूदा सरकार ने फेरा से ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया और उसका विद्रूप स्वरूप देश के सामने रख दिया. इसकी जगह अर्थव्यवस्था में बड़े रिफॉर्म्स होते, लेकिन आपने इंस्पेक्टर राज बना दिया, ये शब्द अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़ुबान पर हैं. बिजनेस कम्युनिटी को व्यापार पर असर डालने लायक कोई भी कोशिश सरकार की तरफ़ से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है. उसकी जगह सरकार ने बिजनेस कम्युनिटी को अधिकारियों की दया पर छोड़ दिया है. विश्व का पूरा फिनांसियल मार्केट इस इंतज़ार में बैठा था कि कब कुछ अच्छा हो और वह हिंदुस्तान में निवेश करे. पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियां देखकर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए.

मंदी के दरवाजे पर खड़ा भारत

हम मंदी की कगार पर है. एक ख़तरनाक ख़बर यह है कि मुद्रा अवस्फीति (डिफ्लेशन) तीन फ़ीसद तक आ चुकी है. यह अंदाज़ा सरकार ने भी लगाया था और उद्योग जगत ने भी. अर्थव्यवस्था में दो या तीन फ़ीसद मुद्रास्फीति (इंफ्लेशन) सहायक होती है, लेकिन तीन फ़ीसद मुद्रा अवस्फीति! यह तो ऐसा लगता है, जैसे हम मंदी को आमंत्रित कर रहे हैं या फिर मंदी की कगार पर खड़े हैं. यह आंकड़ा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स का है. इसका मतलब है कि हम मंदी की कगार पर बैठे हैं. जब अर्थव्यवस्था दबाव में हो, तब आम तौर पर लोगों की मदद की जाती है, उनकी जेब से पैसा नहीं निकाला जाता. भाजपा के दो बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि पहले जब सूखा पड़ता था, तब राजा अपने खजाने खोल देता था, पर मौजूदा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसका उल्टा कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग कम कर दी है. अपने बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों का शेयर बढ़ा दिया और तर्क दिया कि यह वित्त आयोग की रिपोर्ट है.

भाजपा के नेता इस पर टिप्पणी करते हैं कि आपका अपना बजट है, आपकी अपनी योजनाएं हैं, आप देश में चुनकर आए हैं, आपने आशाएं जगाई हैं और आप अपना ही बजट अगर काट देंगे, तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के मानस पर क्या असर होगा? भाजपा नेता कहते हैं कि आप वित्त आयोग की रिपोर्ट का बहाना लेते हैं. आप वित्त आयोग की रिपोर्ट न लेते या वित्त आयोग से कहते कि यह रिपोर्ट इस तरह बनाओ. ये सारे काम सरकारें अपनी योजनाओं के हिसाब से करती हैं, पर हमारी सरकार ने पुराने वित्त आयोग, जिसे कांग्रेस ने बनाया था, की अनुशंसा ज्यों का त्यों स्वीकार कर ली. इसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रबंधन की नाकामी की तरह देखते हैं. नरेंद्र मोदी सरकार का प्लस प्वॉइंट वह माहौल बनाना था कि देश में बड़ा निवेश आएगा, बड़े आर्थिक सुधार होंगे, बड़े बदलाव होंगे. इन तमाम क़दमों से वह माहौल ख़त्म हो गया या बहुत नीचे चला गया.

हक़ीकत यह है कि ऐसा फ़ैसला अरुण जेटली की राय से हुआ. भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि यह स्टाइल नरेंद्र मोदी की भी है. मजे की बात यह कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि अरुण जेटली कानाफूसी और छिपी राजनीति करने के माहिर हैं. अब मुझे इसमें इतना भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि वे सही बोल रहे होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हज़ारों फाइलें पड़ी हैं, उनके डिस्पोज होने या उनके ऊपर फ़ैसला लेने में न्यूनतम समय तीन से चार माह लग रहा है.

एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पार्टी के बड़े नेता महसूस कर रहे हैं, वह यह कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी ताकत पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था. प्रधानमंत्री बनने के डेढ़ साल पहले से नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे थे और पार्टी के नेता भी कर रहे थे. जब तक वह प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक यह पूरी तरह जारी था. प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी कम्युनिकेशन या सरकार का जनता से संवाद करने का ज़िम्मा बौने लोगों के हाथों में आ गया. जिन साधारण लोगों के हाथों में भारतीय जनता पार्टी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां-कार्रवाइयां जनता को बताने का ज़िम्मा आया, वे उसे कह नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, बल्कि उलझा ज़्यादा रहे हैं. इसलिए देश में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. क्या कहा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसे कौन कह रहा है. भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की जिस सबसे बड़ी ताकत की बात हम कर रहे हैं यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, उसी में पार्टी सबसे ज़्यादा पिट रही है या पिछड़ रही है. पार्टी के न वरिष्ठ नेता इसमें लगे हैं और न सरकार के वरिष्ठ मंत्री. जब मैंने एक मंत्री से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम पहले कर रहे थे, लेकिन तब न पार्टी अध्यक्ष ने तारीफ़ की और न प्रधानमंत्री ने और न हमसे बुलाकर कहा गया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अगर हमारे किसी साथी से कोई एक ग़लती हो जाए, तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं. इसलिए कैबिनेट के सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने जनता से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने का काम बंद कर दिया और यह रुख अपना लिया है कि जितना उनसे कहा जाएगा, उतना ही वे करेंगे. हर आदमी इस शक में पड़ गया कि वह जो बोलेगा या करेगा, पता नहीं, क्या अच्छा लगे और क्या बुरा. इसलिए उसने खुद को तटस्थ कर लिया.

फाइल लटकाने वाली कार्यशैली

सत्ता का एक उसूल है कि आप सत्ता को जितना अपनी मुट्ठी में रखेंगे, उतनी ही ग़लतियां करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने साथियों की सत्ता में भागीदारी रखेंगे, उतने ही मजबूत होंगे. इसी सिद्धांत के उलट मोदी सरकार काम कर रही है. ऐसा पार्टी के लोगों का साफ़-साफ़ कहना है. इतना ही नहीं, एडमिशन अथॉरिटी या एडमिशन कंट्रोल नामक चीज राजनीतिक लोगों के हाथों से ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने साफ़ कह दिया कि मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, सचिव उनसे सीधे बात कर सकते हैं. इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में हज़ारों फाइलें पड़ी हैं, जिन्हें वह देख नहीं पा रहा है. फाइलें लौटकर नहीं जा पा रही हैं और मंत्रालय में काम नहीं हो रहा है. डेड लॉक की स्थिति हो गई है. हक़ीकत यह है कि ऐसा फ़ैसला अरुण जेटली की राय से हुआ. भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि यह स्टाइल नरेंद्र मोदी की भी है. मजे की बात यह कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि अरुण जेटली कानाफूसी और छिपी राजनीति करने के माहिर हैं. अब मुझे इसमें इतना भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि वे सही बोल रहे होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हज़ारों फाइलें पड़ी हैं, उनके डिस्पोज होने या उनके ऊपर फ़ैसला लेने में न्यूनतम समय तीन से चार माह लग रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की अगर यह कार्य कुशलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सही कह रहे हैं कि इससे वह छवि तो ख़त्म हो रही है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एक दिन में ही फाइलें निपटा देते थे. वह दक्षता प्रधानमंत्री कार्यालय होने के नाते उनका कार्यालय क्यों नहीं दिखा पा रहा है? नरेंद्र मोदी की क्षमता, उनकी आर्थिक बुद्धिमता (इकोनॉमिक ब्रिलियंस) और उनका अग्रेशन, जिसे लेकर पार्टी में उनके प्रति आकर्षण था और जिसे जनता ने भी अपना आकर्षण मान लिया था, वह छाप प्रधानमंत्री की बहुत हद तक ख़त्म हो रही है.

इसका एक उदाहरण पार्टी के नेता स्वच्छ भारत अभियान का देते हैं. वे कहते हैं कि आपने अभियान शुरू कर दिया, लेकिन वह जनता तक कैसे जाए, इसकी कोई योजना नहीं बनी. अगर आप चाहते हैं कि देश स्वच्छ रहे, तो आप दिल्ली को साफ़ करके दिखा देते. यहां एलजी था, जो केंद्र सरकार के नीचे काम कर रहा था. यहां सफाई के लिए जो ज़िम्मेदार संस्थान हैं, उन्हें मजबूत करते, उनकी प्लानिंग करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज स्वच्छ भारत अभियान का सारे देश में गला घुट रहा है. इसका फ़ायदा सिर्फ़ टीवी चैनलों एवं अख़बारों को विज्ञापन के रूप में हुआ, जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

मोदी-जेटली की गहरी मित्रता का राज क्या है

मेरे इस सवाल पर कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी की इस गहरी मित्रता का क्या राज है? भारतीय जनता पार्टी के कम से कम तीन नेताओं ने हंसकर कहा, दिस इज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री (अनसुलझा रहस्य). जब मैंने पूछा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने दो दिनों में शपथ लेने से पहले, पूरे मंत्रिमंडल का खाका अगर अरुण जेटली ने बनाकर रखा, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उसे ध्यान से देखा नहीं? इन भाजपा नेताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी रहस्य का पता चल जाता, तो फिर क्या बात थी! पर इन नेताओं ने एक बात कही कि अरुण जेटली पार्टी के बहुत बुद्धिमान, समझदार, होशियार एसेट (संपत्ति) हैं, लेकिन वह अर्थशास्त्री नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश सुधारने वाला एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए, जो आने वाले वक्त की नज़ाकत भांप सके और देश को दुनिया के सामने खड़ा कर सके, न कि दुनिया के सामने देश की कमजोरी जाहिर करे. इन नेताओं का कहना है कि डॉलर 65 रुपये पार कर 66 को छूने वाला है और कहीं यह 67-68 रुपये तक पहुंच गया, तो देश की अर्थव्यवस्था से न केवल देश का, बल्कि सारी दुनिया का विश्वास उठ जाएगा. पार्टी में यह कोई नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी इन सारी बातों को समझते नहीं हैं, पर पार्टी के लोगों को यह सवाल मथता है कि वह (मोदी) सुधार का कोई प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं? यह ऐसा सवाल है, जिसका जवाब खुद प्रधानमंत्री दे सकते हैं या फिर ईश्वर दे सकता है.

अब वरिष्ठ नेताओं की आशा सिर्फ़ कृष्ण गोपाल शर्मा हैं

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों निराशा की तरफ़ जा रहे हैं. उन्हें लगता है कि जिस पार्टी की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के आधार पर हुई और जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आकार दिया, वह पार्टी अब किसी और रास्ते पर चल पड़ी है. भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न संपर्क है, न संवाद है. छोटे नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वे संपर्क और संवाद कर सकें. इसलिए नरेंद्र मोदी चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, जिनके आसपास कोई नहीं जा सकता. सिर्फ़ दो व्यक्ति उनके आसपास जा रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की आशा श्री कृष्ण गोपाल जी हैं. वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देश के उत्तर-पूर्व में देखते रहे और उनका देश की राजनीति से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा. उन्हें सुरेश सोनी की जगह भारतीय जनता पार्टी में संघ का कार्यपालक बनाकर लाया गया है और मजे की बात यह है कि देश को अभी तक नहीं पता कि सुरेश सोनी

ने एक साल की छुट्टी ली है. इस दौरान वह अपना इलाज कराएंगे, अध्ययन करेंगे. पूरे मीडिया से यह ख़बर गायब हो गई है कि सुरेश सोनी एक साल की छुट्टी पर हैं और अब संघ की तरफ़ से भारतीय जनता पार्टी को संदेश-सलाह देने और पार्टी के समाचार संघ तक पहुंचाने का काम कृष्ण गोपाल जी को सौंपा गया है. कृष्ण गोपाल जी का भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा. इसके बावजूद वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आशा का केंद्र बन गए हैं. मैं आख़िर में एक बात कहना चाहता हूं. भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुझे अरुण जेटली के ख़िलाफ़ बोलता नहीं दिखाई दिया. सबको इस बात का एहसास है कि अरुण जेटली में कार्यकुशलता है, उनमें बोलने और तर्कों को विश्लेषित करने की शक्ति है और वह कांग्रेस का अच्छी तरह मुक़ाबला कर सकते हैं. लेकिन, उन्हें अरुण जेटली की कार्यशैली पर अवश्य ऐतराज है. अरुण जेटली समझदार हैं. हो सकता है, उन्हें पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं की जानकारी न मिलती हो, क्योंकि वह भी जी-हुजूरी वाले लोगों से घिरे हुए हैं. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी कुछ चीजें सुधार ले, तो शायद वह अपने सांसदों को उत्साहित कर पाएगी और सरकार के साथ उसका संबंध भी सही रह पाएगा. पर इस सबके एकमात्र नियंता प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी हैं. बिगाड़ना भी उनके हाथ में है और बनाना भी उनके हाथ में है. ■

मजे की बात यह है कि देश को अभी तक नहीं पता कि सुरेश सोनी ने एक साल की छुट्टी ली है. इस दौरान वह अपना इलाज कराएंगे, अध्ययन करेंगे. पूरे मीडिया से यह ख़बर गायब हो गई है कि सुरेश सोनी एक साल की छुट्टी पर हैं और अब संघ की तरफ़ से भारतीय जनता पार्टी को संदेश-सलाह देने और पार्टी के समाचार संघ तक पहुंचाने का काम कृष्ण गोपाल जी को सौंपा गया है. कृष्ण गोपाल जी का भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा. इसके बावजूद वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आशा का केंद्र बन गए हैं.

editor@chauthiduniya.com

कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि वह टीवी औ अख़बारों के माध्यम से प्रभावी रूप से जनता को बताए कि आधार काई बनवाना अनिवार्य नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार काई ज़रूरी नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आधार काई का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस के मामले के अलावा कहीं भी अनिवार्य नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार योजना के तहत लोगों से ली गई जानकारियों का इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन जानकारियों का इस्तेमाल उसके आदेशानुसार आपराधिक मामलों की जांच में किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट को सरकार भ्रमित कर रही है

चौथी दुनिया देश का पहला और अकेला अख़बार है, जो आधार कार्ड के ख़तरों से देश को लगातार आगाह करता रहा. आधार कार्ड एक ख़तरनाक कार्ड है, क्योंकि इसमें जनता की निजी जानकारियां निजी और विदेशी कंपनियों के साथ साझा करने का प्रावधान है. सरकार ने इस योजना में ऐसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिनके रिश्ते विदेशी खुफिया एजेंसियों से हैं. आधार कार्ड के ग़लत इस्तेमाल का ख़तरा हमेशा मंडराता रहेगा. चौथी दुनिया ने आधार कार्ड के ख़तरों के बारे में कई रिपोर्ट्स प्रकाशित कीं. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां आधार कार्ड की वैधता पर सुनवाई चल रही है. 11 अगस्त, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कुछ निर्देश दिए. यह समझना ज़रूरी है कि वे निर्देश क्या हैं और उनके मायने क्या हैं?

मनीष कुमार

11 अगस्त, 2015 को आधार कार्ड मामले की सुनवाई के दौरान देशवासियों को एक नई बात पता चली. वह यह कि देश की जनता को निजता का अधिकार ही नहीं है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है, क्योंकि संविधान के तीसरे खंड में इसकी अलग से व्याख्या नहीं की गई है. निजता के अधिकार का मामला आधार कार्ड के ख़िलाफ़ दायर याचिका की वजह से सामने आया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को लगता है कि आधार कार्ड की पूरी प्रक्रिया निजता के अधिकारों का अतिक्रमण है. याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार की दलील देकर आधार कार्ड की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने केंद्र की याचिका वृहद संविधान पीठ को सौंप दी है, जहां यह फ़ैसला होना है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं? इसके बाद ही यह फ़ैसला होगा कि आधार कार्ड वैध है या नहीं?

सरकार की तरफ़ से कहा गया कि कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर जितने भी निर्देश दिए हैं, उनमें से किसी में यह नहीं कहा गया कि सरकार को इस योजना को फिलहाल रोक देना चाहिए. लेकिन, सरकार से यह तो पूछा जाना चाहिए कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद आधार कार्ड को क्यों हर जगह अनिवार्य बताया गया? कई राज्यों में इस शिकायत को लेकर लोग कोर्ट गए. वहां भी यह फ़ैसला आया कि इस योजना को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. कई राज्य सरकारों को आधार कार्ड के मामले में पीछे हटना पड़ा. 11 अगस्त के अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़-साफ़ कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति पर आधार कार्ड बनवाने के लिए दबाव नहीं डाल सकती. मजेदार बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि देश भर में 90 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से आधार कार्ड बनवा लिया है. सरकार का यह बयान भ्रमित करने वाला है. मनमोहन सिंह की सरकार ने तो पहले इसे हर तरह की योजना से जोड़ दिया. अख़बारों और प्रचार के विभिन्न माध्यमों के ज़रिये लोगों को यह बताया गया कि बिना आधार कार्ड के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. स्कूल में एडमिशन से लेकर पेंशन तक को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया. यहां तक कि देश के सांसदों और पूर्व सांसदों से भी आधार कार्ड जमा कराने के लिए कहा जाने लगा. मोदी सरकार के दौरान तो विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वालों की उपस्थिति (अटेंडेंस) भी आधार से जोड़े जाने की मुहिम शुरू की गई. रेल टिकटों का रिजर्वेशन हो या फिर मनरेगा के तहत मिलने वाला काम, सब कुछ आधार कार्ड से जोड़ दिया गया. जब लोगों को लगा कि आधार कार्ड के बिना अब गुज़ारा मुश्किल है, तो उन्होंने उसे बनवाना शुरू कर दिया. यूपीए और एनडीए की सरकारों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि लोगों को मजबूरन आधार कार्ड बनवाना पड़ा. और, अब सरकार की तरफ़ से कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि लोगों ने स्वेच्छा से कार्ड बनवाया है. कोर्ट में इस बात पर ज़रूर बहस होनी चाहिए कि कोर्ट के लगातार मना करने के बावजूद आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं से क्यों जोड़ा गया?

कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि वह टीवी और अख़बारों के माध्यम से प्रभावी रूप से जनता को बताए कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस के मामले के अलावा कहीं भी अनिवार्य नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार योजना के तहत लोगों से ली गई जानकारियों का इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन जानकारियों का इस्तेमाल उसके आदेशानुसार आपराधिक मामलों की जांच में किया जा सकता है.

हैरानी तो इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट चार बार यह निर्देश दे चुका है कि आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं में अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना खुलेआम हो रही है. होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करने वाले को सजा मिलती, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. 11 अगस्त के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक

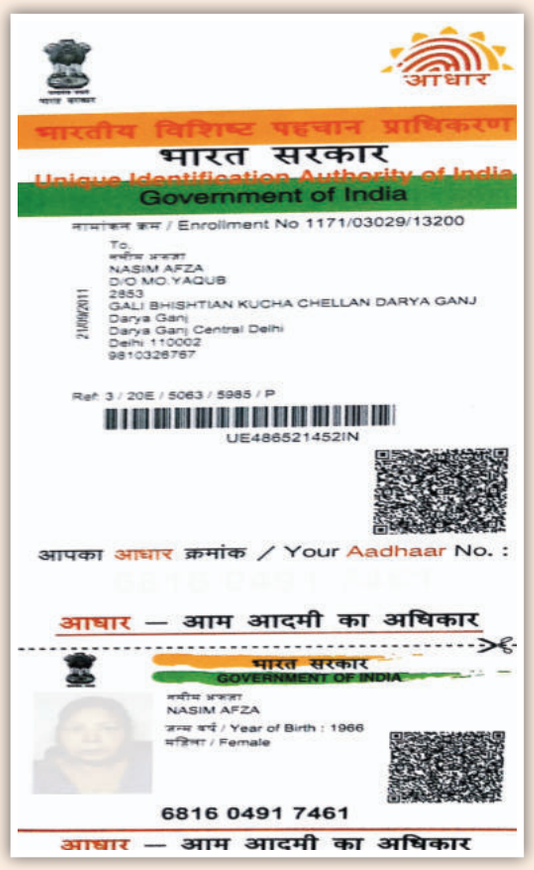

तरफ़ जहां अपने पुराने निर्देश को दोहराया, वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस के मामले में इसके इस्तेमाल की छूट दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 23 सितंबर, 2013 को यह निर्देश दिया था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इस निर्देश की अवहेलना करते हुए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को चुनाव से जोड़ना शुरू कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना सिर्फ़ चुनाव आयोग ने नहीं की, बल्कि केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों पर भी आधार कार्ड बनवाने का दबाव डाला जाने लगा. रक्षा मंत्रालय से जुड़े संस्थानों को भी आधार से जोड़ने की शुरुआत हो गई है. रेल मंत्रालय टिकट आरक्षण (रिजर्वेशन) को आधार से जोड़ने का काम कर चुका है. स्कूलों में प्रवेश (एडमिशन) के लिए आधार कार्ड, रसोई गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड, पेंशन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड, बैंक एकाउंट के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड यानी हर जगह आधार कार्ड धड़ल्ले से लागू किया गया. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शादी के पंजीकरण के लिए भी आधार कार्ड की मांग कर दी. बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जन्म के तुरंत बाद यानी उसी वक्त उनके बायोमीट्रिक डाटा इकट्ठा कर लिए जाएंगे और आधार नंबर दे दिया जाएगा

आधार से जुड़े पांच सवाल

- आधार योजना को लेकर एक बिल संसद में लंबित है. तो फिर वैधता मिलने से पहले ही इसे क्यों लागू किया गया?
- क्या आधार कार्ड के तहत लिए गए देशवासियों के पर्सनल सेंसिटिव बायोमीट्रिक डाटा विदेश भेजे जा रहे हैं या नहीं?
- आधार योजना का काम सरकारी एजेंसियों के बजाय विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों है?
- आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण-पत्र नहीं है, आख़िर क्यों?
- कोर्ट में इन बिंदुओं पर बहस क्यों नहीं हो रही है?

और उसी को जन्म प्रमाण-पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) मान लिया जाएगा. मतलब यह कि सरकार पिछले दरवाजे से आधार को लागू कर रही है. मजेदार बात यह है कि जब भी कोर्ट में सरकार से इस बारे में पूछा जाता है, तो सरकार की तरफ़ से यही कहा जाता है कि यह अनिवार्य नहीं है. जब सरकार यह दलील देने लगे कि देश के 90 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से आधार कार्ड बनवाए, तो फिर कोर्ट और याचिकाकर्ता भला क्या कर सकते हैं? अब यह मामला अनिवार्य होने या न होने का नहीं है.

दरअसल, आधार कार्ड का मामला अब उलझ-सा गया है. ऐसा लगता है कि आधार कार्ड के ज़रिये निजता के अधिकार का हनन और आधार कार्ड की अनिवार्यता ही मूल प्रश्न बनकर रह गए हैं. संविधान पीठ द्वारा अगर यह फ़ैसला हो जाता है कि आधार कार्ड से निजता का हनन नहीं होता और इस कार्ड का इस्तेमाल सरकार जनहित में और ग़रीबों की मदद के लिए करेगी, तो फिर सरकार आधार कार्ड लागू भी करेगी और अनिवार्य भी बना देगी. जबकि मूल प्रश्न कुछ और ही है. निजता का मामला तो बाद में आता है. पहले तो यह पूछा जाना चाहिए कि सरकार को किस क़ानून के तहत यह अधिकार है कि वह आधार कार्ड बनाने के लिए जनता की बायोमीट्रिक जानकारियां ले? दूसरा सवाल यह कि आधार योजना को लेकर एक बिल संसद में लंबित है, लेकिन यूपीए और एनडीए की सरकारों ने आधार को वैधता प्रदान करने वाला क़ानून बनने से पहले ही इस योजना को क्यों लागू कर दिया? मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013 और 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के नागरिकों पर आधार कार्ड जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता. फिर भी सरकारी एजेंसियां इसे अनिवार्य क्यों बना रही हैं? आधार कार्ड को लेकर जो सबसे बड़ा ख़तरा है, वह यह है कि देशवासियों के पर्सनल सेंसिटिव बायोमीट्रिक डाटा विदेश भेजे जा रहे हैं या नहीं? सवाल यह भी उठता है कि कोर्ट में इन बिंदुओं पर बहस क्यों नहीं हो रही है?

कोर्ट के माध्यम से देशवासियों को कम से कम यह तो ज़रूर पता चलना चाहिए कि क्या आधार से जुड़े डाटा के इस्तेमाल और उनके ऑपरेशन का अधिकार विदेशी निजी कंपनियों को दिया गया है? उन कंपनियों का इतिहास क्या है? क्या उन कंपनियों के रिश्ते विदेशी खुफिया एजेंसियों से हैं या नहीं? सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि आधार योजना का काम सरकारी एजेंसियों के बजाय विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों है? आधार के नागरिक इस्तेमाल को सैन्य इस्तेमाल से क्यों जोड़ दिया गया? यदि इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोर्ट का ध्यान नहीं जाता है, तो फिर अनर्थ हो जाएगा. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधार कार्ड एक ऐसा ख़तरनाक जरिया है, जिसमें पुलिस स्टेट और निगरानी राज्य को जन्म देने की सामर्थ्य और संभावनाएं हैं. मनमोहन सिंह सरकार हो या मोदी सरकार, हमने शुरू से ही आधार कार्ड को ख़तरनाक बताया, सरकार और आम लोगों को आगाह किया तथा आगे भी करते रहेंगे. मीडिया की सीमा यहीं तक है. हम ख़तरे के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उससे निपटने का काम सरकार और नागरिकों का है. ■

manishbph244@gmail.com

शहजाद का कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक भोजपुरी की भूमिका के अफसाने इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. सरकार जिन तकनीकी बाधाओं की बात कर रही है, वह बहानेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है. आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इसे मुद्दा बनाते हुए प्रचार करेंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत धरना दिया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

केंद्र को भुगतना पड़ सकता है वादाख़िलाफ़ी का खामियाज़ा

भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के जवाब में सरकार का बयान आया है कि इसमें कुछ तकनीकी बाधा है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर इस बाधा को दूर कौन करेगा? क्या पूर्व में संशोधन विधेयक लाकर अन्य भाषाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया? केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या की भावना के अनादर में विपक्ष की भूमिका भी कम नहीं रही. लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत दबाव समूह होता है, लेकिन भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि जन-सरोकारों और जन-भावनाओं की पैरवी की दिशा में विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा.

भोजपुरी भाषा एवं साहित्य के कई सृजनधर्मियों की इस धरती ने हर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चंपारण में लगातार सक्रियता बनी हुई है. भोजपुरी, उर्दू एवं हिंदी के रचनाकार और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ता गुलरेज शहजाद सत्याग्रह यात्रा नामक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. आंदोलन को गति देने के लिए वह नवका पानी नामक एक भोजपुरी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू करेंगे, जिसका प्रवेशांक सितंबर में संभावित है.

मोतिहारी

राकेश कुमार

देश भर में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही है. विभिन्न भोजपुरी संस्थाएं इस मांग को लेकर देश भर में आंदोलन करके केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी पर आक्रोश व्यक्त कर रही हैं. लोकसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने का वादा किया गया था. उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई मंचों से जनसमूह का अभिवादन भोजपुरी में किया था, लेकिन सरकार बन जाने के बाद 20 करोड़ से अधिक भोजपुरी भाषियों की इस भावना को नज़रअंदाज़ कर दिया गया. भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के जवाब में सरकार का बयान आया है कि इसमें कुछ तकनीकी बाधा है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर इस बाधा को दूर कौन करेगा? क्या पूर्व में संशोधन विधेयक लाकर अन्य भाषाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया? केंद्र सरकार की वादाख़िलाफ़ी अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या की भावना के अनादर में विपक्ष की भूमिका भी कम नहीं रही. लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत दबाव समूह होता है, लेकिन भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि जन-सरोकारों और जन-भावनाओं की पैरवी की दिशा में विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा.

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की धारा 344 (1) के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें असमिया, बंगला, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, बोडो, संथाली एवं मैथिली शामिल हैं. शुरू में इसमें केवल 14 भाषाएं थीं. 1967 में 21वें संशोधन के ज़रिये कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी, 2003 में 92वें संशोधन के ज़रिये डोगरी, बोडो, संथाली एवं मैथिली को शामिल किया गया. आठवीं अनुसूची में शामिल अधिकतर भाषाएं देवनागरी लिपि में मान्य हैं, लेकिन भोजपुरी जिसने अपनी कैथी लिपि त्याग दी, से यह सवाल क्यों?

भोजपुरी का अपना व्याकरण भी है, जो हिंदी के पहले से लिखा जाता रहा है. संस्कृत एवं तमिल को छोड़कर प्राय: सभी भारतीय भाषाओं का विकास दसवीं शताब्दी के बाद हुआ, जबकि भोजपुरी हिंदी से अधिक पुरानी भाषा है. फिर सवाल उठता है कि भोजपुरी हिंदी की बोली कैसे हो गई? अगर उक्त तकनीकी बाधाएं हैं, तो पूर्व में अन्य भाषाओं को दी जाने वाली संवैधानिक मान्यता का आधार क्या था? बिहार विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जयकांत सिंह जय कहते हैं कि देश की 0.1 प्रतिशत जनसंख्या की भाषा बोडो, छोटे क्षेत्रों की भाषा कश्मीरी, डोगरी एवं संथाली है. उन्हें मान्यता कैसे मिली? प्रवासी भाषा सिंधी एवं नेपाली को किस आधार पर मान्यता मिली. डॉ. जय के अनुसार, एक सुनियोजित साजिश के तहत कॉरपोरेट द्वारा अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी को कमज़ोर किया जा रहा है. हिंदी की मजबूती के लिए भोजपुरी का सशक्त होना और उसे मान्यता मिलना बहुत आवश्यक है. चंपारण की भोजपुरिया धरती का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है. उसे कभी उत्तर बिहार की साहित्यिक-सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव हासिल था. भोजपुरी भाषा एवं साहित्य के कई सृजनधर्मियों की इस धरती ने हर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चंपारण में लगातार सक्रियता बनी हुई है. भोजपुरी, उर्दू एवं हिंदी के रचनाकार और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ता गुलरेज शहजाद सत्याग्रह यात्रा नामक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. आंदोलन को गति देने के लिए वह नवका पानी नामक एक भोजपुरी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू करेंगे, जिसका प्रवेशांक सितंबर में संभावित है. इसके अलावा आगामी दिसंबर में तीन दिवसीय भोजपुरी साहित्य मेले की योजना है, जिसमें देश-विदेश के भोजपुरी भाषी प्रतिनिधि एवं रचनाकार हिस्सा लेंगे. शहजाद का कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक भोजपुरी की भूमिका के अफसाने इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. सरकार जिन तकनीकी बाधाओं की बात कर रही है, वह बहानेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है. आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इसे मुद्दा बनाते हुए प्रचार करेंगे.

बीते छह अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत धरना दिया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. भोजपुरी भाषा मान्यता आंदोलन, दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक संतोष पटेल के संयोजकत्व में आयोजित इस धरने में जेपी विश्वविद्यालय के डीन डॉ. वीरेंद्र नारायण यादव, डॉ. जयकांत सिंह जय, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री गुरुचरण सिंह, जनार्दन सिंह, पंकज कुमार, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष अजीत दुबे, महुआ प्लस क्रिएटिव कंसल्टेंट मनोज भावुक, भोजपुरी जन-जागरण अभियान के महामंत्री अभिषेक भोजपुरिया, ऋतुराज, राजेश भोजपुरिया, राजीव उपाध्याय, भोजपुरी संसार के मनोज श्रीवास्तव, धनंजय कुमार सिंह एवं कुलदीप श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की. इस मौक़े पर भोजपुरी जन-जागरण अभियान की ओर से प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को एक छह सूत्रीय ज्ञापन भी भेजा गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिला वोट बैंक

बिहार चुनाव विशेष

नीतीश ने की वादों की बौछार

विभिन्न शहरों में 150 वर्किंग वीमेंस हॉस्टल खोले जाएंगे

महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 फ़ीसद और बिहार पुलिस में 35 फ़ीसद आरक्षण

कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को किया स्थायी, दिया वेतनमान

एक कार्यक्रम के दौरान जब कुछ महिलाओं ने शराब के ठेकों के लाइसेंस देने का विरोध करते हुए शराब बंदी की मांग रखी, तो नीतीश ने झट से ऐलान कर दिया कि वह अगली बार सत्ता में आने पर शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा देंगे. उन्होंने और भी कई वादे किए हैं, जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न शहरों में 150 हॉस्टल खोले जाएंगे, जहां सुरक्षा सहित सारी सुविधाएं होंगी.

आदित्य नारायण पांडेय

राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के रूप में अपना एक और वोट बैंक ढूंढ लिया है और उन्हें अपनी ओर लाने का कोई भी मौक़ा वह हाथ से निकलने नहीं दे रहे हैं. ग़ौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के एक बड़े तबके ने नीतीश का साथ दिया था. लेकिन, हर एक किलोमीटर पर शराब के ठेके खुल जाने से महिलाएं इन दिनों उनसे नाराज़ भी हैं. नीतीश भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वह कई नए चुनावी ऐलान कर रहे हैं. हाल में एक कार्यक्रम के दौरान जब कुछ महिलाओं ने शराब के ठेकों के लाइसेंस देने का विरोध करते हुए शराब बंदी की मांग रखी, तो नीतीश ने झट से ऐलान कर दिया कि वह अगली बार सत्ता में आने पर शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा देंगे. उन्होंने और भी कई वादे किए हैं, जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न शहरों में 150 हॉस्टल खोले जाएंगे, जहां सुरक्षा सहित सारी सुविधाएं होंगी. पहले चरण में ऐसे छह हॉस्टल पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर में खोले जाएंगे.

नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. इसके तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. हाल में नीतीश कुमार ने सभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को स्थायी कर उनके वेतन में 20 फ़ीसद का इजाफा करने का ऐलान किया था. इनमें आधी संख्या महिलाओं की है. छात्राओं के लिए साइकिल, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, बारहवीं तक मुफ्त पढ़ाई और कैश अवॉर्ड जैसी योजनाएं पहले से चलाई जा रही हैं. बिहार पंचायती राज एक्ट-2006 के तहत महिलाओं को 50 फ़ीसद आरक्षण दिया गया है. बिहार पुलिस में महिलाओं को 35 फ़ीसद आरक्षण देने के मामले में बिहार पहला राज्य बना. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अलावा स्कूलों में शौचालय बनाने पर नीतीश सरकार का खासा ज़ोर रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम क़दमों के बाद विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाओं का कितना साथ मिलता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उलिबुरु खदान और हिसिबुरु रेलवे साइडिंग तक पहुंचने के लिए बेल्कुंडी संरक्षित वन के बीच से ओएमडीसी की लौह अयस्क खदान तक सड़क मार्ग का निर्माण भी गुप्ता परिवार द्वारा ही कराया गया था. पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण तक़रीबन दो सौ साल पुराने पेड़ों को अवैध रूप से काटकर कराया गया. हालांकि, केंद्र सरकार की इकाई होने के नाते ओएमडीसी ने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन क्योंझर के तत्कालीन ज़िला वन अधिकारी प्रदीप राज करत ने यह आपत्ति ख़ारिज कर दी थी. राज्य सतर्कता विभाग ने करत को सिर्फ़ उलिबुरु माइनिंग मामले में ही आरोपी बनाया.

ओडिशा

हिसिबुरु से होकर जाता है उलिबुरु माइनिंग घोटाले का रास्ता

शाह आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा में वर्ष 2003 और 2009 के बीच 2000 करोड़ रुपये के लौह अयस्क का घोटाला सामने आया था. यह खदान क्योंझर ज़िले के जोड़ा माइनिंग सर्किल के तहत आती थी. लीज धारक बीके मोहंती ने दीपक गुप्ता (दीपक स्टील पॉवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक) को उलिबुरु गांव स्थित लौह अयस्क खदान की पॉवर ऑफ अटॉर्नी ग़ैर-क़ानूनी तौर पर दी थी. यह खदान बीके मोहंती को 1983 से 2003 तक के लिए लीज पर दी गई थी. इस दौरान खदान में कोई काम नहीं हुआ. वर्ष 2003 में लीज की अवधि समाप्त होने पर दीपक गुप्ता ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और धोखाधड़ी व सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के ज़रिये 2004 से 2009 के बीच लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का खनन किया. यही नहीं, उलिबुरु के रिजर्व फॉरेस्ट पिलर को भी पीछे खिसका दिया गया. इससे देश को लगभग 8,39, 67,11,748 रुपये (सरकारी अनुमान) का नुक़सान हुआ.

बिभूति पति

ओडिशा सरकार ने लंबे समय तक उलिबुरु खनन घोटाले को छिपाकर रखा, लेकिन बाद में मीडिया के दबाव में इसकी जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गई. यहां तक कि ग़ैर-क़ानूनी माइनिंग की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह आयोग को भी इस बड़े घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अंधेरे में रखा गया. अंततः राज्य सतर्कता विभाग ने दिसंबर, 2013 में चार्जशीट दाखिल की. फिर बाद में जून, 2014 में क्योंझर सतर्कता अदालत में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन इसके बावजूद सतर्कता विभाग की चार्जशीट अभी अधूरी है. तो क्या विभाग ने अभी भी बहुत सारे तथ्यों को छिपा लिया है? उलिबुरु खदान से पांच किलोमीटर दूर स्थित हिसिबुरु रेलवे साइडिंग के ज़रिये लौह अयस्क की एक बड़ी मात्रा दूसरे राज्यों में भेजी जा चुकी है. हिसिबुरु रेलवे साइडिंग इस ग़ैर-क़ानूनी काम के लिए दरवाज़े की भूमिका निभा रहा है.

चौथी दुनिया की जांच से पता चला कि गुप्ता परिवार ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी होशियारी के साथ ग़ैर-क़ानूनी खनन से हासिल लौह अयस्क की दूसरे राज्यों में आपूर्ति की. दीपक गुप्ता के पिता एवं दीपक स्टील पॉवर लिमिटेड (डीएसपीएल) के निदेशक हरिचरण दो स्पंज आयरन इकाइयां चलाते थे. पहली इकाई उलिबुरु में थी, जो ग़ैर-क़ानूनी तौर पर चल रही उलिबुरु खदान से चार किलोमीटर दूर स्थित थी और दूसरी इकाई आरपी साव द्वारा आवंटित जोड़ा माइनिंग सर्किल में थी या ग़ैर-क़ानूनी तौर पर चल रही थी. दक्षिण-पूर्व रेलवे ने डीएसपीएल को निजी साइडिंग बनाने की अनुमति दे दी. यह अनुमति बडजमडा (झारखंड) के स्टेशन मास्टर ने (वाइड्स-चीफ कॉमर्शियल मैनेजर (एफएस एंड एफएम) स्पेशल सर्कुलर लेटर संख्या-आरजी-46/4353, दिनांक 02 मार्च, 2007) द्वारा दी. उसके बाद अक्टूबर में हरिचरण ने फॉर्म ए भरकर हिसिबुरु रेलवे साइडिंग पर व्यापार तथा स्टोरेज का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या- 60वीए-542/2008) किया, लेकिन इसमें प्लॉट नंबर ज़ाहिर नहीं किया गया. इसकी अनुमति पूर्ण पात्रा द्वारा दी गई थी. पात्रा उस समय जोड़ा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस (डीडीएम) थे. उन्होंने हरिचरण को दो वर्षों के लिए स्टोरिंग लाइसेंस (संख्या-68867) प्रदान कर दिया, ताकि लौह अयस्क स्टोर किया जा सके और दूसरे राज्यों में रेलवे के ज़रिये डिस्पैच किया जा सके. डीएसपीएल अपने कार्यों का संचालन ओडिशा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना कर रही थी. केवल 11 नवंबर, 2009 को राज्य प्रदूषण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर (क्योंझर) ने पत्र संख्या-1477/10/12/2009 के तहत इस शर्त पर अनुमति दी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानक पूरे किए जाएंगे, लेकिन शर्तों का अनुपालन न होने के बावजूद एक बार फिर राज्य प्रदूषण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर ने 24 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक काम करने की अनुमति दे दी. उसके बाद काम जारी रखने के लिए प्रदूषण बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई.

डीएसपीएल ने अक्टूबर 2008 का अपना पहला मासिक रिटर्न (फॉर्म-इ) जोड़ा सर्किल में दाखिल किया था. यह सब, जिसमें लेन-देन के बाद 1,43,959 मीट्रिक टन लौह अयस्क का शेष दिखाया गया था, कैसे हुआ? इसका कोई जवाब डीडीएम जोड़ा के पास नहीं है. उसके बाद कंपनी ने अक्टूबर 2008 से जून 2009 तक के मासिक रिटर्न्स दाखिल किए, जिनमें यह दिखाया गया था कि उसने झारखंड से 4,62,967 मीट्रिक टन लौह अयस्क खरीदा और उसे डिस्पैच किया. डीडीएम जोड़ा ने 2014 में इस लेन-देन के सत्यापन के लिए रेलवे को कई पत्र लिखे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

इसके अलावा डीएसपीएल ने हिसिबुरु रेलवे साइडिंग पर ग़ैर-क़ानूनी तौर पर स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित किया है. अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009 तक के जोड़ा सर्किल ऑफिस में दाखिल किए गए अपने मासिक रिटर्न्स में डीएसपीएल ने बताया कि उसने स्क्रीन करके रेलवे रेक के ज़रिये 57,298 मीट्रिक टन लौह अयस्क बाहर रवाना किया है. ख्याल रहे कि कंपनी को स्टोरिंग के लिए लाइसेंस दिया गया था, न कि प्रोसेसिंग के लिए. डीडीएम जोड़ा ने इस तरह के डिस्पैच के लिए परमिट जारी नहीं किए थे. यह लौह अयस्क माफिया द्वारा जंगल में किए जा रहे खनन से ग़ैर-क़ानूनी तौर पर हासिल किया गया था. अगर इस लौह अयस्क की क़ीमत ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी) की न्यूनतम दर (5,000 रुपये प्रति टन) के हिसाब से लगाई जाए, तो सरकार को कम से कम 14 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है.

14 अक्टूबर, 2009 को डीएसपीएल के हिसिबुरु रेलवे साइडिंग पर जोड़ा के माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग ऑफिस, क्योंझर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं व्यवसायिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया, जिसमें तत्कालीन माइनिंग ऑफिस (जोड़ा) ने 41,000 टन लौह अयस्क तत्काल रूप से ज़ब्त किया था, जिसने डीएसपीएल में चल रही अनियमितता बेनकाब की थी. इसके बाद जोड़ा के डीडीएम पूर्ण पात्रा ने डीएसपीएल का लाइसेंस (संख्या-68867) निलंबित करते हुए पत्र संख्या 49133, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 के ज़रिये उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया. डीएसपीएल ने इस नोटिस का जवाब 29 अक्टूबर, 2009 को दिया. जिस पर जांच के बाद कार्रवाई करते हुए डीडीएम ने 21 नवंबर को कंपनी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. निरीक्षण के समय पाए गए लौह अयस्क की क़ीमत वसूल करने के लिए माइंस के निदेशक की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली गई. जोड़ा सर्किल ऑफिस के दैनिक राजस्व वसूली रजिस्टर (18 माइंस रजिस्टर) और माइंस निदेशक के पास मौजूद 2008 से 2013 तक के सारांश (एब्सट्रैक्ट) से पता चलता है कि डीडीएम जोड़ा ने केवल 2013 में जुर्माने की राशि रिकवर की. जोड़ा के डीडीएम पूर्ण पात्रा नवंबर 2009 से लंबी छुट्टी पर चले गए थे. कुछ दिनों के लिए उनका कार्यभार तत्कालीन माइनिंग ऑफिसर ने संभाला था. उसके बाद उमेश चंद्र जेना ने डीडीएम की कुर्सी संभाली.

27 अक्टूबर, 2009 से डीएसपीएल का लाइसेंस निलंबित था, लेकिन इस बीच डीडीएम जोड़ा की अनुमति से खनन का काम जारी रहा. 26 जुलाई, 2010 को एक बार फिर डीएसपीएल ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह थी कि नए डीडीएम जेना ने उसके लाइसेंस का नवीनीकरण पुरानी फाइल (60 वीए-542/2008) के बजाय नई फाइल खोलकर किया, जिसका नंबर था 60 वीए-579/2010. यह कार्रवाई केवल डीएसपीएल की पुरानी फाइल की अवैधता छिपाने के लिए की गई थी. जोड़ा माइनिंग सर्किल का पूरा ऑफिस हरिचरण के साथ सहयोग कर रहा था. डीडीएम जेना ने डीएसपीएल के स्टोरिंग लाइसेंस का नवीनीकरण 27 अक्टूबर, 2010 से दो वर्षों के लिए कर दिया. उन्होंने न तो लाइसेंस का निलंबन रद्द किया और न जुर्माने का हिसाब-किताब किया. यह कैसे मुमकिन हो सका? अवैध नवीनीकरण और निलंबन की अवधि के दौरान डीएसपीएल ने 3,31,546 मीट्रिक टन कच्चा लोहा हासिल किया और 3,81,906 मीट्रिक टन वहां से बाहर रवाना किया. डीडीएम जेना ने डीएसपीएल को निलंबन की अवधि में कुल 22 परमिट जारी किए. 27 अक्टूबर, 2010 के लाइसेंस नवीनीकरण के बाद भी उन्होंने कई परमिट जारी किए.

दीपक गुप्ता द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही उलिबुरु खदान का लाइसेंस तत्कालीन डीडीएम जोड़ा पूर्ण पात्रा ने निलंबित कर दिया था, लेकिन इस दौरान हरिचरण हिसिबुरु रेलवे साइडिंग का इस्तेमाल डीएसपीएल के नाम पर करते रहे. लिहाज़ा, बिना किसी आदेश के उलिबुरु खदान का अवैध लौह अयस्क हिसिबुरु रेलवे साइडिंग के माध्यम से बाहर जाता रहा. दिलचस्प बात यह है कि डीडीएम जेना ने इस गोरखधंधे में एक क़दम आगे जाते हुए डीएसपीएल को 889.624 टन कच्चा लोहा कंपनी के उलिबुरु प्लांट (जो उलिबुरु खदान के निलंबन की वजह से प्रभावित हो रहा था) तक पहुंचाने के लिए 23 जनवरी, 2010 को नया परमिट संख्या 1929 जारी कर दिया. उलिबुरु खदान और हिसिबुरु रेलवे साइडिंग तक पहुंचने के लिए बेल्कुंडी संरक्षित वन के बीच से ओएमडीसी की लौह अयस्क खदान तक सड़क मार्ग का निर्माण भी गुप्ता परिवार द्वारा ही कराया गया था. पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण तक़रीबन दो सौ साल पुराने पेड़ों को अवैध रूप से काटकर कराया गया. हालांकि, केंद्र सरकार की इकाई होने के नाते ओएमडीसी ने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन क्योंझर के तत्कालीन ज़िला वन अधिकारी प्रदीप राज करत ने यह आपत्ति ख़ारिज कर दी थी. राज्य सतर्कता विभाग ने करत को सिर्फ़ उलिबुरु माइनिंग मामले में ही आरोपी बनाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

सतर्कता विभाग की कोताही

सतर्कता विभाग ने 24 जून, 2014 को क्योंझर की सतर्कता अदालत में एक पूरक चार्जशीट (संख्या-06/2014) दाखिल की थी, जिसमें डॉक्यूमेंट रिकवरी प्वॉइंट नंबर 13 और 14 में दर्ज है कि करत की डायरी से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने जंगल के बीच से अवैध रूप से बनाई गई सड़क का दौरा उस समय किया था, जब उस रास्ते में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की ढुलाई हो रही थी. इससे ज़ाहिर होता है कि करत को अवैध रूप से चल रहे खनन की जानकारी थी. सतर्कता विभाग की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि मामले के मुख्य आरोपी दीपक गुप्ता ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि करत ने उसे उलिबुरु की अवैध खदान से बेल्कुंडी के संरक्षित वन के बीच से बनाए गए रास्ते से हिसिबुरु रेलवे साइडिंग तक लौह अयस्क ले जाने की इजाजत दी. उक्त तथ्यों के बावजूद सतर्कता विभाग ने कभी हिसिबुरु रेलवे साइडिंग की जांच नहीं की. आख़िरी बार खनन निदेशक ने राज्य सतर्कता दस्ते को जांच के लिए 2013 में भेजा था, लेकिन एक साल पहले आ चुकी जांच की यह गुप्त रिपोर्ट खनन निदेशक आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को नहीं भेज रहे हैं. इसके क्या कारण हैं, यह तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वह ग़ैर-ज़रूरी तौर पर डीडीएम जोड़ा की राय जानने के लिए यह रिपोर्ट भेजकर समय बर्बाद करने की नीति पर काम कर रहे हैं. डीडीएम सत्यानंद साहू इसमें उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं. राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह जांच आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में राज्य के प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) दस्ते की जांच रिपोर्ट की सराहना की है और सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, क्योंकि राज्य सरकार और अवैध खनन करने वालों के बीच साठगांठ है, जिससे देश और पर्यावरण को नुक़सान हो रहा है. ■

अधिकारियों के अजीबोग़रीब जवाब

तहकीकात के दौरान यह संवाददाता खनन निदेशक दीपक मोहंती से दो बार मिला, लेकिन उनका कहना था कि यह मामला बहुत पुराना है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं है. आप मुझे अपने सवाल लिखकर दे दीजिए, मैं कुछ दिनों के बाद जवाब दे दूंगा. लेकिन एक महीने से अधिक समय गुज़र जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया है. उसके बाद वन अधिकारी यूसी जेना से उनके समय में हुई धांधली के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से इंकार कर दिया (उनके इंकार का वीडियो भी मौजूद है). प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) जेडी शर्मा से जब पूछा गया कि डीएसपीएल द्वारा उलिबुरु लौह अयस्क खदान से लोहे की ढुलाई के लिए बेल्कुंडी संरक्षित वन के बीच से अवैध रूप से बनाई गई सड़क के बारे में क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ वन अधिकारी करत की नाक के नीचे यह सब हो रहा था? जेडी शर्मा ने जवाब दिया कि हमने कार्रवाई की है. अगर आपके पास कोई और मामला हो, तो लिखित में देने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है. चौथी दुनिया ने सतर्कता विभाग के जांच अधिकारी राधाकृष्णन (डीएसपी) से हिसिबुरु रेलवे साइडिंग की जांच के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी जवाब देने से इंकार कर दिया. हालांकि, टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हिसिबुरु की जांच नहीं की गई है, लेकिन उनकी चार्जशीट में यह ज़िक्र किया गया है कि हिसिबुरु से डीएसपीएल की प्रोसेसिंग इकाई तक लौह अयस्क की ढुलाई होती थी. इससे साफ़ हो जाता है कि राज्य सतर्कता विभाग अपनी तफ्तीश में नाकाम हो गया और उनसे पास चौथी दुनिया द्वारा पूछे गए सवालों (देखें बॉक्स) का जवाब नहीं है. सभी संबंधित विभागों के अधिकारी जानबूझ कर हिसिबुरु घोटाला दबाने की कोशिश कर रहे हैं. ■

माइनिंग निदेशक से चौथी दुनिया के सवाल, जिनका जवाब नहीं मिला

- 28 अक्टूबर, 2008 को डीडीएम जोड़ा पीसी पात्रा द्वारा डीएसपीएल को हिसिबुरु में निजी रेलवे साइडिंग बनाने की इजाज़त दी गई. डीएसपीएल के मासिक रिटर्न्स में बताया गया कि उसके पास 1,43,000 टन लौह अयस्क था. यह कैसे मुमकिन हो सका?
- आपके ज़िला स्तर के दस्ते ने डीएसपीएल के हिसिबुरु साइडिंग का निरीक्षण किया था, जिसमें उसने पाया कि डीएसपीएल के पास खनिज आदान-प्रदान करने के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं हैं. तत्कालीन डीडीएम पीसी पात्रा ने 27 अक्टूबर, 2010 को उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था, लेकिन उनके बाद आए डीडीएम यूसी जेना ने जुर्माने की राशि वसूले बिना ही लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया. ऐसा क्यों?
- डीएसपीएल ने लाइसेंस निलंबन के बाद अक्टूबर 2009 में अस्वीकृत जुर्माने की राशि डीडीएम जोड़ा के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई. वह ड्राफ्ट 2013 या 14 में भुनाया गया. ऐसा क्यों?
- डीएसपीएल को डीडीएम जोड़ा यूसी जेना ने निलंबन अवधि के दौरान भी खनिज के आदान-प्रदान की इजाजत दी. उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई?

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय एवं पीटीआई*

जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही गोलीबारी का विरोध कर रहे थे.

खाद्य पदार्थों की बढ़ती क़ीमतों के विरोध में दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री महंगाई रोक पाने में विफल रहे हैं.

राजनीतिक विरोधों से दूर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और जदयू अध्यक्ष शरद यादव कुछ इस अंदाज़ में मिले.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव एवं पार्टी के अन्य सांसदों ने जातिगत जनगणना को लेकर संसद में अपना विरोध दर्ज कराया. मुलायम सिंह ने केंद्र की एनडीए सरकार को चेतावनी दी कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, तो भविष्य में इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी जाएगी.

राष्ट्रीय अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हाल में हुए गुरुदासपुर आतंकी हमले के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब न कभी आतंकवाद के समक्ष झुका है, न झुकेगा.

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी पार्टी के 25 सांसदों के निष्कासन के विरुद्ध संसद भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया.

नई दिल्ली में किराया क़ानून को लेकर पगड़ी किरायेदार संगठन ने प्रदर्शन किया. संगठन की मांग है कि राज्य में अनियंत्रित किराये रोकने के लिए सरकार को तत्काल क़ानून लाना चाहिए.

जब नीरा से मेरी मुलाकात हुई...

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब रही है. जो मुझे जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि मैंने हमेशा महिलाओं के साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखी है. मैंने निमंत्रण स्वीकार किया. अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया. 20 लोगों की यह एक छोटी-सी पार्टी थी. बेहतरीन संगीत और नृत्य चल रहा था. मैंने देखा कि नीरा नृत्य की काफी शौकीन थी. मैंने एक कॉकटेल लिया और क़रीब एक घंटे तक उसे थामे रहा...

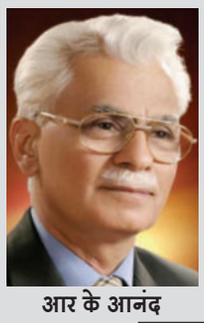

आर के आनंद

वर्ष 1996, गर्मी का मौसम. मेरे कार्यालय में एक आकर्षक महिला आती है. डिजाइनर कपड़े पहने और सलीके से चलती हुई वह महिला मुस्कुराते हुए मेरे कार्यालय में दाखिल होती है. मुझे याद है, उसने ओपियम परफ्यूम इस्तेमाल किया था. उसकी खुशबू काफी मुलायम होती है. उसका सलीका और पहनावा माहौल के अनुकूल था. उसके साथ मेरा एक दोस्त था. यह सिर्फ़ एक सोशल विजिट (सामाजिक मुलाकात) थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. हमने खुशनुमा माहौल में क़रीब आधे घंटे तक बातचीत की. कुछ समान दिलचस्पी की बातें, मुझे अच्छी लगीं. कुछ अन्य बातें भी हुईं, आर्थिक मसलों पर. उनमें मेरी दिलचस्पी थोड़ी कम थी और वे मेरे सिर के ऊपर से गुज़र रही थीं, लेकिन फिर भी मैं बोर नहीं हो रहा था.

उस मुलाकात को लेकर, जिसमें मेरा दोस्त भी शामिल था, मैं यही याद कर पाता हूं कि वह महिला अभी इंग्लैंड से लौटकर आई है, बेहतरीन ढंग से बातचीत कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी टॉपिक पर घंटों उलझाए रख सकती है. मैंने महसूस किया था कि वह भारत बिजनेस करने के लिए आई है, कोई छोटा-मोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस. उसने मुझे प्रभावित किया. उस वक्त नीरा राडिया सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया स्थित पूर्व पहलवान एवं फिल्म अभिनेता दारा सिंह के मकान में किराये पर रहती थी. उस मकान के ठीक बगल में चंद्रास्वामी का निवास था. हमारी मुलाकात के कुछ ही महीने बाद से हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा.

अचानक एक दिन उसने मुझे अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए आमंत्रित किया. मेरा दोस्त, जो नीरा को लेकर मेरे पास आया था, अक्सर उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें करता था. वह नीरा राडिया के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित नज़र आता था. वह मुझसे कहता था कि मुझे नीरा राडिया को अपना पारिवारिक मित्र बनाना चाहिए. मैं आदतन मजबूर हूं. मैंने हमेशा जनता के बीच काम किया है. हमेशा मेरे कामों की पब्लिक स्क्रूटनी हुई है. मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब रही है. जो मुझे जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि मैंने हमेशा महिलाओं के साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखी है. मैंने निमंत्रण स्वीकार किया. अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया. 20 लोगों की यह एक छोटी-सी पार्टी थी. बेहतरीन संगीत और नृत्य चल रहा था. मैंने देखा कि नीरा नृत्य की काफी शौकीन थी. मैंने एक कॉकटेल लिया और क़रीब एक घंटे तक उसे थामे रहा और फिर घर वापस जाने का निर्णय लिया. घर जल्दी जाने की मेरी आदत रही है, क्योंकि मेरी पत्नी 1992 से ही स्लेरोसिस नामक बीमारी से ग्रस्त है. इस बीमारी में व्हील चेयर पर बेहतर देखभाल की ज़रूरत होती है. मेरे दो बेटे हैं, एक लंदन में और दूसरा यहीं भारत में पढ़ाई कर रहा है. मेरी विधवा मां भी मेरे साथ रहती हैं. ऐसे में उनकी देखभाल की सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही है. तब मैं दरभंगा छतरपुर फॉर्म में रहता था. वह शहर से दूर एक बहुत ही शांत जगह है. मैं अपने घर किसी भी क़ीमत पर रात नौ बजे तक ज़रूर आ जाता था.

केएलएम-मोदीलुफ्त विवाद

1996 की उस रात के डिनर के बाद नीरा ने एक दिन मुझे ऑफिसियल अप्वायंटमेंट के लिए कॉल किया. यह कॉल किसी पेशेवर मसले पर बातचीत के लिए थी. यह अप्वायंटमेंट शाम का था और नीरा सही वक्त पर पहुंची. उसके साथ दो अंग्रेज थे, केएलएम (यूके) का चीफ फिनांसियल ऑफिसर जॉन डेरबीशायर और दूसरा आदमी इयान स्मिथ था, जिसके बारे में मुझे बताया गया कि वह उसी कंपनी में एक अधिकारी है. उन लोगों ने मुझसे सलाह लेने से पहले बेहतर रिसर्च वर्क किया था. वे जब मेरे कमरे में आए, तब मेरी बातचीत जेम्स टिडमार्श से हो रही थी. टिडमार्श जेनेवा के एक वकील हैं, जो अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उनके क्लाइंट की मैंने एक केस में मदद की थी.

बहरहाल, नीरा और उनके साथ आए लोगों में गजब का आत्मविश्वास था. मुझे भी विमानन क्षेत्र का अच्छा-खासा अनुभव रहा है. उदाहरण के लिए, 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार मोहन कुमारमंगलम की मौत इंडियन एयरलाइंस के बोइंग-707 के एयरक्रैश में हो गई. जांच हुई. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने जांच की. मैं इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन की तरफ़ से था और मैंने को-पायलट का बचाव किया. मैंने डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशक) का भी कई मौक़े पर बचाव किया, जिनमें कनिष्क विमान हादसा भी शामिल है. 9/11 से पहले हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे.

वे दोनों अंग्रेज डीजीसीए और विधि मंत्रालय में मेरे संपर्क के बारे में जानते थे और मेरी मदद चाहते थे. यहीं से मेरी सीधी टक्कर नीरा से होनी शुरू हुई. एयर यूके (तब केएलएम-यूके) ने मोदीलुफ्त को तीन विमान लीज पर दिए थे. मोदीलुफ्त का मालिक सतीश मोदी है. लीज का समय ख़त्म होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन विमान का स्वामित्व मोदीलुफ्त के पास ही था, जिससे यूके की इस कंपनी को भारी नुक़सान हो रहा था. इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति हवाई यात्रा करता है, तब वह एयर ट्रैवल टैक्स देता है, जिसे एयरलाइन की ओर से कस्टम विभाग वसूलता है, ताकि उसे सरकार के पास जमा कराया जा सके. इस केस में मोदीलुफ्त ने यात्रियों से कर तो लिया, लेकिन उसे सरकार के पास जमा नहीं किया. मोदीलुफ्त के पास सरकार के क़रीब 12.5 करोड़ रुपये बकाया थे. इस वजह से कस्टम ने उसके विमान अपने पास रख लिए, ताकि पैसे वापस मिल सकें. अब सवाल यह था कि क्या कस्टम इन विमानों को बेचकर पैसे वापस पाएगा? आख़िरकार वे विमान मोदीलुफ्त के नहीं, बल्कि केएलएम (यूके) के थे.

जिस क्लाइंट ने मुझसे संपर्क साधा था, वह पहले ही कई अदालतों की दौड़ लगा चुका था, लेकिन असफल रहा था. जब उन लोगों ने नीरा राडिया से संपर्क साधा, तो नीरा उन्हें मेरे पास लेकर आई. मुझसे अपना वकील बनने का अनुरोध किया और डीजीसीए एवं विधि मंत्रालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कहा. मुझे लगा कि अगर एक भारतीय कंपनी (मोदीलुफ्त) पैसा नहीं दे रही है, तो ऐसे में भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होगी. एक दूसरी परेशानी केएलएम (यूके) के साथ यह थी कि उक्त विमान भारत में रजिस्टर्ड थे और जब तक उन्हें डी-रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, तब तक वे दुनिया के किसी और देश में फिर से रजिस्टर्ड नहीं होते. यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी. मैंने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाईं, कई आदेश प्राप्त किए. अंत में वे विमान भारत से क़रीब-क़रीब निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तीन करोड़ रुपये की मांग करके उन्हें रोक लिया. मैंने फिर विभिन्न प्राधिकरणों में याचिकाएं लगाईं, डीजीसीए को समझाया, तब कहीं जाकर वे विमान भारत से उड़कर स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट पहुंच सके. ***जारी...***

(आरके आनंद मशहूर वकील और क्लोज इंकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

कमल मोरारका

क्या 2019 का चुनाव मौजूदा सिस्टम में हो पाएगा

संसद सत्र में काम न होने की खूब चर्चा रही. लेकिन, मुझे लगता है कि इस सबके बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु भुला दिया गया. बिल पास न होने और सुधार प्रक्रिया रोके जाने पर खूब बातें हुईं, लेकिन यह सही नहीं है. जीएसटी बिल पास नहीं हुआ, जिसे पास करने या न करने से देश की प्रगति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा इसे बिहार चुनाव के बाद पास कराना चाहती है. लेजिस्लेटिव (विधायिका) काम न होना कोई बहुत दु:ख की बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है. दूसरी बात मीडिया में यह आई कि सत्र पर इतना अधिक पैसा खर्च हुआ और यह जनता द्वारा अदा किए गए टैक्स का पैसा था, जो बर्बाद हुआ. चूंकि मीडिया पूंजीपतियों के कब्जे में है, इसलिए वह उन्हीं के विचार परोसेगा. कॉरपोरेट चाहता है कि विधायिका उसके हित के लिए क़ानून बनाए, उसके व्यापार के हित में काम करे. उसे सामाजिक-आर्थिक मसलों या सामाजिक सौहार्द्र या अन्य मुद्दों से मतलब नहीं है. उसे इस सबकी चिंता नहीं है, जो जीएसटी या भूमि अधिग्रहण बिल की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

इसलिए पूरा मीडिया यही कहता रहा कि कांग्रेस सुधार प्रक्रिया को रोक रही है. भाजपा और सरकार कह रही है कि कांग्रेस विकास नहीं चाहती है. मानो एक या दो बिल पास नहीं हुए, तो उससे देश के विकास की राह में बड़ा फ़र्क आ जाएगा. यूपीए के दस सालों के दौरान आर्थिक प्रगति किसी भी मानक के हिसाब से ठीक थी. मनमोहन सिंह के शांत, सहज एवं सभ्य आचरण के साथ सरकार का प्रदर्शन अच्छा था. वे चुनाव घपलों-घोटालों की वजह से हार गए. क्या यूपीए सरकार के दौरान भाजपा संसद में हंगामा नहीं मचाती थी? लेकिन, इस समस्या का भी हल था. इस समस्या का हल अगर भाजपा सरकार चाहती, तो विपक्ष से बातचीत करके निकाल सकती थी. ऐसा करना भाजपा सरकार के लिए बहुत आसान था. उसने विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय संसद सत्र जाया होने दिया. ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई, भाजपा, संसदीय मामलों के मंत्री और उन लोगों की ओर से, जो संसदीय कार्यवाही का प्रबंधन करते हैं.

अब दो बातें हैं. हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा एक अनुभवहीन आदमी है. मुख्यमंत्री के रूप में उनका अनुभव है, लेकिन वह पूरी तरह से अलग बात है. दूसरी बात, उनके पास अपने दम पर, बिना सहयोगियों की ज़रूरत के, बहुमत है. 282 सीटें हैं. मेरी इस बारे में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब संघ के भीतर ऐसे विचार ज़रूर आए होंगे कि अब हम सत्ता में आ गए हैं, तो हमें सरकार का कांग्रेसी स्वरूप उलट देना चाहिए. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ परिवार की कोई भूमिका नहीं थी. ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को किया. बाद में जो लोग कांग्रेस से निकले, वे सोशल डेमोक्रेट हैं. इसलिए यह संविधान एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा देता है और इसे सफलतापूर्वक सोशल डेमोक्रेट द्वारा संचालित किया गया.

संघ परिवार को यह खुशफहमी हो सकती है कि देश ने सोशल डेमोक्रेट को खारिज कर दिया है. ज़ाहिर है, भाजपा ने पूरे देश के 16.5 करोड़ वोट पाए हैं, लेकिन मेरी किताब में अभी भी इन 16.5 करोड़ लोगों से कहीं अधिक लोग हैं, जो उसके साथ नहीं हैं. यह मूक बहुमत अभी भी स्वभाव से सोशल डेमोक्रेट है. यह देश एक सोशल डेमोक्रेट देश है. मैं नहीं जानता कि सत्ता पक्ष की योजना क्या है, लेकिन मुझे आशंका है कि यदि पिछली संसद की तरह इस बार भी चापलूसी होती है, तो लोगों को यह समझाना आसान हो जाएगा कि इस देश का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना आदि सब पुराने हो चुके हैं. यदि ऐसा होता है, तो यह इस देश के लिए एक बहुत गंभीर बात होगी. मैं उन लोगों में से हूं, जो मानते हैं कि भारत जैसे देश के लिए यह संविधान सबसे अधिक समझदार, सबसे अधिक मानवीय, सबसे अधिक प्रगतिशील और सबसे अधिक लोकतांत्रिक है. चीन ही केवल ऐसा देश है, जिसके साथ तुलना की जा सकती है, लेकिन वहां लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है. यूरोप के देश छोटे हैं. अमेरिका और ब्रिटेन सही उदाहरण हैं. ब्रिटेन एक पुराना लोकतंत्र है, जहां से हमने अपना संविधान लिया है. हम ऐसी स्थिति से कैसे निपटते हैं, इसे लेकर मैं वास्तव में चिंतित हूं. मैं बिल पास न होने से चिंतित नहीं हूं. यहां तो घर में ही समस्या है.

यह बड़ा मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि हमारे सिस्टम (व्यवस्था) के साथ क्या होता है? शरद यादव ने सही कहा कि हम संसद को चलाने के बारे में पूंजीपतियों से व्याख्यान नहीं सुनना चाहते. हम जानते हैं कि पूंजीपति केवल अपने उद्देश्य का हल चाहते हैं, वह चाहे लोकतंत्र से निकले या तानाशाही से. इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की, तब उद्योग जगत ने उनके घर के सामने एकत्र होकर कहा कि अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है और इंदिरा गांधी ने सही काम किया है. इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोगों की बातें हमें नज़रअंदाज़ करनी चाहिए. देश का अपरिपक्व लोगों के हाथों में जाना एक ख़तरनाक बात है. ट्वीटर पर आवाज़ें उठ रही हैं कि एक फ्रांसीसी शैली की क्रांति राह पर है. मुझे इस पर विश्वास नहीं है. भारत वास्तव में एक अच्छा देश है, एक स्थिर देश है और वास्तविक स्थिरता गांवों में है, जिनसे हवाई किले में बैठे इन आंदोलनकारियों और इंडस्ट्री कैप्टन का कोई लेना-देना नहीं है. कोई भी आदमी गांवों में जाकर देख सकता है कि वहां की पंचायत प्रणाली पूरी मजबूती से स्थापित है. लोकतंत्र में हर पंचायत के तीन वर्ग हैं. एक सत्तारूढ़, दूसरा, जिसे हटाकर सत्ता मिली है और तीसरा, जो सत्तारूढ़ पार्टी को हटाना चाहता है. लेकिन, यह सब ठीक है. यही लोकतंत्र है.

> संघ परिवार को यह खुशफहमी हो सकती है कि देश ने सोशल डेमोक्रेट को खारिज कर दिया है. ज़ाहिर है, भाजपा ने पूरे देश के 16.5 करोड़ वोट पाए हैं, लेकिन मेरी किताब में अभी भी इन 16.5 करोड़ लोगों से कहीं अधिक लोग हैं, जो उसके साथ नहीं हैं. यह मूक बहुमत अभी भी स्वभाव से सोशल डेमोक्रेट है. यह देश एक सोशल डेमोक्रेट देश है. मैं नहीं जानता कि सत्ता पक्ष की योजना क्या है, लेकिन मुझे आशंका है कि यदि पिछली संसद की तरह इस बार भी चापलूसी होती है, तो लोगों को यह समझाना आसान हो जाएगा कि इस देश का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना आदि सब पुराने हो चुके हैं.

हर पांच साल में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जाते हैं. वहां भी भ्रष्टाचार है, लीकेज हैं. अब इस सरकार ने 15 महीने के बाद अपना स्वयं का बयान बदल लिया है. और, कह रही है कि मनरेगा ग़रीबी कम करने में कामयाब रही है. शुरू में इसे भ्रष्टाचार फैलाने वाली योजना बता रही थी. लेकिन, मुझे इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए. अभी तो सिस्टम ख़तरे में है. आडवाणी जी ने ठीक ही कहा है कि आपातकाल जैसा ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि यह तभी आता है, जब बहुत अधिक शक्ति एक हाथ में केंद्रित हो जाती है. आज फिर से ऐसी ही स्थिति है. संसद में जो कुछ हुआ, उसे लेकर मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस, विशेषकर सोनिया गांधी को संघ परिवार के जाल में नहीं फंसना चाहिए और न अपनी पार्टी को इसकी अनुमति देनी चाहिए. अन्य सभी क्षेत्रीय दलों और सोशल डेमोक्रेट के लिए भी यही लागू होता है. यह जाल सिस्टम को नीचा दिखाने और फिर इसे समाप्त करने के लिए है. इसकी जगह दूसरा क्या सिस्टम आएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. समय की मांग है कि समूचे विपक्ष को नीतियों और जीत-हार के मसले पर नहीं, बल्कि सिस्टम को बचाने के मसले पर एक साथ आना चाहिए. जैसे जेपी 1977 में सबको एक साथ लेकर आए और यह महसूस कराया कि अगर कांग्रेस जीतती है, तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा.

समय आ गया है कि हर किसी को अपने मतभेद भुलाकर सिस्टम को बचाने के लिए आगे आना चाहिए. यह सिस्टम पवित्र है. यदि मैं स्पीकर की कार्रवाई के ख़िलाफ़ बोलता हूं, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा. वर्तमान स्पीकर बहुत अच्छी हैं. मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं. लेकिन, मुख्य विपक्षी दल के 44 सदस्यों में से 25 को निलंबित करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. यह संसद का महत्व कम कर देता है. दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में 70 में से भाजपा के सिर्फ़ तीन सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें मुख्य विपक्षी दल के रूप में पहचान दी है. लोकतंत्र को सिद्धांतों और परंपराओं पर चलाना चाहिए. इस पर नहीं कि कौन जीतता है या कौन नहीं जीतता. चुनाव पांच साल के लिए होते हैं, जिसमें से एक साल बीत गया है. लेकिन, मुझे भय है कि क्या 2019 का चुनाव इसी सिस्टम में होगा? अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, तो हो सकता है कि 2019 का चुनाव इस सिस्टम के तहत न हो. उस स्थिति से बचने के लिए सभी ग़ैर-भाजपा दलों को साथ आना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए. अभी भी देर नहीं हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> समय आ गया है कि हर किसी को अपने मतभेद भुलाकर सिस्टम को बचाने के लिए आगे आना चाहिए. यह सिस्टम पवित्र है. यदि मैं स्पीकर की कार्रवाई के ख़िलाफ़ बोलता हूं, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा. वर्तमान स्पीकर बहुत अच्छी हैं. मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं. लेकिन, मुख्य विपक्षी दल के 44 सदस्यों में से 25 को निलंबित करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. यह संसद का महत्व कम कर देता है. दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में 70 में से भाजपा के सिर्फ़ तीन सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें मुख्य विपक्षी दल के रूप में पहचान दी है. लोकतंत्र को सिद्धांतों और परंपराओं पर चलाना चाहिए.

जब एक स्त्री डाकू बदला लेने पहुंचती है

मृतकों की संख्या 20, स्थान बेहमई, समय 14 फरवरी की रात और हत्याकारी फूलन देवी. फूलन ने उस रात ठाकुरों के कत्लेआम का जो दृश्य पेश किया, उसके पीछे उसका अपना कड़वा अतीत था. लालाराम और श्रीराम डाकू थे तथा पास के गांव दमनपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने फूलन के प्रेमी विक्रम मल्लाह को धोखे से मरवा दिया था तथा जिनके गिरोह ने फूलन को बंदी बनाकर उसके साथ दर्जनों बार बलात्कार किया था. बेहमई उनके अड्डों में से एक था. क्या यह फूलन की व्यक्तिगत प्रतिहिंसा थी या इसके पीछे उत्तर प्रदेश में उभर रहे जातिवाद की नई उग्रता भी थी? इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान संतोष तिवारी ने भी दिया था. बेहमई ने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के डाकुओं को जाति के आधार पर बांट दिया, पर छुपे तौर पर अलग-अलग क्षेत्रों के डाकू जाति के आधार पर धीरे-धीरे बंटने लगे थे. पुलिस अधिकारी भी अपनी जाति का सहारा लेकर डाकुओं द्वारा दूसरी जाति के डाकुओं को मरवाने लगे थे. बेहमई ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े पैमाने पर डाकुओं के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए मजबूर कर दिया था. वहीं दूसरी ओर डाकुओं ने भी अपने को और ज़्यादा संगठित करना प्रारंभ कर दिया था. दरअसल, बेहमई एक ऐसा मोड़ है, जिसने जुल्म और बदले का खौफनाक चेहरा देखा है.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

क्या यह महज एक संयोग था कि जिस समय कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक वीके जैन अपने बंगले में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस द्वारा क़ानून-व्यवस्था कायम करने की डींगें हांक रहे थे, ठीक उसी समय उनसे कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर उनके ही क्षेत्र के एक गांव बेहमई में क़ानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. मिठाइयां कुतरते और कॉफी की चुस्कियां लेते पत्रकार वहां उनसे डाकू-पुलिस मुठभेड़ों के रोमांचक किस्से सुन रहे थे, उधर बेहमई में 20 लोग फूलन देवी के गिरोह के हाथों अपने ठाकुर होने या समझे जाने की क़ीमत अपनी जान देकर अदा कर रहे थे.

यमुना नदी के किनारे बीहड़ों में स्थित गांव बेहमई में 14 फरवरी को सूरज कुछ जल्दी ही डूब गया था. गोलियों की बौछार से अप्रत्याशित ढंग से बचे वकील सिंह के अनुसार, गांव में क़रीब दो बजे फूलन देवी के नेतृत्व में डाकू आए. उन्होंने सबसे पहले गांव के मुखिया के यहां धावा बोला, पर मुखिया उस समय गांव में नहीं थे. फिर डाकुओं ने एक-एक घर में घुसना शुरू किया. आदमियों को पकड़-पकड़ कर गांव के बीच स्थित कुएं के चबूतरे पर बैठा दिया गया और लूटपाट चलने लगी. औरतों व बच्चों को डाकुओं ने नहीं छुआ. यह सब क़रीब एक घंटे तक चला. तब उनकी नेता फूलन देवी ने, जो कंधे पर मैगाफोन टांगे हुए थी, चिल्ला कर कुएं में इकट्ठा किए गए लोगों से गांव के बाहर की तरफ़ चलने को कहा. उसने कहा कि वह वहां पंचायत करना चाहती है. गांव वालों के लिए डाकुओं का आना और पंचायत करना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए सब चुपचाप उधर चल दिए. बाहर निकल कर, जहां पर रास्ता कुछ गहरा जाता है और दोनों तरफ़ मिट्टी की दीवारें उठी हुई हैं, फूलन ने सबको एक दीवार से पीठ टेककर बैठने का आदेश दिया. सबने उसके आदेश का पालन किया. इसके बाद उसने फूलन देवी की जय, मुस्तकीम की जय और काली माता की जय के नारे लगाते हुए दीवार से पीठ टिकाए बैठे ग्रामीणों पर अपनी राइफल से गोली चलाना शुरू कर दिया.

सोहन सिंह, जिनकी कमर कई महीने पहले एक दुर्घटना में टूट गई थी और जो डाकुओं के आने के समय अपने पक्के घर के बाहर चबूतरे पर बिछी चारपाई पर लेटे हुए थे, ने बताया, डाकू आकर मुझसे चाबियां मांगने लगे. मैंने कहा कि चाबियां मेरे पास नहीं हैं. इस पर एक डाकू ने मुझे जोर से अपनी बंदूक का कुंदा मारा. सोहन सिंह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, मुझ अपंग को क्यों मारना चाहते हो? तब फूलन देवी ने अपने साथियों को ऐसा करने से मना कर दिया. लेकिन वे उनके छोटे भाई बनवारी सिंह को पकड़ ले गए और उसे मार दिया. घायल जंटर सिंह के अनुसार, जब हमें कुछ शंका हुई, तो सबने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन फूलन के चेहरे पर सख्त भाव बने रहे. पहले उसके साथियों ने हमें लाठियों से पीटा, फिर फूलन ने स्पीकर से हमें मारने का आदेश दे दिया. इसके बाद जो कुछ हुआ, मैं देख नहीं सका. एक गोली मुझे लगी और पांच अन्य मुझ पर कटे पेड़ की तरह गिर पड़े. फिर होश नहीं रहा. जंटर सिंह ने बताया कि वह उस वक्त अपने घर में दरवाजे बंद किए सो रहा था, जब उसके दरवाजे खटखटाए गए. उसने उठकर दरवाजा खोला, तो सीधे उसके सीने पर बंदूक की नाल रख दी गई. एक अन्य घायल गुरुमुख सिंह के अनुसार, पता नहीं था कि वे हमें मारने आए हैं. जिस इत्मीनान से उन्होंने हमें इकट्ठा किया था, उससे तो यही लगता था कि शायद वे खाने-रहने के लिए ही आए हैं. लेकिन, फिर अचानक उनके तेवर बदल गए.

कुछ ग्रामीणों के अनुसार, डाकू हर एक से उसकी जाति पूछ रहे थे और ठाकुरों को ही छांटकर कुएं पर बैठने का आदेश दे रहे थे. गांव के कुल 45 घरों में अधिकांश घर ठाकुरों के ही हैं. बाकी लोहार, गड़रिया, ब्राह्मण व बनिया हैं. उस समय गांव में कुल 30 आदमी मौजूद थे, जिनमें 25 को डाकुओं ने बटोर लिया था. इनमें तीन मज़दूरों को छोड़कर, जो तुलसी राम के यहां काम कर रहे थे, सभी ठाकुर थे. बताते हैं कि मारने से पहले फूलन देवी ने उनसे उनकी जाति की पुष्टि करनी चाही, तो उक्त तीनों मज़दूरों के साथ-साथ सभी अपने को ग़ैर-ठाकुर बताने लगे. इस पर झुंझला कर फूलन ने सबको मौत के घाट उतार दिया. इस दौरान वह माइक पर बार-बार लालाराम व श्रीराम, जो इस क्षेत्र के डाकू सरदार हैं और जिनके द्वारा फूलन के प्रेमी विक्रम की हत्या किए जाने की चर्चा है, को पनाह देने वाले ठाकुर को भंगी बना देने का ऐलान करती रही. उसने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है और उसने एक हज़ार ठाकुरों को सबक सिखाने की कसम ली है. किसान सिंह का कहना था कि सभी डाकू पुलिस की वर्दी में थे. पहले तो उसने उन्हें असली पुलिस वाला ही समझा, वरना उसे भागने का पूरा मौक़ा था. उसे दो गोलियां लगीं, फिर भी वह बच गया, जबकि उसका भाई शिव बालक सिंह मारा गया. दो ग्रामीणों बालमुकुंद सिंह और तखत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि डाकू गांव में आ रहे हैं, वे सिर पर पैर रखकर भाग लिए. तखत सिंह के अनुसार, वह दौड़ते हुए बेहमई से क़रीब दो किलोमीटर दूर खोजा रामपुर गांव में लगे पीएसी कैंप में गया और उन्हें बेहमई में डाकुओं के आने की ख़बर दी. लेकिन, उस समय पीएसी के लोग वालीबॉल खेल रहे थे. उन्होंने उसके साथ जाने से इंकार कर दिया. गांव वालों ने यह भी बताया कि गांव में उस वक्त कुछ गड़रिया भी थे, जिनकी जाति जानकर डाकुओं ने उन्हें गांव से भगा दिया. ■

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह देशप्रेम नहीं, देशद्रोह है

> “देश के सामने इस समय आर्थिक मंदी का ख़तरा पैदा हो गया है. हम तीन प्रतिशत मुद्रा अवस्फीति (डिफ्लेशन) की तरफ़ चले गए हैं, बाहर से निवेश आ नहीं रहा है. सरकार की वे तमाम योजनाएं, जिनसे रोज़गार सृजित हो सकते थे, न शुरू हो पाई हैं और अगर वे अगले एक साल में शुरू भी हुईं, तो इतनी जल्दी उनका कोई असर नहीं दिखने वाला. व्यापारियों के पास धन नहीं है, नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं. ऐसी स्थिति में कई लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार के ऊपर आ जाना देशप्रेम नहीं, देशद्रोह है.”

एक मजेदार स्थिति पैदा हो गई है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था से तो रिश्ता है, लेकिन उसका इस्तेमाल राजनीतिज्ञ अपने हक़ में करना चाहते हैं. चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के, बिना यह जाने कि इस मांग का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, उसे उठाते जा रहे हैं और देश को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं. वन रैंक-वन पेंशन की मांग रिटायर हुए सैनिक उठाते आ रहे हैं और इस मांग को शुरू किया बड़े अफसरों ने. लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और वे सारे लोग, जो रिटायर हो चुके हैं. सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं, जब यह मांग हमारे सामने आती है और तब लगता है कि दोनों पार्टियों के शीर्षस्थ लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं. न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोच रहे हैं और न उनकी पार्टियां.

सेना के वर्तमान अधिकारी इस मांग के ख़िलाफ़ हैं और उनका कहना बिल्कुल सही है. उनका कहना है कि जिन भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों ने यह मांग शुरू की, उन्होंने बहुत सस्ते में महानगरों में बड़ी-बड़ी कोठियां बना लीं और अब वे आज की राशि के ऊपर ज़्यादा पैसा पेंशन के ज़रिये लेना चाहते हैं. पेंशन का सिद्धांत है कि जिस आख़िरी तनख्वाह के ऊपर आप रिटायर हुए, उससे संबंधित नियमानुसार पेंशन तय होती है. लेकिन, आप चाहते हैं कि जो आज की तनख्वाह पर अफसर या सिपाही रिटायर हों, वही पैसा उस समय रिटायर हुए अफसर या सैनिक को मिले, जो कि निहायत ग़लत है. अगर सेना के लिए वन रैंक-वन पेंशन की मांग लागू होती है, तो इसके बाद अर्द्धसैनिक बलों द्वारा यह मांग उठाई जाएगी कि हमने भी अपनी जान हमेशा जोखिम में डाली और हमें भी वन रैंक-वन पेंशन मिलनी चाहिए. इसके बाद पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी यही मांग उठाएंगे और देश का आईएएस तबका यह मांग उठाने के लिए अभी से तैयारी कर रहा है.

देश के सामने इस समय आर्थिक मंदी का ख़तरा पैदा हो गया है. हम तीन प्रतिशत मुद्रा अवस्फीति (डिफ्लेशन) की तरफ़ चले गए हैं, बाहर से निवेश आ नहीं रहा है. सरकार की वे तमाम योजनाएं, जिनसे रोज़गार सृजित हो सकते थे, न शुरू हो पाई हैं और अगर वे अगले एक साल में शुरू भी हुईं, तो इतनी जल्दी उनका कोई असर नहीं दिखने वाला. व्यापारियों के पास धन नहीं है, नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं. ऐसी स्थिति में कई लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार के ऊपर आ जाना देशप्रेम नहीं, देशद्रोह है. हम मौजूदा व्यवस्थाओं को देखते हैं कि वे चरमरा रही हैं. उदाहरण के लिए टेली कम्युनिकेशन. न इंटरनेट चल रहा है, न फोन कनेक्ट हो रहे हैं. फोन एक बार कनेक्ट हो जाए, तो तीन बार कॉल ड्रॉप होती है. हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को पैसा जाने वाला है और ऐसे में, अगर यह ख़तरा भी हमारे सामने पैदा हो जाए कि 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये भूतपूर्व सैनिकों को मिलने हैं, तो यह पैसा कहां से आएगा, किसी को नहीं पता. इसके बाद अर्द्धसैनिक बल, फिर पुलिस और उसके बाद आईएएस अधिकारी. यह देश दिवालिएपन की कगार पर चला जाएगा.

इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादे के रूप में छेड़ दिया और अब उनके मंत्री एवं भूतपूर्व सैन्य अधिकारी राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री ने दो-दो बार वादा किया है, इसलिए यह लागू होगा. जब वादा किया था, तब प्रधानमंत्री को यह नहीं पता था कि कितने पैसे का बोझ आने वाला है. और, वह देश की अर्थव्यवस्था में किन योजनाओं की कटौती करके यह पैसा निकालेंगे? राहुल गांधी से तो अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए कि वह इन सारी चीजों से कुछ सीख लेंगे. उनकी सरकार थी और उस समय भी वन रैंक-वन पेंशन की मांग उठ रही थी, तब उन्होंने इसे क्यों नहीं लागू किया? आज मौजूदा सरकार को परेशान करने के लिए वह देश को गर्त में ले जाने की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था का जरा भी ज्ञान होता, तो वह चुनाव में फ़ायदा लेने के नाम पर या भूतपूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जगह देश को गिरती अर्थव्यवस्था के दायरे से निकालने वाले सुझाव देते.

इसलिए मैं प्रधानमंत्री से यह आग्रह करता हूं, पूरी सरकार से आग्रह करता हूं तथा कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करता हूं कि देश को बर्बाद करने वाली इस मांग को स्वीकार नहीं करना चाहिए. सेना के मौजूदा अफ़सरों से राय लेनी चाहिए और अगर उनकी राय इसके ख़िलाफ़ है, तब तो इस मांग को हरगिज लागू नहीं करना चाहिए.

टेलीविजन पर बार-बार आ रहा है कि अन्ना हजारे ने इसका समर्थन किया. आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि अन्ना हजारे किसी चीज को नहीं समझते हैं. सारी जगह यह चर्चा है कि अन्ना हजारे की मौजूदा पेंशन छह हज़ार रुपये है, यह मांग लागू होते ही उनकी पेंशन तीस हज़ार रुपये हो जाएगी. अन्ना हजारे ने पहले मांग की कि देश से भ्रष्टाचार हटाने वाली संस्थाएं बननी चाहिए, यह मांग उन्होंने बीच में छोड़ दी. लोकपाल बिल पास हो गया, लोकपाल नहीं नियुक्त हुआ, इस मांग को भी छोड़ दिया. किसानों का सवाल उठाया, उसे भी छोड़ दिया. दस बार यह वादा करने के बाद कि मैं पदयात्रा करूंगा, देश भर में भ्रमण करूंगा, लोगों को तैयार करूंगा, ताकि किसानों के सवाल को देश और सरकार समझे. लेकिन, किया कुछ भी नहीं, हर बार बहाना बनाकर रास्ते से भाग गए. शब्द बहुत कठोर हैं, लेकिन मेरे दर्द से जुड़े हुए हैं. बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी ऐसे लोगों के प्रेम में आकर बर्बाद हो गई, उनके साल बर्बाद हो गए, जिन्हें वे देश बदलने का अग्रदूत मानते थे.

> सेना में जो सिपाही गए और जो आज मांग कर रहे हैं कि वन रैंक-वन पेंशन होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, तो उनसे सवाल यह है कि क्या उन्हें किसी ने आमंत्रण भेजा था कि आप सेना में आइए और अपनी जान जोखिम में डालिए? आप क्यों सेना में गए? सेना से आने के बाद जो उस समय की सेवा शर्तें थीं, उनके अनुसार आपको जो मिल रहा है, उसके ऊपर संतोष करना चाहिए. सारे देश को आर्थिक भंवर में डालने वाली मांग करने वाले भूतपूर्व सैनिक आख़िर कैसे देशप्रेमी हैं?

सेना में जो सिपाही गए और जो आज मांग कर रहे हैं कि वन रैंक-वन पेंशन होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, तो उनसे सवाल यह है कि क्या उन्हें किसी ने आमंत्रण भेजा था कि आप सेना में आइए और अपनी जान जोखिम में डालिए? आप क्यों सेना में गए? सेना से आने के बाद जो उस समय की सेवा शर्तें थीं, उनके अनुसार आपको जो मिल रहा है, उसके ऊपर संतोष करना चाहिए. सारे देश को आर्थिक भंवर में डालने वाली मांग करने वाले भूतपूर्व सैनिक आख़िर कैसे देशप्रेमी हैं? क्या उन्हें देश के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है?

इसलिए मैं सेना के मौजूदा अफसरों के साथ हूं, जो कम से कम देश के बारे में सोच रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले वक्त को देख रहे हैं. इसलिए राजनीतिक दलों की इस मांग को मैं देशभक्ति की मांग नहीं मानता. मुझे यह मांग निहायत स्वार्थी मांग लगती है और मैं आख़िर में सभी भूतपूर्व सैनिकों से यह सवाल करना चाहता हूं कि आप सेना में देशप्रेम का ज़ज्बा लेकर गए थे और आज आप देश को बर्बाद करने की मांग कर रहे हैं. आप एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, जो सिर्फ़ सेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्यों लागू हो? फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और आईएएस के लिए क्यों नहीं? आप इतने स्वार्थी कैसे हो गए? मैं इस मुद्दे पर चाहता हूं कि सरकार और विपक्ष देश को सामने रखकर सोचे, न कि चुनावी स्वार्थ को ध्यान में रखकर.

सेना के मौजूदा अफसर और सिपाही इसलिए भी मांग उठाने वाले भूतपूर्व सैनिकों और अधिकारियों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय चुप्पी साध ली, जब भूतपूर्व सैनिकों का सरकारी नौकरियों में कोटा कम किया जा रहा था. दरअसल, भूतपूर्व अधिकारी आज भी भूतपूर्व सैनिकों को कुछ भी दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं. इसीलिए आज सेना के भीतर इस मांग को लेकर गुस्सा है और अफ़सोस भी. ■

editor@chauthiduniya.com

नेतृत्व का हुनर सिखाने की कवायद

मेघनाद देसाई

कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन से केवल एक ही सवाल पैदा होता है कि उसके कुल 44 सांसदों को क्यों नहीं निलंबित किया गया? सदन में पार्टी नेतृत्व के उकसाने और प्रोत्साहन पर सांसदों के लगातार दुर्व्यवहार को कैसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है? राहुल गांधी अपने सांसदों को टीवी कैमरे की तरफ़ प्लेकार्ड का रुख करने का इशारा करते दिखे, जो ज़ाहिर करता है कि यह सारा हंगामा कहीं राहुल गांधी को नेतृत्व का हुनर सिखाने की कवायद का नतीजा तो नहीं है? पिछली संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति नाममात्र थी. वह विरले ही बोलने के लिए उठे और जब बोले, तो यह जताने की कोशिश में कि अभी-अभी किस मुफस्सिल में उन्होंने रात बिताई. हालांकि, वहां से हासिल अनुभवों से वह काफी आश्चर्यचकित दिखे, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकतर समय तो विदेश में बिताया. हम जैसे लोगों के लिए बिना छत और बिना सुनिश्चित रोज़गार के जीवन गुज़ारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. अंततः यह कांग्रेस राज का ही प्रतिफल है. ऐसा लगता है कि भाजपा भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन के लिए राजी हो जाएगी. अगर ऐसा हुआ, तो विपक्ष इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देखेगा और इस कामयाबी को सदन में व्यवधान डालने की नीति का नतीजा बताएगा. हालांकि, ऐसा नतीजा नौ महीने पहले भी हासिल हो सकता था. साथ ही यह भी कि विधेयक को सदन में पेश करते समय ही विपक्ष के रचनात्मक सुझाव अपना लिए गए होते और बहस के बाद उनके पर्याप्त सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया गया होता. यदि दुनिया की दूसरी संसदों में किसी हंगामे के बिना और कामकाज ठप्प किए बग़ैर क़ानून में संशोधन कर लिया जाता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता?

दरअसल, इसके कुछ कारण हैं. संसद वह जगह नहीं है, जहां आप क़ानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करते हैं, बल्कि यह वह जगह है, जहां विपक्ष अहमियत न मिलने की वजह से अपनी भड़ास निकालता है. जब वर्ष 2004 में भाजपा (एनडीए) चुनाव हार गई, तो जहां एक तरफ़ पार्टी नेतृत्व खुद से खफा था, वहीं हार की वजह न समझ पाने के चलते भी नाराज़ था. जनता ने न सिर्फ़ इंडिया शाइनिंग कैंपेन को नकार दिया था, बल्कि सत्ता की लगाम एक विदेशी (सोनिया गांधी) के हाथों में सौंप दी थी, जिन्हें भाजपा नापसंद करती थी. सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आत्मदाह करने और विधवा जैसा सिर मुड़ाने की धमकी तक दी गई. इस तरह के अनुकरणीय लोकतांत्रिक सदाचार को उस वक्त धक्का लगा, जब सोनिया गांधी ने खुद ही प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया. इस घटना ने भाजपा का गुस्सा और बढ़ा दिया. पार्टी ने आडवाणी की अगुवाई में अगली दो लोकसभाओं का समय सत्ता में न आने का गुस्सा निकालने में बिता दिया. यह नया विघटनकारी संसदीय व्यवहार भाजपा के चुनाव जीतने के साथ समाप्त नहीं हुआ. उसके बाद कांग्रेस ने इसे अपनाने का फ़ैसला किया.

कांग्रेस यह नहीं समझ पा रही है कि आख़िर देश के लिए गांधी-नेहरू परिवार की कई पीढ़ियों की कुर्बानियां लोग कैसे नकार सकते हैं और वह भी इतने तिरस्कार के साथ? सोने पर सुहागा यह हुआ कि भाजपा एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जीती, जिसे भारत के नेहरूवादी विचार के मुताबिक कभी नहीं जीतना चाहिए था. एक मौत का सौदागर, जिसकी कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त मीडिया अभी तक लानत-मलामत करता रहा था, कैसे एक निर्णायक अंतर के साथ जीत गया. सबसे बड़ी बात यह कि नेहरू-गांधी वंश की अगली पीढ़ी के नेता को यह राष्ट्र सौंपा जाना था, जिसने बड़ी बहादुरी से अपनी मां के हाथों दिए जा रहे नेतृत्व का ज़हर पीना स्वीकार भी कर लिया था. यदि जनता ने आशा के अनुरूप फ़ैसला दिया होता, तो राहुल सत्ता संभालने के बाद सत्ता के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते, जैसा कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद को प्रशिक्षित किया था. फिलहाल कांग्रेस को जो चोट पहुंची है, वह उसकी बर्दाश्त से बाहर है. शायद वह इसे एक बुरे सपने की तरह ले रही है. जैसे ही देश और कांग्रेस नींद से जागेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर विराजमान होगी. लेकिन, जो कड़वी सच्चाई है, वह इससे बिल्कुल अलग है. राहुल गांधी को नेतृत्व का प्रशिक्षण सत्ता में रहते हुए नहीं, बल्कि संसद में एक विपक्ष के नेता के रूप में लेना होगा, हालांकि उन्हें संसद में उपस्थित रहना कोई खास पसंद नहीं है. लेकिन, अब वह संसद में भी कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि संसद का हर सत्र इतना छोटा होगा कि वह भोजनकाल से पहले ही स्थगित हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग राष्ट्रीय स्तर पर गठित सर्वोच्च संस्था है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में स्थित है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ऐसी शिकायतें की जाती हैं, जहां वस्तुओं या सेवाओं की कीमत अथवा मांगे गये मुआवजे की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक हो. यहां राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील भी की जा सकती है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है.

उपभोक्ता अधिकार क़ानून
क़मजोर नहीं है ग्राहक

चौथी दुनिया ब्यूरो

बाजार से कोई भी सामान, जो आप खरीदते हैं, उसके बदले आप एक निश्चित मूल्य चुकाते हैं. एक उपभोक्ता के तौर पर आपके कई अधिकार हैं, जिसका संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 के तहत होता है. यह कानून केंद्र सरकार द्वारा खास तौर से छोड़ी गई कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है. इस कानून के अंतर्गत निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आ जाते हैं. जब किसी उपभोक्ता को लगे कि वस्तु या सेवा में कुछ अनुचित या खराब है, जिसके कारण उसे हानि पहुंचती है, तब वह इस कानून का प्रयोग कर उचित उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.

ये शिकायतें जिला उपभोक्ता मंच या डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम में की जाती है. उपभोक्ता फोरम को एक दीवानी अदालत की तरह मामले को निपटाने का अधिकार है. विपक्षी के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने के अंदर उपभोक्ता फोरम को किसी उपभोक्ता की शिकायत पर अपना निर्णय करना चाहिए. यदि शिकायत से संबंधित वस्तु या सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण होना है तो ऐसी शिकायत पर उपभोक्ता फोरम को पांच महीने में अपना निर्णय ले लेना चाहिए .

इसके बाद, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राज्य आयोग होता है. हर राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग संबंधित राज्य की राजधानी में स्थित होता है. जिन मामलों में वस्तुओं या सेवाओं या शिकायतकर्ता द्वारा मांगे गये मुआवजे की कीमत बीस लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक हो, वहां यह शिकायत राज्य आयोग में की जाती है. जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के खिलाफ भी यहां अपील की जाती है. राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग राष्ट्रीय स्तर पर गठित सर्वोच्च संस्था है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में स्थित है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ऐसी शिकायतें की जाती हैं, जहां वस्तुओं या सेवाओं की कीमत अथवा मांगे गये मुआवजे की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक हो. यहां राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील भी की जा सकती है. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच): देशभर के उपभोक्ता टोल फ्री नम्बर 1800–11–4000 पर डायल कर सकते हैं और उपभोक्ता के रूप में अपनी परेशानी के लिए सलाह ले सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

उपभोक्ता के अधिकार

- जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार.
- उपभोक्ता पदार्थों एवं सेवाओं का मूल्य, उनका स्तर, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा व प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का अधिकार.
- जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपभोक्ता पदार्थों एवं सेवाओं की उपलब्धि के भरोसे का अधिकार.
- अपने पक्ष की सुनवाई का अधिकार व साथ ही इस आश्वासन का भी अधिकार कि सभी उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखा जायेगा.
- अनुचित व्यापार प्रक्रिया अथवा अनियंत्रित उपभोक्ता शोषण से संबंधित शिकायत की सुनवाई का अधिकार .
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

पैकेट बंद वस्तुओं को खरीदते समय यह देखना चाहिए

- निर्माता का नाम, पता एवं निर्माण व एक्सपायरी तिथि अंकित हो.
- सामान की मात्रा एवं एमआरपी प्रिंट होना चाहिए.
- औषधियां खरीदते समय निर्माण व एक्सपायरी तिथि जरूर पढ़ें.
- खरीदे गए वस्तु की रसीद जरूर लें.

आम आदमी का हथियार
सूचना का अधिकार

चौथी दुनिया ने अपने पाठकों एवं आम लोगों के लिए कुछ साल पहले यह कॉलम शुरू किया था. एक बार फिर यह कॉलम आपके समक्ष है. इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि इस कानून का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आपको इस कानून के इस्तेमाल से संबंधित कोई परेशानी हो या कोई सुझाव चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. पहले अंक में हम एक ऐसा आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के लिए कर सकते हैं.

सूचना का अधिकार: सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ. यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है.

किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं: सभी इकाइयों/विभागों, जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है.

किससे मिलेगी सूचना और कितना आवेदन शुल्क: इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन/लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पद का प्रावधान है. आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है. आवेदन के साथ क्रेंद सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है.

सूचना प्राप्ति की समय सीमा: पीआईओ को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए.

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना के लिए आवेदन

(राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु–जन्म–मृत्यु–आवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार करे)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,
मैने आपके विभाग में ..... तारीख को ..... के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन, अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है.

कृपया इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायें. मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उसपर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
2. विभाग के नियम के अनुसार, मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय–सीमा का पालन किया गया है?
3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?
5. मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रु अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड सं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3)का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय
नाम: पता: फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते है तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है.

चौथी दुनिया
एफ–2 सेक्टर–11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश पिन–201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

स्वास्थ्य

लहसुन खाएं, रोग भगाएं

लहसुन का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन इसके लाभ को देखते हुए इसे रामबाण कहें तो गलत नहीं होगा. यह एन्टीबैक्टिअल, एन्टीवायरल, एन्टीफंगल और एन्टीऑक्सिडेंट गुण से भरा होता है. इसे आप किसी भी रूप में खाएं, यह समान रूप से लाभ पहुंचाता है.

लहसुन के प्रमुख लाभ:

यह बैक्टिअल और वायरल संक्रमण को दूर करता है.

लहसुन त्वचा के संक्रमण को ठीक करता है. त्वचा पर इन्फेक्शन हो तो लहसुन को पीसकर उस जगह पर लगा कर कुछ देर बाद पानी से धो दें.

रोज सुबह खाली पेट लहसुन का एक फांक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है.

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है.

दिल को स्वस्थ रखता है. धमनियों को लचीला बनाने में बहुत मदद करता है.

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है.

लहुसन का एलिसिन रक्त के ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है. इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है.

यह एंटी एलर्जी गुण से भरा है.

गले का दर्द और जुकाम से बचाने में मदद करता है.

ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है. लहसुन खाने से शरीर में इन्सुलिन लेवल बढाने में मदद मिलती है.

कैंसर से बचाने में मदद करता है. इसमें मौजूद एलियल सल्फाइड एन्टी–कैंसर का काम करता है.

दांत के दर्द से राहत दिलाता है.

फ्रांसीसी राजा की जासूस थीं इयॉन

अरुण तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

चार्ल्स बियोमोंट का जन्म 5 अक्टूबर 1728 को हुआ था. उन्हें केवेलियर डी इयॉन के नाम से जाना जाता है. अपने जीवन में उन्होंने कई तरह की जिम्मेदारियां निभाईं. इन जिम्मेदारियों में फ्रेंच राजनयिक, जासूस और एक सैनिक के तौर किए गए काम शामिल हैं. इयॉन काफी खूबसूरत महिला थीं और उनमें किसी की भी नकल उतारने की गजब की काबिलियत थी. इयॉन ने अपने जीवन के 49 वर्ष पुरुष वेश में बिताए. हालांकि इस बात को लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनी रही कि वे आखिर पुरुष हैं या महिला. इयॉन खुद को महिला ही बताती थीं. उनके विषय में यह हमेशा एक विवाद का हिस्सा रहा. इससे अलग इयॉन ने जो विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं उसके लिए उनकी तारीफ की जाती है.

इयॉन का जन्म फ्रांस के बरगंडी शहर में हुआ था. उनका परिवार पूर्व में संभ्रांत था लेकिन उनके पिता को हुए नुकसान की वजह से परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया था. इयॉन को बचपन में भूतों की कहानियां पढ़ने में बहुत आनंद आता था. उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन बातों का उल्लेख भी किया. उनकी आत्मकथा का नाम है द इंटरेस्ट्स ऑफ केवेलियर डी, इयॉन बियोमोंट. इयॉन ने कानून की पढ़ाई की और सरकार में सचिव के पद पर कार्य करने लगीं.

सन 1756 में इयॉन को वहां के फ्रांस के राजा द्वारा गठित खुफिया संस्था में शामिल किया गया. राजा ने इयॉन को महारानी एलीजाबेथ से मिलने के लिए भेजा था जिससे अपनी ताकत को बढ़ाया जा सके और देश में उपस्थित में अन्य राजाओं से मजबूत स्थिति बनाई जा सके. उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध खराब चल रहे थे. इस वजह से महारानी से सिर्फ फ्रांसीसी महिलाएं और बच्चे ही मिल सकते थे. इयॉन को ब्रिटेन पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई. उन्होंने फ्रांस के राजा की मदद के लिए महारानी को मना भी लिया. इसके बाद उन्होंने रूस में भी नौकरी की. इसके बाद आगामी कई सालों तक वे फ्रांसीसी राजा की दूसरे देशों में मदद करती रहीं. इयॉन को फ्रांस की सर्वकालिक बेहतरीन महिला जासूसों में शुमार किया जाता है.■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

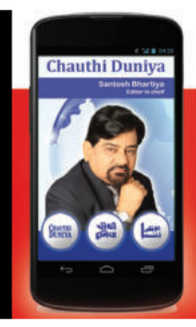

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

इराक और सीरिया जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रत्येक वर्ष कुछ लोग अकेले तो कुछ लोग काफ़िले के साथ ज़ियारत के लिए जाते हैं. सीरिया सरकार ने वहां आईएसआईएस के द्वारा फैलाई जा रही बर्बरता से बेबस होकर श्रद्धालुओं को वीज़ा देने से मना कर दिया है. सीरिया सरकार के द्वारा वीज़ा न देने के कारण भारत के श्रद्धालु भी ख़ुश नहीं हैं. चौथी दुनिया ने ईरान और सीरिया का सफर कराने वाले भारत के कुछ टूर ऑपरेटर्स से बात की तो कई बातें खुलकर सामने आईं. हैदराबाद के अलरज़ा टूर एंड ट्रैवल्स के अध्यक्ष शाबान अली प्रत्येक वर्ष भारतीय श्रद्धालुओं का काफ़िला ईरान, इराक और सीरिया लेकर जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह इस काफ़िले को वहां लेकर नहीं जा रहे हैं.

सीरिया बना आतंकवादियों का गढ़

तीर्थयात्री पवित्र स्थलों की ज़ियारत से वंचित

- सीरिया में आईएस ने ख़ूनख़राबे को बढ़ाया
- श्रद्धालुओं को ज़ियारत से रोक रहा है आईएस
- ईरान प्रत्येक वर्ष 40 लाख श्रद्धालुओं को देता है वीज़ा
- सीरिया सरकार का श्रद्धालुओं को वीज़ा देने से इंकार
- बदतर हालात के पीछे बशर अल असद की सरकार ज़िम्मेदार

मसरूर सुग़रा

इराक और सीरिया से दुनिया भर के मुसलमानों की श्रद्धा जुड़ी है. ईरान प्रत्येक वर्ष 40 लाख श्रद्धालुओं को वीज़ा देता है. जो श्रद्धालु ईरान जाते हैं, वह सीरिया में मौजूद पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सीरिया में आतंकवादियों ने ख़ूनख़राबे का माहौल कायम कर रखा है. वहां की वर्तमान परिस्थितियां हिंसा के आगोश में हैं. इन परिस्थितियों का जिम्मेदार आतंकी संगठन आईएसआईएस है, जो पूरी दुनिया को इस्लामी देश बनाने के इरादे से अस्तित्व में आया था और इस्लाम का मसीहा बन कर इस्लाम के सिद्धांतों को ही रौंद रहा है. आईएसआईएस यहां के लोगों को पवित्र स्थलों तक पहुंचने से रोकने का हरसंभव प्रयास कर रहा है.

इराक और सीरिया जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रत्येक वर्ष कुछ लोग अकेले, तो कुछ लोग काफ़िले के साथ ज़ियारत के लिए जाते हैं. सीरिया सरकार ने वहां आईएसआईएस के द्वारा फैलाई जा रही बर्बरता से बेबस होकर श्रद्धालुओं को वीज़ा तक देने से मना कर दिया है. सीरिया सरकार के द्वारा वीज़ा न देने के कारण भारत के श्रद्धालु भी ख़ुश नहीं हैं. चौथी दुनिया ने ईरान और सीरिया का सफर कराने वाले भारत के कुछ टूर ऑपरेटर्स से बात की तो कई बातें खुलकर सामने आईं.

हैदराबाद के अलरज़ा टूर एंड ट्रैवल्स के अध्यक्ष शाबान अली प्रत्येक वर्ष भारतीय श्रद्धालुओं का काफ़िला ईरान, इराक और सीरिया लेकर जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह इस काफिले को वहां लेकर नहीं जा रहे हैं. ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में शाबान कहते हैं कि जून 2012 में आख़िरी बार अपना काफ़िला लेकर वह सीरिया गये थे. इसके बाद से वहां पाबंदी लगा दी गई. सीरिया में ईरान और इराक से काफ़ी संख्या में लोग प्रत्येक वर्ष ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन भारतीय श्रद्धालुओं को वहां जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं. वहां की सरकार का कहना है कि अगर उन पर अचानक हमला हो जाए तो उनकी सुरक्षा बहुत मुश्किल है. हालांकि ऐसा कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती. शाबान अली ने बताया कि ख़ालिस बशर अल असद की जब सरकार थी तो उस समय शांति का माहौल था और श्रद्धालु ज़ियारत के लिए वहां जाते थे. उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता था, लेकिन अब आतंकवादियों ने ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं कि वहां की शांति हिंसा की भेंट चढ़ चुकी है.

मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी का कहना है कि ज़ायरीन सीरिया में फैले आतंकवाद से इतने परेशान हैं कि लाख उपाय के बाद भी वे वहां ज़ियारत करने नहीं जा पा रहे हैं. एजेंसी कहती है कि जब वह 800 डॉलर देकर कर्बला तक जाते हैं, तो और 400 डॉलर देकर वह सीरिया क्यों नहीं जाना चाहेंगे? सीरिया सरकार का कहना है कि वह ख़ुद तो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर नहीं पा रही है, तो फिर विदेशी श्रद्धालुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सैयद कल्बे रूशैद रिज़वी का कहना है कि उनकी सीरिया सरकार से अपील है कि वह अतिशीघ्र सीरिया से आतंकवाद का खात्मा करे .मुस्लिम समस्याओं और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ क़मर आग़ा का कहना है कि सीरिया की वर्तमान हालत का सबसे बड़ा कारण है बशर अल असद की बेबस सरकार. उसके क़ब्जे में आधे से ज़्यादा देश बाहर हैं. वहां की आर्थिक स्थिति आतंकवादियों के निरंतर हमले के कारण बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है. लाखों लोग बेघर हो गये हैं. वहां गृहयुद्ध जारी है.

आईएसआईएस को बहुत से दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त है. ऐसे हालात में भारत के श्रद्धालुओं का वहां जाना ख़तरे से ख़ाली नहीं है. आतंकवादियों के हौसले इस हद तक बुलंद हैं कि वह कर्बला और नजफ के साथ-साथ रोज़ा-ए-रसूल को भी तबाह करने और उन्हें किसी गुप्त स्थान पर दफ़न करने पर आमादा हैं. आतंकवादी मक्का स्थित ख़ाना-ए-काबा में हिजर अस्वद का भी अपमान करने पर तुले हैं. दिसंबर 2014 में ईरान और इराक की ज़ियारत करने वाले सैयद मुमताज़ अली रिज़वी का कहना है कि ज़ियारत के दौरान जितने भी श्रद्धालु सीरिया की ज़ियारत से वंचित रहे, उन लोगों की यही इच्छा थी कि सीरिया से शीघ्र-अतिशीघ्र आईएसआईएस का ख़ात्मा हो जाये और वहां का माहौल शांतिमय हो जाये, ताकि लोग वहां की ज़ियारत कर सकें. इन हालातों के मद्देनज़र भारत सरकार को इसे लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है. सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में सीरिया जाने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीरिया में आतंकवादियों की बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाने का हरसंभव कूटनीतिक प्रयास करे, ताकि श्रद्धालुओं को इन पवित्र स्थलों पर जाने का मौका मिल सके.■

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को कैंसर

जिम्मी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे. कार्टर ने 1977 से 1981 तक बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका की सेवा किया. पिछले दिनों उन्होंने दुनिया को बताया कि उन्हें कैंसर है. उनके इस बयान के बाद उनके प्रशंसकों में मायूसी छा गई. कार्टर ने बताया कि हाल ही में हुई लीवर सर्जरी के बाद उन्हें कैंसर होने के बारे में पता चला. गौरतलब है कि कैंसर अब उनके अन्य अंगों में भी फैल गया है. कार्टर की उम्र 90 वर्ष है. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा सहित दुनिया भर के नेताओं ने कार्टर के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है. कार्टर 1981 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से हाल के वर्षों में अपने कार्टर सेंटर के ज़रिए मानवीय मदद के कार्य कर रहे थे. राष्ट्रपति पद छोड़ने के तुरंत बाद ही उन्होंने मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए कार्टर सेंटर शुरू किया था. 1994 में उन्होंने उत्तरी कोरिया के साथ परमाणु समझौते में मध्यस्तता की थी. अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण हल के प्रयासों के लिए उन्हें साल 2002 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था. कार्टर ने एक किताब लिखा है, जिसका टाइटल है-ए फुल लाइफ़: रिफ़्लेक्शन एट नाइनटी.■

मलेशियन विमान हादसे में रूसी हाथ!

मलेशियाई विमान हादसे से कौन नहीं वाकिफ होगा. इस विमान हादसे ने विश्व राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया था. इस विमान हादसे के बारे में नीदरलैंड के जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए मलेशियाई विमान एमएच17 के मलबे में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं. ऐसी संभावना जताई गई है कि ये रूसी मिसाइल के टुकड़े हो सकते हैं. अगर नीदरलैंड के जांचकर्ताओं की बातों में तनिक भी सच्चाई है तो मलेशियाई विमान हादसे को देखने और विश्लेषण करने का पूरे विश्व का अंदाज बदल जाएगा. एमएच17 विमान पर 298 लोग सवार थे और पिछले साल जुलाई में इस विमान को गिराया गया था. हालांकि रूस ने इस घटना से अपने किसी भी तरह के संबंध से इंकार किया है. उस इलाक़े में सक्रिय रूस से समर्थित विद्रोहियों ने भी विमान गिराने से इंकार किया है. नीदरलैंड में संयुक्त जांच टीम ने संभावना जताई है कि जो टुकड़े मिले हैं, वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली बीयूके मिसाइल प्रणाली के हैं. इनसे इस बात की जांच करने में मदद मिल सकती है कि विमान हादसे के पीछे किसका हाथ था. हालांकि जांचकर्ताओं का कहना है कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मिसाइल के इन टुकड़ों और हादसे में क्या संबंध है.■

एक समय की बात है

पंडित माउंटबेटन की जय...

माउंटबेटन की 27 अगस्त, 1979 को हत्या कर दी गई थी. उस समय माउंटबेटन आयरलैंड में एक निजी नाव पर सवार थे. धमाका हुआ ही था और उसके कुछ ही देर बाद ब्रिटेन की महारानी के चचेरे भाई लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने दम तोड़ दिया. 79 वर्षीय लॉर्ड माउंटबेटन और उनका परिवार आम तौर से गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए उत्तर-पश्चिम आयरलैंड स्थित अपने महल में जाया करते थे. धमाके के समय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का परिवार उनकी निजी नाव शैडो-5 पर सवार थे. माउंटबेटन मछली पकड़ने के शौकीन थे और उस समय नाव पर वे मछली ही पकड़ रहे थे. पास के मछुआरों ने ही लॉर्ड माउंटबेटन को पानी से बाहर निकाला था. ये वही माउंटबेटन थे, जो पराधीन भारत के आखिरी और स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने. उनके समय में ही भारत आजाद हुआ. जिस दिन अंग्रेज भारत को सत्ता सौंपने वाले थे, उस दिन शाम पांच बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेज़ पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था. माउंटबेटन के सलाहकारों को अंदाजा था कि 30 हजार लोग आएंगे, लेकिन वहां 6 लाख लोग आए. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पाए. उन्होंने वहीं से चिल्ला कर नेहरू से कहा, लेट्स होएस्ट द फ़्लैग. मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज़ सुन ली. तिरंगा झंडा फ़्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े-खड़े उसे सैल्यूट किया. लोगों के मुंह से आवाज़ निकली, माउंटबेटन की जय...पंडित माउंटबेटन की जय.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

चेस किलर अलेक्जेंडर पिचुस्की

अलेक्जेंडर पिचुस्की एक ऐसा नाम है, जिसका जिक्र होने पर इंसानियत आज भी थर्रा उठती थी. इसे बित्सा पार्क किलर और चेस किलर के रूप में दुनिया जानती थी. यह एक रूसी सीरियल किलर था. उसने कम से कम 49 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था. ऐसा नहीं कि पिचुस्की शुरू से ही इतना खौफनाक था, बल्कि बचपन में हुए एक हादसे ने पिचुस्की को पूरी तरह बदल दिया था. विशेषज्ञ बताते हैं कि उसके साथ जो हादसा हुआ, उससे उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था. 1992 में अपने छात्र जीवन में ही पिचुस्की ने पहली हत्या कर दी थी. सही मायने में देखा जाए तो पिचुस्की ने 2001 में अपराध की दुनिया में कदम रखा. 15 अक्टूबर, 2005 को पुलिस ने 31 साल के एक व्यक्ति की लाश बरामद की, जिसके सिर पर बेरहमी से वोडका की बोतल मारी गई थी. उस व्यक्ति की हत्या इतनी दर्दनाक थी कि उसे देखकर मॉस्को के लोग भी सहम गये थे. इस हत्या को पिचुस्की ने ही अंजाम दिया था. पिचुस्की मुख्य रूप से बेघर पुरुषों को फुसलाने के लिये मुफ्त वोदका की पेशकश करके उन्हें अपना निशाना बनाता था. उन्हें वोदका पीलाने के बाद वह अपने शिकार को उसी बोतल से सिर पर उस समय तक वार करता, जब तक उसका शिकार मर नहीं जाता. पिचुस्की बेघर पुरुषों के अलावा बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ता था. उसकी सभी वारदातों में हत्या करने का तरीका एक सा था. इतनी हत्याओं को अंजाम देने के बाद मॉस्को की पुलिस ने उसे सीरियल किलर घोषित कर दिया. उसे 16 जून, 2006 को गिरफ्तार किया गया और 24 अक्टूबर 2007 को उसे 49 हत्याओं के आरोप में दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई.■

हे ईश्वर! आप ही की मर्ज़ी से हमने अलग–अलग देशों में जन्म लिया है, अलग–अलग भाषाएं बोलते हैं, और अलग–अलग धर्मों एवं संस्कृतियों से सम्बंधित हैं. हम सभी आप ही की संतान हैं, और अपके प्यार और सुरक्षा के लिए हमेशा आपके आभारी हैं. आप हमारी सोच को पवित्र कर दें और हमारे अन्दर ऐसी भावना पैदा करें ताकि हम हिंसा और नफरत छोड़ कर आपकी सेवा के काबिल बन सकें दुनिया में प्रेम, त्याग और सहयोग की भावना की ज़रुरत है. हमें शिरडी साई बाबा जैसे संतों का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करें, जिन्होंने हिंदी में कहा था कि सब का मालिक एक.

जग-माया में सद्गुरु का स्वरूप

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

श्रद्धा एवं सबूरी–बाबा ने भक्ति का जो मार्ग दिखलाया, वह है–श्रद्धा और सबूरी इन्हीं में ईश्वरीय भक्ति का सार है श्रद्धा का अर्थ है–भक्तिपूर्ण निष्ठा अर्थात अपनो के प्रति ऐसा आस्था भाव जिसमें कि विश्वास में दृढ़ता हो, चित्त में एकाग्रता एवं अनुराग हो और किसी भी परिस्थिति में वह परिवर्तित न हो तथा सुख या दु:ख हर स्थिति में आस्था दृढ़ बनी रहे कि जीवन में सुख या दु:ख ईश्वर की ही देन हैं. इस प्रकार सुख या दु:ख हर परिस्थिति में बाबा को धारण करते है, तो स्थिरता बनी रहती है. गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होने से हर स्थिति में लगता है कि वे हमारे साथ हैं. श्रद्धावान व्यक्ति सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए हर वस्तु को त्यागने की क्षमता रखता है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, वह बाबा के ही पथ पर चलता है तथा दूसरी दिशाओं में नहीं भटकता. भक्ति की परीक्षा विपरीत स्थितियों में होती है. अगर कोई विपरीत स्थितियों में बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर नहीं रख पाता है, तो धैर्य न होने के कारण ऐसी स्थिति में उसका भक्तिभाव भी डगमगा जाएगा. अत: विपरीत स्थितियों में भी उसे धैर्य रखना चाहिए कि बाबा उसके कष्ट को कम करेंगे और उसे विपरीत स्थिति से अवश्य निकालेंगे. धीरज का एक अन्य अर्थ भी है अर्थात जब भी ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार आदि के कारण कोई खराब भाव मन में उत्पन्न हो, तो गुरु को स्मरण करते हुए, सब कुछ सहते हुए किसी प्रकार की कोई शिकायत न करते हुए, बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते रहना ही सबूरी है. आज विश्व भर में लोगों के जीवन में अधिकांश समस्याओं का कारण

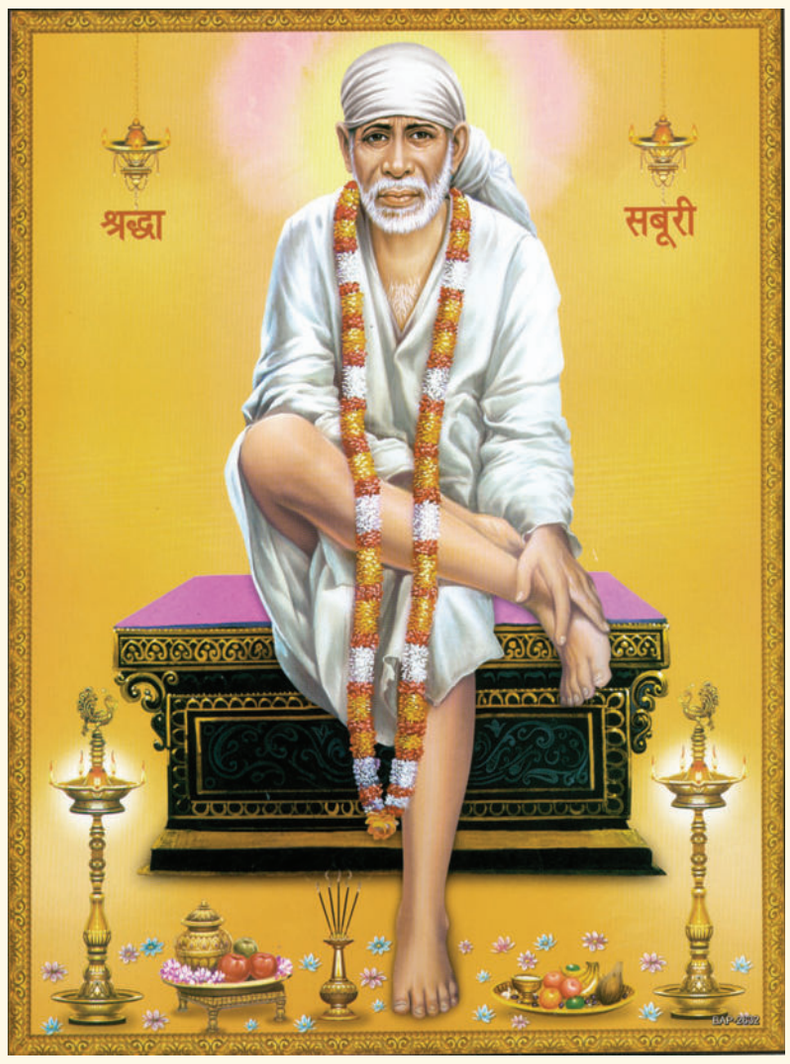

भक्ति की परीक्षा विपरीत स्थितियों में होती है. अगर कोई विपरीत स्थितियों में बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर नहीं रख पाता है, तो धैर्य न होने के कारण ऐसी स्थिति में उसका भक्तिभाव भी डगमगा जाएगा. अत: विपरीत स्थितियों में भी उसे धैर्य रखना चाहिए कि बाबा उसके कष्ट को कम करेंगे और उसे विपरीत स्थिति से अवश्य निकालेंगे.

श्रद्धा एवं सबूरी का अभाव है. जीवन में श्रद्धा एवं सबूरी को धारण करने से जीवन सरल एवं मधुर बन जाता है. इस प्रकार बाबा न केवल आज बल्कि आने वाले समय में और भी प्रासंगिक रहेंगे.

नाम जाप का महत्व

बाबा ने कहा था कि नाम–जाप करो. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था?

संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नानक, कबीर आदि सभी संतो ने कहा था कि नाम लेते रहो. जो कलियुग में कष्ट–साधना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नाम का जप करना सहज और श्रेष्ठ है. नाम लेते रहने से नामी चाहे गुरु इष्ट–का रुप सामने आता है और हमारी चेतना पर छा जाता है. उनका गुण भी मन के आंदोलित करने लगता है. फिर उनकी चेतना शक्ति से भक्त की चेतना शक्ति जुड़ जाती है. इसीलिए अपनी चेतना शक्ति को सद्गुरु से जोड़ कर रखने का जो प्रयास है, वही सरल मार्ग है. पर इसको करना कठिन इसलिए है, क्योंकि दुनिया में रहते की प्रकार के भाव तरंग मन में उत्पन्न होते हैं और चित्त को चंचल कर देती है. जो मन को अखंडित रुप से गुरु–चेतना के साथ मिलाकर चलता है, उनका स्वरूप अर्थात उनके अखंड मडंलाकार रूप को देख सकता है. इसलिए इसे अविच्छिन्न भाव को रखने के लिए(कि वह खंडित या विच्छिन्न न हो) जोगी और संतगण रात को सोते नहीं थे.

जग–माया में सद्गुरु का स्वरुप

मायामय इस जगत में हम सद्गुरु का स्वरुप को कैसे जानें?

यह दृश्यमान जगत, जो माया का रुप है, उसके पीछे ईश्वर सद्गुरु का असली स्वरुप छुपा हुआ है. जब तक कोई व्यक्ति की जन्मों की साधना और गुरु कृपा के कारण इस माया को दूर नहीं करता, तब तक सद्गुरु के स्वरुप को स्पष्ट देख नहीं सकता. सद्गुरु ही माया के खेल द्वारा भक्तों को आकर्षित करके ज्ञान और अज्ञान दोनों का अनुभव कराते हैं. माया को सद्गुरु का एक रुप समझकर बाबा को साथ लिए चलना चाहिए

–श्रद्धा–सबूरी सहित. जैसे–जैसे बाबा की कृपा बढ़ती जाएगी वैसे–वैसे माया का बंधन टूटता जाएगा.

गुरु की आवश्यकता

सद्गुरु के पास जाने का रास्ता कैसा है?

सद्गुरु के पास पहुचने का रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस पर चलते हुए व्यक्ति को किसी भी वक्त सांसारिक हवाएं उड़ा ले जाती हैं और सद्गुरु के सिंद्धात के अनुसार अगर किसी को उनके पथ पर चलना है, तो प्रथम क्रम में कम से कम चार वर्ष तक गुरु–शिष्य–परंपरा का अनुपालन करना होगा. लोग गुरु शष्यि परंपरा के एक प्रतिशत भाग का पालन करना तो दूर रहा, उसे ठीक रूप से समझते तक नहीं हैं. बाबा ने कहा था–अनेक हैं. यहां से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं. किंतु पथ प्रदर्शक अर्थात गुरु यदि साथ हो तो वह सिंह भेड़ियों और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, लेकिन उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है. बिना कोई तर्क–कुतर्क या वाद–विवाद किए श्रद्धा और धैर्यपूर्वक गुरु के उपदेश–पालन से वही कठिन रास्ता सरल बन जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपदा दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

संसद में टकराव देश के लिए घातक है

जब तोप मुकाबिल हो- सत्ता पक्ष और विपक्ष में दूरी चिंतनीय(03 अगस्त-09 अगस्त 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि भारत की राजनीति में एक बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति पिछले 10-12 सालों में बढ़ी है और वह प्रवृत्ति सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में देखी जा रही है. यह प्रवृति आने वाले दिनों और खतरनाक रूप लेगी, जो देश के लिए खतरनाक है और इसी प्रवृति के कारण मानसून सत्र में हमें टकराव देखने को मिला. सरकार और विपक्ष में गतिरोध प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सरकार और विपक्ष दोनों को बातचीत के जरिए गतिरोध को दूर करना चाहिए. संसद चलाना सरकार का काम है, इसलिए सरकार को नरम बरतनी चाहिए. कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लटके पड़े हैं, जिनका देश के हित के लिए संसद में पास होना जरूरी है, लेकिन संसद में गतिरोध के कारण संसदीय कार्य नहीं हो पा रहा है. पहले सरकार और प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करते थे और किसी भी विधयक आम राय बनती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान न कभी विपक्षी पार्टियों तरजीह दिया और अब वही काम एनडीए की सरकार कर रही है, जो देश के लिए ठीक नहीं.

-राममूर्ति राम, शहादरा, दिल्ली.

बेटा-बेटी एक समान

बेटा अगर तन है, तो बेटी मन है.
बेटा अगर मान है, तो बेटी गुमान है.
बेटा अगर बारिश है, तो बेटी पारस है.
बेटा अगर वंश है, तो बेटी अंश है.
बेटा अगर वंश है, तो बेटी अंश है.
बेटा अगर संस्कार है, तो बेटी संस्कृति है.
बेटा अगर आग है, तो बेटी बाग है.
बेटा अगर दवा है, तो बेटी दुआ है.
बेटा अगर भाग्य है, तो बेटी विधाता है.
बेटी लक्ष्मी है, सरस्वती है.
आने वाली कल की जननी है.
उनका सम्मान करो.

-अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

जब आईपीएस बेहाल तो जनता कितनी खुशहाल!

उत्तर प्रदेश आइपीएस अमिताभ ठाकुर और मुलायम सिंह यादव विवाद में पूरी सपा सरकार एक आईपीएस के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, सपा सरकार का आईपीएस अमिताभ के खिलाफ अभियान छेड़ देना, एक ईमानदार आईपीएस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाना और धमकी देना सपा सरकार के चाल-चरित्र और राज्य की जनता और अपने ही आईपीएस अधिकारी के साथ के व्यवहार को दर्शाता है. यह सब देखकर मैं एक आमदी के नाते यह सोचने को विवश हूं कि जब राज्य में एक आईपीएस अधिकारी के साथ सरकार का यह रवैया है, तो समाजवादी सरकार में आम जनता की कितनी सुनी जाती होगी और वो अपने कितना सुरक्षित महसूस करती होगी?

-प्रभु नारायण, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.

एक नारी का दर्द

मैं औरत हूं और मैं कदम-कदम पर, चप्पे-चप्पे पर, हर रास्ते पर, गलियों में खतरों से घिरी हूं. यह मत पूछो मुझसे कि मैं हर जगह किस तरहा बची हूं. आज हमारे देश की यह विडम्बना है कि राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखने का दावा करने वाली हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में असफल है. आए दिन संकीर्ण मानसिकता वाले लोग न जाने कितनी महिलाओं का शौषण करते हैं. जिस देश में नारी को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है उसी देश मे नारी की आबरू को बेआबरु होना पड़ता है. हाल ही में एक महिला आईएएस ने मध्य प्रदेश मानवधिकार आयोग के आयोग मित्र के खिलाफ कथित रुप से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया. ऐसे ना जाने कितने उत्पीड़न, शोषण और बलात्कार से पीड़ित नए मामले देश के विकास से दस गुना अधिक बढ़ते जा रहे हैं. आज 1 साल की बच्ची हो या अस्सी साल की बुढ़िया कोई भी सुरक्षित नहीं है. अब सवाल यह उठता है कि सरकार अपने कुभकरणी नीद से कब जागेगी.

-मानसी बत्तरा, द्वारका, दिल्ली.

सरकार और विपक्ष की महाभारत

यूपीए के शासनकाल में विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भाजपा ने कड़े तेवर अपनाए थे, आज उसी तरह कांग्रेस अपने चंद सांसदों के साथ कड़े तेवर अपना रही है. सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी है. ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापमं घोटाले पर शिवराज चौहान और ललित मोदी मसले को लेकर सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे का अलावा विपक्ष के पास जनता की भलाई और देश के विकास को लेकर ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं जो संसद के भीतर उठा सके. दूसरी तरफ सरकार लाचार नज़र आ रही है, क्योंकि कई अहम बिल संसद में लंबित पड़े हैं और हंगामा के चलते न सरकार उस पर चर्चा करा पा रही है और न ही उसे पास करा पा रही है. मानसूत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ और लगता है कि शीतकालीन सत्र में भी ऐसा ही हंगामा होगा. आम आदमी दिन रात मेहनत कर दो जून की रोटी का जुगाड़ करता है और दूसरी तरफ सांसदों के हंगामे के कारण जनता की मेहनत की कमाई का करोंड़ों रुपये बर्बाद हो गया. आखिर कब तक सरकार और विपक्ष की अहम की लड़ाई में जनता पिसती रहेगी और देश का आर्थिक नुकसान होता रहेगा. ■

-कविता राणा, लक्ष्मीनगर, दिल्ली.

अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय आध्यात्मिक गुरु

चौथी दुनिया ब्यूरो

स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो के धर्म संसद को संबोधित किया था. उस संबोधन ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का गौरवान्वित किया था. स्वामी विवेकानंद के बाद अब आध्यात्मिक विचारक और समाजसेवी डॉ. चन्द्रभानु सतपथी ने उसी स्तर की एक और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि भारत की झोली में डाल दी है. वह भारत के पहले नागरिक और आध्यातमिक विचारक हैं जिन्होंने गैर–सरकारी तौर पर अतिथि चैपलिन (देखिए बॉक्स) के रूप में वाशिंगटन स्थित अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के मौजूदा सत्र का उद्घाटन अपने भाषण से किया. अतिथि चैपलिन के दो सौ साल से पुरानी परम्परा में यह पहला मौक़ा था जब किसी भारतीय नागरिक को यह सम्मान दिया गया. डॉ सतपथी की कोशिशों की सराहना करते हुए प्रतिनधि सभा में सियाटेल राज्य के प्रतिनिधि जिम मैकडरमट ने कहा कि डॉ सतपथी प्रख्यात धार्मिक गुरु हैं, जो मानवता की भलाई और दुनिया में शांति के लिए प्रयासरत हैं.

डॉ. सतपथी अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड समेत कई देशों में भारतीय दर्शन और आध्यात्म का प्रचार–प्रसार कर रहे हैं. इसके अलावा मेडिकल कैंप चलाने, प्राकृतिक आपदा के समय ज़रूरतमंदों के लिए खाना और आवास मुहय्या कराने, ग़रीबों के इलाज प्रायोजित करने और ग़रीबों की शिक्षा के प्रयास जैसे कामों (मुख्य रूप से भारत में) में लगे हुए हैं.

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डॉ सतपथी का संबोधन

ॐ! हे इश्वर! आप ही की मर्ज़ी से हमने अलग–अलग देशों में जन्म लिया है, अलग–अलग भाषाएं बोलते हैं, और अलग–अलग धर्मों एवं संस्कृतियों से सम्बंधित हैं. हम सभी आप ही की संतान हैं, और अपके प्यार और सुरक्षा के लिए हमेशा आपके आभारी हैं. आप हमारी सोच को पवित्र कर दें और हमारे अन्दर ऐसी भावना पैदा करें ताकि हम हिंसा और नफरत छोड़ कर आपकी सेवा के काबिल बन सकें दुनिया में प्रेम, त्याग और सहयोग की भावना की ज़रुरत है. हमें शिरडी साईं बाबा जैसे संतों का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करें, जिन्होंने हिंदी में कहा था कि सब का मालिक एक. हे इश्वर, हम में अपने आसपास की दुनिया की रक्षा और उसकी देखरेख करने की शक्ति प्रदान करें ताकि जीवन को बचाया जा सके. श्रीमद भगवत गीता में निहित आत्म–संयम के नैतिक और समग्र पथ पर चलने और हमारे उद्देश्यों और समर्पण में पवित्रता प्रदान करें. हे इश्वर! अमेरिका के महान संसद और राष्ट्र को मानवता की भलाई के लिए उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारीयों और मानवीय उद्देशों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ!

चैपलिन एवं अतिथि चैपलिन

अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के चैपलिन (पादरी) का पद एक सरकारी ओहदा होता है. चैपलिन का काम आम तौर पर प्रर्थना के साथ प्रतिनिधि सभा के सत्र का उद्घाटन करना होता है. इसके अतिरिक्त चैपलिन धार्मिक मामलों पर सभा के सदस्यों को परामर्श देता है. किसी सदस्य की मृत्यु पर शोक सभा का आयोजन करता है और कांग्रेस की अनुशंसा पर अतिथि चैपलिन को आमंत्रित करता है. यह परम्परा अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता के निति को भी उजागर करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

अनंत विजय

गजेन्द्र तो बहाना है...

पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के चेयरमैन के तौर पर महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका अदा कर अपनी पहचान बना चुके गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति पर विवाद जारी है. संस्थान में काम–काज और पढ़ाई–लिखाई ठप है. गजेन्द्र के विरोधी यह तर्क दे रहे हैं कि चौहान में इस प्रतिष्ठित संस्थान की रहनुमाई करने के लिए अपेक्षित कद और काम नहीं है. यह बात सही है कि गजेन्द्र ने टीवी सीरियल्स के अलावा सी ग्रेड फिल्मों में काम किया है. उनकी उच्च बौद्धिकता को लेकर भी संदेह है. गजेन्द्र चौहान को फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का चेयरमैन बनाने के पीछे सरकार की मंशा के बारे में आगे विस्तार से बात होगी. गजेन्द्र के विरोधियों का एक तर्क है कि जिस संस्थान के चेयरमैन पद को श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, महेश भट्ट, यू आर अनंतमूर्ति जैसे मूर्धन्य लोगों ने सुशोभित किया है, उस पद पर गजेन्द्र कैसे बैठ सकते हैं. ये सही है कि गजेन्द्र चौहान के पास उन लोगों जितना अनुभव और उनके जैसा आभामंडल नहीं है, लेकिन यहां पर यह भी सवाल उठता है कि श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, महेश भट्ट और यू आर अनंतमूर्ति जैसे दिग्गजों ने फिल्म संस्थान के लिए क्या किया? इतने बड़े दिग्गजों के सालों तक इस संस्था के चेयरमैन रहते हुए भी इसका विकास आईआईटी या आईआईएम की तर्ज पर क्यों नहीं हो सका? 1960 में स्थापित इस फिल्म संस्थान के 55 साल हो गए, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिल्म स्कूल के आसपास भी पहुंच पाया? क्या विश्व सिनेमा जगत में इस संस्थान ने अपना स्थान बना पाया? विश्व सिने जगत की बात ही छोड़िए, क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस संस्थान ने दक्षिण एशियाई देशों में अपना स्थान बनाया? क्या सिंगापुर के संस्थान की भी हम बराबरी कर पाए हैं? पिछले 55 साल में क्या हम 55 छात्रों का नाम गिना सकते हैं, जिन्होंने इस संस्थान से पढ़ाई की और सिनेमा को अपनी विधा में प्रभावित किया? क्या हम निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड, म्यूजिक, वीडियो एडिटिंग आदि विधा से चार–चार लोगों का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर लोगों को चौंकाया? साउंड में तो ले–देकर रसूलपुकुट्टी को याद कर सकते हैं. अगर इन सवालों का उत्तर सकारात्मक होता तो हम कह सकते थे कि श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, महेश भट्ट और यू आर अनंतमूर्ति की प्रतिभा का लाभ इस संस्थान को मिला, लेकिन अफसोस

कि इन सवालों का जवाब नकारात्मक है. लिहाजा, इन बौद्धिकों से ये सवाल तो किए ही जाने चाहिए कि आपने इस संस्था के लिए क्या किया? दरअसल, हकीकत यह है कि इन बड़े नामों के पास इस संस्था के लिए वक्त ही नहीं था. श्याम बेनेगल के दौर में फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और चेयरमैन की मुलाकात साल में एक बार हो जाए तो संस्थान में चर्चा का विषय होती थी. एक डायरेक्टर के तौर पर श्याम बेनेगल की प्रतिभा और प्रतिष्ठ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इसी तरह से अदूर गोपालकृष्णन के भी निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. महेश भट्ट और यू आर अनंतमूर्ति पर भी नहीं. दरअसल, अगर हम इन तमाम बड़े लोगों के कार्यकाल का आंकलन करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनमें से ज्यादातर के पास संस्थान के लिए वक्त ही नहीं था. बड़े नाम होने की वजह से इनकी नियुक्ति होती थी और कभी–कभार किसी सभा–संगोष्ठि में इनके दर्शन हो जाया करते थे. भला हो गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति पर उठे विवाद का कि इस संस्थान के क्रियाकलाप पर बहस शुरू हो गई. उनके काम–काज का हिसाब पूछा जाने लगा. इस संस्थान को इन बड़े लोगों से फायदा हुआ हो या नहीं, इनके नाम के साथ ये चस्पा अवश्य हो गया कि ये इस संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. यह जानकार हैरानी होती है कि इस संस्थान में कई छात्र दो हजार आठ से छात्रावासों में रह रहे हैं. यह नए छात्रों के साथ बेईमानी तो है ही, उनके अधिकारों पर डाका भी है. यह संस्थान भारत सरकार के अनुदान पर चलती है, यानी कि इसमें हमारा आपका, सभी करदाताओं का पैसा लगता है. हमारी गाढ़ी कमाई का इतना अपव्यय इतने सालों से हो रहा था और ये तमाम बड़े नाम यहां गद्दीनशीं थे, खामोश थे. यह जानकर तो और हैरानी होती है कि करोड़ों के बजट के बावजूद इस संस्थान के उपकरणों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया. यह तो वैसी ही बात हुई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में कुछ सालों पहले तक लेटर प्रेस और उसकी तकनीक पढ़ाई जाती है. हमारे देश के विश्वविद्यालयों के कई विभाग प्रतिभा के कब्रगाह बने हुए हैं. उसी तरह से एफटीआईआई में भी पुरानी तकनीक और पुराने तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जा रही है. कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा रहे हैं, जिनकी स्क्रिप्ट की वजह से एक मशहूर निर्देशक को झटका लग चुका है.

दरअसल, गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति पर सरकार और वामपंथी विचारधारा के लोगों की टकराव की वजह एकदम से अलहदा है. इसके राजनीतिक कारण हैं. आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है. इस सरकार का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं, जिनके विचार अटल बिहारी वाजपेयी से मेल खा सकते हैं, लेकिन मिजाज नहीं. अटल बिहारी वाजपेयी इस मामले में थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी विचारधारा को लेकर सजग ही नहीं हैं, बल्कि उसको स्थापित करने के लिए मजबूती के साथ प्रयत्नशील भी हैं. इस बार सरकार ने तय किया है कि सभी संस्थानों पर अपने लोग बिठाए जाएं. अब इन्हीं अपने लोगों को बिठाने की प्रक्रिया में गजेन्द्र चौहान जैसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं. अभी आनेवाले दिनों में इस तरह की और नियुक्तियां होंगी. विश्वविद्यालय के कुलपतियों से लेकर भाषा, कला और सांस्कृतिक संगठनों तक में. यह सच है कि बौद्धिक जगत में वामपंथी विचारधारा की तुलना में दक्षिणपंथी विचारधारा में विद्वानों की संख्या कम है, लेकिन जो हैं, उसके आधार पर ही सबकुछ अपने माफिक करने की कोशिश हो रही है और आगे भी होती रही है. हम देखें तो दक्षिणपंथी विद्वानों की संख्या इस वजह से कम नजर आती है कि आजादी के पैंसठ साल बाद तक उनको अवसर से वंचित किया जाता रहा, जो भी राष्ट्रवादी बातें करता, या राष्ट्रवादी विषयों पर शोध करता या जो भी वामपंथ से अलग हटकर भारत और भारतीयता की बात करता, उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता रहा है. न तो विश्वविद्यालयों में उनकी नियुक्ति हो पाती थी और न ही किसी शोध संस्थान में उनको शोध करने दिया जाता था. ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां वामपंथ से इतर सोच रखनेवाले छात्रों और शोधार्थियों को बेवजह तंग किया गया हो और उनको समान अवसर से वंचित रखा गया हो. इस तरह की बौद्धिक अस्पृश्यता ने वामपंथ से इतर विचार रखनेवालों को हतोत्साहित किया. गजेन्द्र के मसले पर जारी संघर्ष का वृहत्तर अर्थ है. वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को यह लगने लगा है कि ये सरकार आनेवाले दिनों में उनके सांस्कृतिक साम्राज्य को खत्म कर देगी. लिहाजा, वो भी आक्रामक हो गई है. गजेन्द्र तो एक बहाना मात्र है, जिसकी आड़ में वामपंथी अपने खत्म होते साम्राज्य को बचाने की जुगत में हैं. दूसरी वजह यह है कि उनको यह भी लगने लगा है कि अगर उनकी विचारधारा के लोग सत्तानशीं नहीं रहे तो उनके कारनामे खुलेंगे. जैसे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में सत्ता परिवर्तन के बाद यह बात सामने आने लगी है कि किस तरह से करदाताओं के पैसों की लूट चल रही थी और एक एक प्रोजेक्ट चार दशक से अधिक वक्त से अर्थात् तैंतालीस साल से एक ही व्यक्ति कर रहा था. इस तरह के खुलासों से बचने केलिए गजेन्द्र जैसी नियुक्तियों पर विवाद खड़े होते रहेंगे. नियुक्तियों की आड़ में खेले जा रहे इस खेल में छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन हाल के अनुभवों को देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार इस मसले पर अपना कदम पीछे खींचनेवाली नहीं है. यह राजनीतिक लड़ाई है और उसी के औजारों से लड़ी भी जा रही है. राजनीति के इस खेल में यथास्थितिवाद को चुनौती देने से विरोध का बवंडर उठेगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उस बवंडर को किस तरह से शांत कर अपनी विचारधारा को स्थापित करती है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

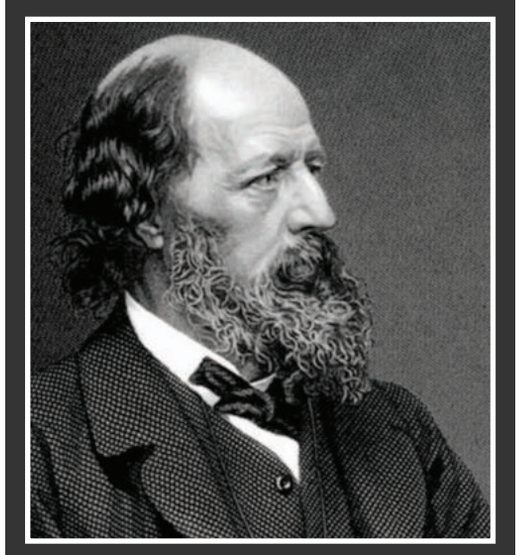

विक्टोरियाई युग के कवि लॉर्ड एल्फ्रेड टेन्निसन को अंग्रेजी साहित्य के बेहतरीन कवियों में शुमार किया जाता है. उनकी कृति इन मेमोरियम सर्वकालिक महान कृतियों में शामिल की जाती है. वे कविताओं में मानवीय संवेदनाओं को उभारने के लिए जाने जाते थे.

नई किताब

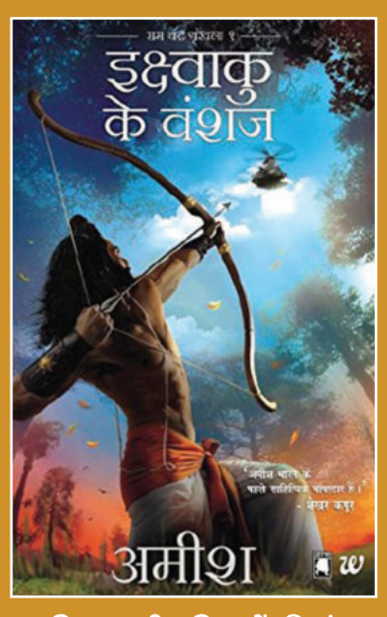

भगवान शिव पर तीन किताबों की श्रृंखला की ख्याति के बाद लेखक अमीश त्रिपाठी अपनी नई किताब इक्ष्वाकू के वंशज के साथ फिर आए हैं. यह किताब भगवान राम पर आधारित है.

यथार्थ और सौंदर्य के बीच की ग़ज़लें

कुमार कृष्णन

समकालीन हिंदी ग़ज़ल आज जिस भाव और कथ्य को लेकर आगे बढ़ रही है, वह हिंदी कविता के लिए उत्साहवर्द्धक है. हिंदी में ग़ज़ल के प्रवेश से हिंदी कविता पठनीयता के जिस संकट से जूझ रही थी, उसे तोड़ने में हिंदी ग़ज़ल को काफी हद तक सफलता मिली है. हिंदी ग़ज़ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह आत्ममुग्धता और दंभ से ग्रसित नहीं है और पाठकों की बात उनसे उन्हीं की ज़ुबान में करती है. यदि उसका कथ्य गंभीरता से देखें, तो उसमें न उपदेश है और न शब्दों का इंद्रजाल. यही वजह है कि पाठकों ने उसका हिंदी साहित्य में तहेदिल से स्वागत किया है. जहां तक छंद और सौंदर्य की बात है, यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि उर्दू में लिखी जा रही ग़ज़लों से वह कहीं से कम नहीं है.

समकालीन ग़ज़लकारों की बात की जाए, तो हिंदी में बहुत सारे ग़ज़लकार गंभीरता से काम कर रहे हैं. उन्हीं ग़ज़लकारों की सूची में भावना का नाम काफी प्रमुखता के साथ सामने आता है. उनका दूसरा ग़ज़ल संग्रह–शब्दों की क़ीमत हाल में अंतिका प्रकाशन से छपकर पाठकों के समक्ष आया है, जिसमें 87 ग़ज़लें हैं, जो विभिन्न भाव–भूमि के तथ्यों के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं. संग्रह की ग़ज़लें देखने के बाद यह सहज ही प्रतीत होता है कि भावना का ग़ज़ल लेखन यथार्थ और सौंदर्य की परिक्रमा करता है. उनकी ग़ज़लें एक ओर जहां पूरी तल्लीनता के साथ समकालीन यथार्थ की विवेचना करती हैं, वहीं दूसरी ओर कहन के सौंदर्य को भी अपने भीतर बांधे रहती हैं, जो ग़ज़ल लेखन की अपनी खूबसूरती है. मिसाल देखिए:

हर शै की लगी हुई दुकान आजकल,
बिकती है टीवी शो में भी मुस्कान आजकल.
जो दिख रहा है वह कभी होता न दरअसल,
हंसते लबों में बंद है तूफान आजकल.
++++++++
इस जमीं से आसमां तक इक हवा चलती रही,
और पर्दे में हमारी ज़िंदगी ढलती रही.
ओढ़कर रातों की चादर नींद में मंजर रहे,
ख्वाब में तस्वीर उसकी आंखों में पलती रही.

पहले दो शेर देखने से साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे सहज कथ्य के साथ ही अंतर्कथ्य भी लिए हुए हैं. भावना ने अपने शेरों में जीवन और आधुनिकता के बीच एक रेखाचित्र खींचने का सफल प्रयास किया है, जिसके अंदर आज का पूरा समाज छटपटा रहा है. आदमी और आदमी की आदमियत चौराहे पर खड़ी होकर अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है. आदमी का अपना अहं जैसे खो–सा गया है, जिसे उत्तर आधुनिकता और बाज़ार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है. यही कारण है कि ग़ज़लकार भावना को कहना पड़ा कि आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि मुस्कान बाज़ार में मिलने लगी है. यहां मुस्कान का तात्पर्य संतोष और आत्म–संतोष से है. असल में मुस्कान बाज़ार का एक कारण है और व्यक्तित्व ह्रास का एक मजबूत स्तंभ भी, जिससे आदमी रोज टकरा–टकरा कर लहूलुहान हो रहा है.

समीक्ष्य कृति : शब्दों की क़ीमत (ग़ज़ल संग्रह)
ग़ज़लकार : भावना
प्रकाशक : अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद

रही बात उनकी ग़ज़लों में सौंदर्य बोध की, तो ग़ज़ल की कलात्मकता और नए–नए आयामों के संप्रेषण के बीच भावना ने अपनी ग़ज़लों को प्रेम–बिंदु पर लाकर खड़ा तो किया है, लेकिन उस प्रेम–बिंदु पर सिर्फ़ देह–आकर्षण नहीं, बल्कि घर, परिवार, समाज एवं प्रकृति की भीनी–भीनी सुगंध भी मिलती है. उन्होंने ख्वाब, नींद और मंजर जैसे शब्दों में कल्पनाशीलता के नए–नए रंग बिखेरे हैं. ख्वाब जहां कल्पना है, नींद जहां स्वाभाविक है, मंजर जहां सौंदर्य है, जिन्हें पारदर्शी अनुभवों के साथ देखा जा सकता है. भावना का प्रेम काफी ऊंचाई पर है, जो मन का भेद, मन का रहस्य तुरंत–तुरंत बताने से संकोच करता है. संग्रह में कई ऐसे शेर हैं, जो ग़ज़लकार भावना को काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं:

हमारे घर का कोना जानता है,
जो ख़ामोशी से रोना जानता है,
वो मन का मैल हो या धूल तन की,
सफाई से धोना जानता है.
++++++++
दाने से मछलियों को लुभाता रहा,
क्या हक़ीकत थी, क्या वह दिखाता रहा,
था अजब उसके कहने का अंदाज़ भी,
कुछ बताता रहा, कुछ छुपाता रहा.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संग्रह की सभी ग़ज़लें पठनीय हैं और हिंदी ग़ज़ल को एक नई ऊंचाई देने में सफल हुई हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

अभिलाषा

निर्मल पावन कोमल शीतल,
कैसा है स्पर्श तुम्हारा.
तन–मन की कैसी पीड़ा हो,
हर लेता है प्यार तुम्हारा.

जब भी जीवन में थकता हूं,
तेज धूप में मैं तपता हूं.
जीवन का हर ताप मिटाता
आंचल का इक सार तुम्हारा .

मुझे खिला तुम भूखे रहती,
ढाल बनी सब सुख दुःख सहती.
शब्दों में ना कह पाउंगा,
अकथनीय है प्यार तुम्हारा .

बचपन में जब बाल खींचकर ,
जब–जब मैंने तुमको मारा .
तब–तब तुमने शीश चूमकर ,
जाने तुमने कितना दुलारा .
कैसे भूल सकूंगा मां मैं,
निश्छल वो दुलार तुम्हारा .

मन में अब अभिलाषा एक,
चाहे मिले जन्म अनेक .
गोद तुम्हारी, प्यार तुम्हारा,
आंचल का हो सार तुम्हारा . ■

दीपक चौबे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनकी कई कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कर्नाटक में पहाड़ों के किनारे बसा मादिकेरी बेहद खूबसूरत है. धुंध में छिपे पहाड़, ठंडी हवाएं, हरी-हरी घाटियां, कॉफी बागान और प्रकृति के लुभावने दृश्य मादिकेरी को यादगार पर्यटन स्थल बनाते हैं. मादिकेरी को इलायची, काली मिर्च, शहद और मनमोहक सुगंध वाले फूलों के लिए भी जाना जाता है. इस पर्यटन स्थल और उसके आस-पास बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें भी हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ओंकारेश्वर मंदिर, अब्बे झरना, मादिकेरी किला, राजा की सीट, भागमंडल, नगरहोले राष्ट्रीय पार्क, इरप्पु झरना, तालकावेरी, हरंगी बांध, नल्कनाद महल, मंडलपट्टी हिल्स, दुबारे फॉरेस्ट, बयलाकुप्पे गोल्डन टेम्पल, और ब्रह्मगिरी वाइल्डलाइफ सेंचुअरी.

टोयोटा इटियोस का एक्सक्लूसिव एडिशन लॉन्च

टोयोटा इंडिया ने इटियोस का एक्सक्लूसिव एडिशन लॉन्च किया है. इस कार में कई इंटीरियर और कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है. अगर बाहरी बनावट की बात करें, तो इटियोस एक्सक्लूसिव में क्रोम फिनिस्ड विंग मिरर, नया ब्लू मेटेलिक पेंट स्कीम और एक्सक्लूसिव बैज शामिल है. हालांकि गाड़ी के केबिन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वुड ग्रेन फिनिस्ड उपकरण पैनल, डोर आर्म रेस्ट और ड्यूल टोन फैब्रिक सीट शामिल है. नई गाड़ी टॉप-एंड वीएक्स ट्रिम पर बेस है. इस नए मॉडल में एक नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन सपोर्टेड नेविगेशन सिस्टम, वॉयस फंक्शन और जेस्चर कंट्रोल की सुविधा है. कंपनी ने कहा कि ग्राहकों की लाइफ स्टाइल रोज़ाना बदल रही है, ऐसे में हमने इटियोस एक्सक्लूसिव को लॉन्च किया है. उम्मीद है कि ये कार ग्राहकों को पसंद आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशल एडिशन है. इसलिए इस कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस कार में भी 1.4 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन लगाया गया है. दिल्ली में इसके पेट्रोल वैरिएंट की कीमत 7.82 लाख रुपये रखी गई है. डीज़ल वेरिएंट की कीमत 8.93 लाख रुपये है. ■

ओपो ने लॉन्च किया मिड रेंज स्मार्टफोन

ओपो ने अपने नए स्मार्टफोन को पेश किया है. कंपनी ने मिरर 5 को डायमंड फिनिश के साथ भारतीय बाजार में उतारा है. इस फोन की खास बात यह है कि इसकी बैक बॉडी को डायमंड जैसी फिनिशिंग दी गई है. इसके अलावा फोन के फीचर्स की बात की जाए तो कंपनी ने मिरर 5 हैंडसेट में 16 जीबी मेमोरी दी है. इसे माइक्रो एसडी स्लॉट की मदद से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. कैमरा फीचर की बात करें, तो इस फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह ड्यूल सिम सपोर्ट करता है. इसमें एंड्रॉयड का 5.1 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. ओपो मिरर 5 स्मार्टफोन में 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है. यह हैंडसेट 2 जीबी रैम के साथ आता है. ओपो के इस फोन की कीमत 15,990 रुपये है. ■

अब बोलकर करें ट्रांसलेट

माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए एक खास ट्रांसलेटर ऐप बनाया है, जो 50 भाषाओं का अनुवाद करेगा. यह ऐप ऐंड्रॉयड और आईओएस के साथ एप्पल वॉच और स्मार्ट वॉच के साथ भी काम करेगा. इस ट्रांसलेटर ऐप की मदद से बोल कर भी अनुवाद किया जा सकता है. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अपनी वेबसाइट बिंग, विंडोज फोन,स्काइप और डेस्कटॉप ट्रांसलेटर के जरिए भी यह सुविधा देता रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐप गूगल को कड़ी टक्कर देगा. गूगल अभी अपने ट्रांसलेटर ऐप में सिर्फ 27 भाषाओं में ही अनुवाद की सुविधा देता है. वहीं माइक्रोसॉफ्ट का यह ऐप 50 भाषाओं का अनुवाद कर सकता है. इस ऐप की एक और खासियत यह है कि यह अनुवाद का उच्चारण भी करता है. ■

सैर-सपाटा

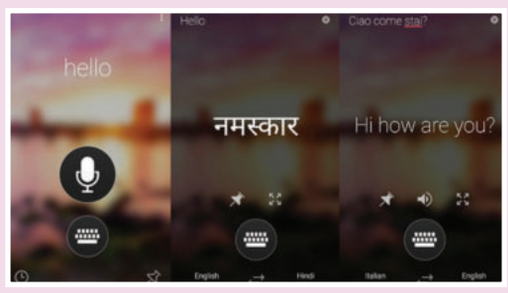

भारत का स्कॉटलैंड मादिकेरी

देश में सबसे तेजी से उभरते टूरिस्ट डेस्टिनेशन कर्नाटक के कुर्ग का नाम तो आपने सुना होगा, पर इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह का नाम आपने शायद ही सुना हो. यह जगह है कुर्ग का हेडक्वॉर्टर मादिकेरी. कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया मादिकेरी की वजह से ही कहा जाता है. देश में सबसे तेजी से उभरते टूरिस्ट डेस्टिनेशन का यह सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है. पहाड़ों के किनारे बसा मादिकेरी बेहद खूबसूरत है. यहां की धुंध में छिपे पहाड़, ठंडी हवाएं, हरी-हरी घाटियां, कॉफी के बागान और प्रकृति के लुभावने दृश्य मादिकेरी को यादगार पर्यटन स्थल बनाते हैं. मादिकेरी को इलायची, काली मिर्च, शहद और मनमोहक सुगंध वाले फूलों के लिए भी जाना जाता है. मादिकेरी में और उसके आस-पास बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें भी हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ओंकारेश्वर मंदिर, अब्बे झरना, मादिकेरी किला, राजा की सीट, भागमंडल, नगरहोले राष्ट्रीय पार्क, इरप्पु झरना, तालकावेरी, हरंगी बांध, नल्कनाद महल, मंडलपट्टी हिल्स, दुबारे फॉरेस्ट, बयलाकुप्पे गोल्डन टेम्पल, और ब्रह्मगिरी वाइल्डलाइफ सेंचुअरी. मादिकेरी दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती मन को मोह लेती है. मादिकेरी का वातावरण, घाटियां, विलक्षण गांव, रंगीन दृश्य, मनमोहक खुश्बू, शांत पर्यावरण, नदियां, पशु-पक्षी, घने जंगल और झरनों से गिरता मोतियों सा पानी स्वर्ग का एहसास दिलाता है. अगर आप अपनी छुट्टियां साउथ इंडिया में बिताने की सोच रहे हैं तो मादिकेरी जाना न भूलें. मादिकेरी जाने के लिए सबसे अच्छा समय है सितंबर से मार्च के बीच.

कैसे जाएं : मादिकेरी मैंगलोर से 135 किलोमीटर दूर है. मादिकेरी जाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलोर है. मैसूर से मादिकेरी की दूरी 120 किलोमीटर है. आप मैसूर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं. मादिकेरी के लिए बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर से नियमित बस सेवाएं और टैक्सी भी उपलब्ध हैं. ■

खाना पीना

बच्चों को भाए बाल मिठाई

कविता राणा

खोये से यह मिठाई बनाई जाती है. इसका स्वाद चॉकलेट जैसा होता है. इसमें जो बाल लगी होती है, उसकी मिठास के क्या कहने. बाल मिठाई अल्मोड़ा में बनती है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि पूरे उत्तराखंड में है. चॉकलेट से भरी और सफेद मीठी खस-खस की गोलियों से सजी बाल मिठाई देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है. यह मिठाई भूने हुए खोये से बनाई जाती है और इसका रंग चॉकलेट की तरह भूरा होता है. उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की यह सबसे प्रसिद्ध मिठाई है. पहाड़ों की बाल मिठाई से जुड़ी न जाने कितनी कुमाऊंनी कहानियां हैं, जिसके बारे में यहां के स्थानीय लोग आज भी बताते हैं. अल्मोड़ा के बाज़ार में कदम रखते ही आप तक बाल मिठाई की सुगंध पहुंच जाएगी. कहा जाता है कि अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई के जन्मदाता हलवाई जोगा लाल शाह हैं. सर्वप्रथम उन्होंने ही बाल मिठाई को बनाना शुरू किया था. जोगालाल शाह हलवाई सबसे पहले इस तरह की मिठाई किसी नजदीकी गांव से दूध लेकर बनाया करते थे. वे मिठाई के ऊपर पोस्ता यानी खस-खस के दाने चीनी में भीगोकर लगाते थे. उसके बाद रौतेला बंधुओं ने उन्नत रूप में यह काम शुरू किया. अल्मोड़ा नगर में आज भी कई व्यवसायी हैं, जिन्होंने परंपरागत रूप से तैयार की जाने वाली इस मिठाई की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया. ये व्यवसायी आज भी पहाड़ी खोये से ही मिठाई बनाते हैं. बाल मिठाई की लोकप्रियता और स्थानीय विशेषता के कारण लोग एक-दूसरे के यहां आने-जाने पर उपहार के रूप में बाल मिठाई ही ले जाते हैं ■

बनाने की विधि

सामग्री :

चीनी -400 ग्राम
चीनी के सफ़ेद दाने -100 ग्राम
खोया (मावा)-एक किलो

विधि :

1. खोये को धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक ये भूरे रंग का न हो जाये.
2. अब इसमें चीनी डाल कर गाढ़ा होने तक इसे पकायें.
3. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाये तो एक थाली पर चिकनाई लगा कर मिश्रण फैला दें.
4. मिश्रण को ठंडा कर के चौकोर आकार में काट लें.
5. अब टुकड़ों को चीनी के दानों में लपेटें.
6. बाल मिठाई तैयार है.

मुकाम

गूगल के पहले भारतीय सीईओ बने सुंदर पिचाई

तमिलनाडु में जन्मे सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से पासआउट हैं. सुंदर को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक गूगल के नए सीईओ बनाए गए हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के पद्म शेषाद्रि बाल भवन (पीएसबीबी) स्कूल में हुई. बचपन से ही सुंदर काफी प्रतिभाशाली छात्र थे. सुंदर पिचाई का बचपन दो कमरों वाले घर में गुजरा, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे. उस वक्त न तो उनके पास टीवी था, न टेलीफोन और न ही कार. सुंदर पढ़ाई में अच्छे थे, जिसका फायदा उन्हें मिला. उन्हें आईआईटी खड़गपुर में विशेष सीट मिली. यहां से इंजीनियरिंग करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चले गए. हालांकि उस वक्त उनके घर की माली हालत इतनी खराब थी कि सुंदर की हवाई यात्रा के लिए उनके पिता को कर्ज लेना पड़ा था. सुंदर पिचाई की पहचान एक अच्छे शख्स के रूप में होती है. पिचाई ने 2004 में गूगल कंपनी ज्वॉइन की थी और 11 साल से वे यहीं काम कर रहे हैं. सुंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (एंड्रॉयड, क्रोम और ऐप्स डिवीजन) रह चुके हैं. पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गूगल का सीनियर वीपी (प्रोडक्ट चीफ) बनाया गया था. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फैशन दुनिया

फैशन का रंग देश के महानगरों में ही सीमित नहीं है, इसका दायरा अब छोटे शहरों में भी फैलता जा रहा है. असम के डिब्रूगढ़ में भी हाल में फैशन के रंगों की चमक दिखाई दी. डिब्रूगढ़ में संपन्न हुए फैशन शो के दौरान मॉडल्स ने विभिन्न तरह के परिधान पहनकर रैंप पर वॉक किया.

रूट बने नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज

पहले टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में रूट तीसरे नंबर पर थे. स्मिथ अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स दूसरे स्थान पर बरकरार हैं. भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली दसवें नंबर पर हैं और विराट टॉप टेन में एकमात्र भारतीय भी हैं.

एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. एशेज सीरीज में दो शतक, दो अर्द्धशतक और 73.83 की औसत की मदद से 443 रन बना चुके इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पछाड़कर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंच गए हैं. रूट इससे पहले टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे. स्मिथ अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स दूसरे स्थान पर बरकरार हैं. भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली दसवें नंबर पर हैं और टॉप टेन में एकमात्र भारतीय भी हैं.

टेंटब्रिज में जीत के साथ ही एलिस्टेयर कुक ने भी एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की. वह डब्ल्यू जी ग्रेस और माइक ब्रेयरली के बाद इंग्लैंड के तीसरे ऐसे कप्तान बन गये हैं, जिन्होंने दो बार घरेलू सरजमीं पर एशेज जीती.

इतना ही नहीं, गेंदबाजी रैंकिंग में स्टुअर्ट ब्रॉड अपने करियर की सर्वोच्च दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गये हैं. ब्रॉड ने पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टेंट बाउल्स, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को नीचे करते हुए अपनी रैंकिंग सुधारी. ब्रॉड ने एशेज सीरीज में अच्छे प्रदर्शन से फ्रेड टरूमैन के 307 विकेट की संख्या को पीछे छोड़ा. ब्रॉड के नाम पर अब 83 मैचों में 308 विकेट दर्ज हैं. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन गेंदबाजी तालिका में शीर्ष पर हैं. ■

टेस्ट क्रिकेट में टॉप 10 बल्लेबाज

1. जो रूट (917 अंक)
2. एबी डिविलियर्स (839 अंक)
3. स्टीवन स्मिथ (806 अंक)
4. हाशिम अलमा (798 अंक)
5. कुमार संगकारा (790 अंक)
6. एंजेलो मैथ्यूज (781 अंक)
7. यूनिस खान (765 अंक)
8. केन विलियमसन (739 अंक)
9. क्रिस रोजर्स (723 अंक)
10. विराट कोहली (720 अंक)

तैराकी चैंपियनशिप

फेलेप्स 100 मीटर बटरफ्लाई के विजेता बने

माइकल फेलेप्स ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही रियो ओलंपिक 2016 के अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी को भी करारा जवाब दिया. ओलंपिक में 22 पदक जीतने वाले फेलेप्स ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तीसरे दिन 50.45 सेकेंड के साथ 100 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के चाड ले क्लोस को मात दी. क्लोस ने रूस के कजान में चल रही विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर बटरफ्लाई में 50.56 सेकेंड का समय निकाल कर स्वर्ण पदक जीता था. ■

भारत फीफा रैंकिंग में 156 वें स्थान पर

भारतीय फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग में 156वें स्थान पर बरकरार है. रैंकिंग में अर्जेंटीना अभी भी टॉप पर है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी तीन पायदान गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई है. वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम दूसरे स्थान पर, कोलंबिया चौथे, ब्राजील पांचवें, पुर्तगाल छठे और रोमानिया सातवें स्थान पर हैं. भारत 2018 वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर में ओमान और गुआम से हारकर रैंकिंग में 15 पायदान गिर गया था. भारत के किर्गिस्तान के समान 160 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान 171वें स्थान पर है.■

साई में सहायक कोच बनेंगी रानी

रानी भारतीय टीम की फॉरवर्ड प्लेयर हैं और उन्होंने द्रोणाचार्य अवॉर्डी बलदेव सिंह की हरियाणा स्थित शाहबाद अकादमी से अपने खेल को निखारा था.

भारतीय हॉकी टीम की फॉरवर्ड प्लेयर रानी रामपाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) में सहायक कोच बनेंगी. साई ने उनके बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए भर्ती के अपने नियमों में भी छूट दी है. रानी भारतीय टीम की फॉरवर्ड प्लेयर हैं और उन्होंने द्रोणाचार्य अवॉर्डी बलदेव सिंह की हरियाणा स्थित शाहबाद अकादमी से अपने खेल को निखारा था. हरियाणा की रहने वाली रानी ने पहली बार तब सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जब वह 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कप 2010 में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनी थीं. इससे एक साल पहले उन्होंने रूस के कजान में चैंपियन्स चैलेंज टूर्नामेंट में चार गोल करके भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें तब टूर्नामेंट की युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था.■

भुला न पाएंगे...

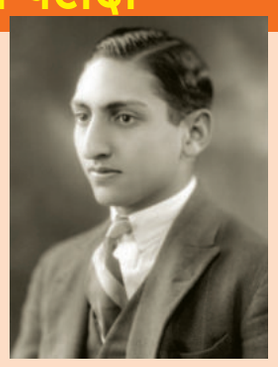

नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी

इफ्तिखार अली खान एक बेहतरीन खिलाड़ी थे. उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से भी टेस्ट खेला और आगे चलकर भारत की भी नुमाइंदगी की. उन्होंने अपने जीवन का पहला मैच 2 दिसंबर, 1932 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला. उस समय वह इग्लैंड टीम का हिस्सा थे. उन्होंने आखिरी मैच 20 अगस्त, 1946 को खेला, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस समय वह भारतीय टीम का हिस्सा थे. आज तक इतिहास में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, जिसने दो देशों की टीम के साथ खेला हो. उन्हें सबसे पहले 1932-33 में एशेज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के लिए चुना गया था. इंग्लैंड ने यह मैच 10 विकेट से जीता. सिडनी में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में इफ्तिखार अली खान ने शतक बनाया. उन्होंने अपने जीवन में 6 टेस्ट मैच और 127 प्रथम श्रेणी मैच खेले.

टेस्ट मैच में उन्होंने 199 रन बनाए, जबकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 8,870 रन बनाए. टेस्ट मैच में उन्होंने 19.90 की औसत से और प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 48.61 की औसत से रन बनाए. अपने करियर में उन्होंने टेस्ट मैच में एक शतक और प्रथम श्रेणी में 29 शतक और 34 अर्धशतक लगाए. टेस्ट मैच में उनका उच्चतम स्कोर 102 रहा और प्रथम श्रेणी में 238 रन नाबाद रहा था.■

कीर्तिमान...

उसैन बोल्ट

100 मीटर: 9.58 सेकंड (बर्लिन 2009)
150 मीटर: 14.35 सेकंड (मैनचेस्टर 2009)
200 मीटर: 19.19 सेकंड (बर्लिन 2009)
300 मीटर: 30.97 सेकंड (ओस्त्रवा 2010)
400 मीटर: 45.28 सेकंड (किंग्सटन 2007)

एक खेल ऐसा भी...

पानी में कुश्ती

एक्वाथलोन को पानी में कुश्ती के रूप में जाना जाता है. इस खेल में दो प्रतियोगी भाग लेते हैं. भाग लेने वाले दोनों प्रतियोगी मास्क पहन कर पानी के नीचे लड़ाई करते हैं. इसमें 5 मीटर का स्वीमिंग पूल होता है. इसमें दोनों खिलाड़ियों के हाथों में बैंड बांध दिया जाता है. दोनों के पास 30 सेकंड का समय होता है. 30 सेकंड के भीतर ही प्रतियोगियों को यह मुकाबला जीतना पड़ता है. इस खेल में कुल 3 पड़ाव होते हैं. अगर तीनों दौर टाई हो जाते हैं तो फिर एक और अर्थात चौथा दौर खेलना पड़ता है. यह खेल 2 मीटर (6.6 फुट) और 6 मीटर (20 फुट) के बीच एक पानी की गहराई के साथ एक स्वीमिंग पूल में आयोजित किया जाता है. इसके लिए प्रतियोगी को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि यह ताकत और पैंतरों का खेल है. एक खिलाड़ी अपने प्रतियोगी को दांव-पेंच से हराने की भरपूर कोशिश करता है. यह खेल पूर्व सोवियत संघ में 1980 के दशक के दौरान आरंभ हुआ.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इंटरव्यू

चित्रांशी ने कॉमेडी की दुनिया में रखा क़दम

फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का किरदार निभाने वाली चित्रांशी अब हास्य भूमिका में भी हाथ आजमाने जा रही हैं. उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया कि यह एक पारिवारिक फिल्म है. इसके संवाद आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे. उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म हास्य संवादों से भरी है लेकिन आपको कहीं भी फूहड़ता जैसी कोई बात नहीं महसूस होगी. यह फिल्म की विशेषता है.

स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर चित्रांशी रावत ने बड़े परदे पर भी हॉकी खेलकर ही अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की. उन्होंने फिल्म चक दे इंडिया में हरियाणा की तेज़-तर्रार हॉकी प्लेयर कोमल चौटाला का किरदार निभा कर फ़िल्मी दुनिया में अपना कदम रखा. उनकी पहली ही फिल्म ने कई लोगों को उनके अभिनय का कायल बना दिया. कामयाबी का पता इसी बात से चलता है की आज भी कई लोग चित्रांशी को कोमल के नाम से बुलाते हैं. चक दे के बाद फैशन, लक, तेरे नाल लव हो गया जैसी हिट फिल्में कर चुकी चित्रांशी अब नज़र आने वाली हैं फिल्म हो गया दिमाग का दही में. इस फिल्म से वो कॉमेडी की दुनिया में कदम रख रही हैं. फौज़िया अर्शी द्वारा निर्देशित, डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड के बैनर तले बनी ये कॉमेडी फिल्म चित्रांशी के लिए काफी ख़ास है. वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म के ज़रिये उन्हें अपने पसंदीदा कलाकारों कादर खान, ओम पुरी और राजपाल यादव के साथ काम करने का मौका मिला है.

एफ.एम रेनबो को फिल्म के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कादर खान जी के साथ मैं काम कर पाउंगी लेकिन फिल्म हो गया दिमाग का दही में यह संभव हुआ. मैं कादर खान और राजपाल यादव जैसे अपने प्रिय कलाकारों के साथ नजर आउंगी. उन्होंने बताया कादर खान के साथ यह मेरी पहली फिल्म है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. वे बहुत महान कलाकार हैं. मैं बचपन से उनकी फिल्में देखती आई हूं और उनकी अदाकारी की बचपन से ही बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं.

इंटरव्यू में अपने पहले प्यार हॉकी और अभिनय में से क्या मुश्किल लगता है पूछे जाने पर चित्रांशी ने बड़े सहज भाव में कहा, हॉकी की तरह ही अभिनय में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियों के लिए तैयार करना पड़ता है. उनका कहना है, क्योंकि कैमरे के आगे सिर्फ एक चीज नजर आती है इसलिए उसके पीछे जो हम लोग तैयारी करते हैं, वह किसी को नहीं दिखती. यह तैयारी आपसे बहुत कुछ लेती भी है और आपको बहुत कुछ देती भी है.

फिल्म हो गया दिमाग का दही में फौज़िया अर्शी द्वारा काम करने का ऑफर मिलने को चित्रांशी अपने और फौज़िया अर्शी के पुराने रिश्ते और फौज़िया द्वारा उनके अभिनय को पसंद करने का परिणाम बताती हैं. उन्होंने बताया कि फौज़िया ने उनसे कहा था कि मुझे आपकी अदाकारी बहुत पसंद है और मैं आपसे वादा करती हूं, जब भी मैं कोई फिल्म बनाउंगी तो आपको जरूर लूंगी, जिस पर चित्रांशी ने कहा था कि आप जब भी बुलाएंगी तो मैं आ जाउंगी.

फिल्म हो गया दिमाग का दही के बारे में उन्होंने कहा ये एक प्लेन और सिंपल कॉमेडी ड्रामा है. यह ऐसी फिल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यह फिल्म लिखी गई है, आजकल उस टाइप की फिल्में नहीं लिखी जाती हैं. इस फिल्म के संवाद बहुत ही अलग टाइप के हैं. फिल्म का फ्लेवर अलग है. चित्रांशी को इस नए अंदाज़ में कॉमेडी करते देखने का इंतज़ार सभी को रहेगा. उनकी फिल्म हो गया दिमाग का दही 25 सितंबर को रिलीज हो रही है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

कादर खान की फिल्मों में वापसी अमिताभ ने किया स्वागत

सदी के महान कलाकार अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी के बादशाह कादर खान की फिल्मों में वापसी का स्वागत किया है. अमिताभ ने ट्विटर के ज़रिये यह बात अपने प्रशंसकों से साझा की. ट्विटर पर बिग बी ने कादर खान की वापसी पर खुशी ज़ाहिर करते हुए लिखा कि कादर खान, महान सहयोगी, लेखक, मेरी कई सफल फिल्मों में सहायक, एक लम्बे अंतराल के बाद फिल्म में वापस लौट रहे हैं. स्वागत है.

कादर खान 8 साल बाद फौज़िया अर्शी की कॉमेडी फिल्म हो गया दिमाग का दही से बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं. बॉलीवुड के कॉमेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध कादर खान एक बार फिर से लोगों को हास्य प्रतिभा से गुदगुदाने आ रहे हैं. बॉलीवुड में कादर खान ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. उन्होंने कुली, बाप नंबरी-बेटा दस नंबरी, हम, बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू और जुड़वा सहित 350 से अधिक फिल्में की हैं.

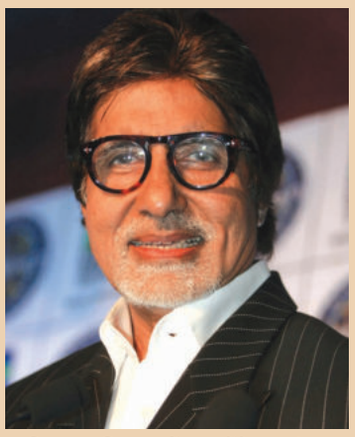

कादर खान केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक और संवाद लेखक भी हैं. कुली फिल्म में अमिताभ के किरदार में जान डालने वाले संवाद 'बचपन से सर पर अल्लाह का हाथ और अल्लाह रख्खा है अपने साथ', 'बाजू पर 786 का है बिल्ला और नाम है इक़बाल' कादर ख़ान ने ही लिखे थे. इतना ही नहीं अग्निपथ, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उस फिल्म में भी अमिताभ के जानदार संवादों का श्रेय भी कादर खान को ही जाता है. उम्मीद है कादर खान की 25 सितम्बर को आने वाली फिल्म हो गया दिमाग का दही को अमिताभ बच्चन जैसे उनके पुराने दोस्तों का भरपूर प्यार मिलेगा. ■

राष्ट्रीय पुरस्कार से बड़े हैं प्रशंसक : सलमान

बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले सलमान खान को राष्ट्रीय पुरस्कार से नहीं बल्कि अपने प्रशंसकों से प्यार है. सलमान का कहना है कि उनके प्रशंसक ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड हैं. दबंग खान कई फिल्मों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे चुके हैं. राष्ट्रीय पुरस्कार की चाह न रखने वाले दबंग खान को फिल्म बजरंगी भाई जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा. सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान और प्रेम रतन धन पायो का इंतजार उनके प्रशंसक बेसब्री से कर रहे हैं. सलमान खान पूरे बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनके नाम से ही फिल्म चलती है और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकार्ड कायम करती है. ■

एक अकेले इंसान के प्रेम और संघर्ष की कहानी मांझी- द माउंटेनमैन

फिल्म की कहानी बिहार के दशरथ मांझी की है, जिनकी पत्नी गेहलौर की पहाड़ी से फिसलकर चोटिल हो जाती हैं. पत्नी की यह हालत दशरथ मांझी के दिल में घर कर जाती है और वह पहाड़ से मुकाबला करने की ठान लेते हैं.

केतन मेहता निर्देशित मांझी-द माउंटेनमैन का ट्रेलर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें मुख्य कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दकी और राधिका आप्टे हैं. फिल्म की रिलीज की तारीख 21 अगस्त रखी गई है. फिल्म की कहानी बिहार के दशरथ मांझी की हैं, जिनकी पत्नी गेहलौर की पहाड़ी से फिसलकर चोटिल हो जाती हैं. पत्नी की यह दशा दशरथ के दिल में घर कर जाती है और वह पहाड़ से मुकाबला करने की ठान लेते हैं. लगातार 22 वर्ष (1960-1982) साल तक छेनी-हथौड़ी लेकर पहाड़ से युद्ध करते हैं और अंत में पहाड़ भी मांझी के सामने नतमस्तक होकर 360 फुट लम्बा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे देता है. जिससे गांव से शहर की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाती है. प्रेम के लिए एक अकेले इंसान के संघर्ष और जीत की कहानी को दर्शाती है मांझी-द माउंटेनमैन. ■

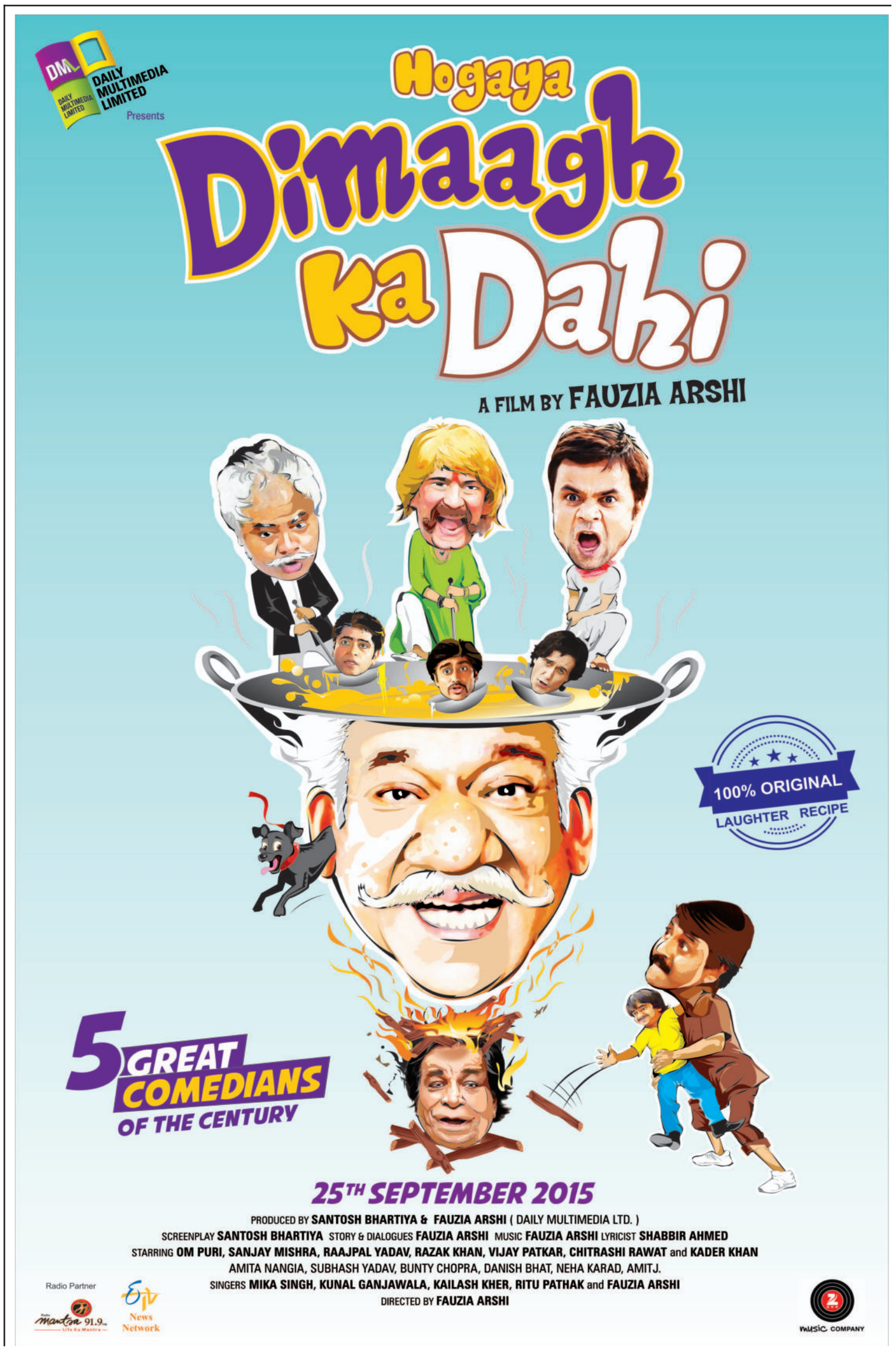

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

24 अगस्त-30 अगस्त 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाहर आया भागलपुर दंगे का जिन्न

चुनाव सिर पर हो और ऐसे में भागलपुर देंगे की जांच रिपोर्ट आ जाए, तो क्या होगा? जाहिर है कि इसके असर को देखते हुए ही सरकार ने इसे विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पटल पर रखा, न कोई चर्चा, न कोई बहस. सवाल है क्या भागलपुर दंगा पीड़ितों को इस रिपोर्ट के आने के बाद भी न्याय मिल पाएगा? क्या दोषियों को सजा हो पाएगी?

चौथी दुनिया ब्यूरो

भागलपुर दंगे का जिन्न फिर बाहर आ गया है. 26 साल पहले (1989) की इस कलंक गाथा की जांच के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व की तत्कालीन एनडीए, जिसमें जदयू और भाजपा ही थी, सरकार ने फरवरी 2006 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनएन सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था. इस आयोग की दूसरी और अंतिम रिपोर्ट सरकार को कुछ ही महीने पहले सौंप दी गई थी और इसे विधान मंडल अधिवेशन के अंतिम दिन पेश कर दिया गया. इस आयोग को दंगों के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों व कारणों की तलाश नहीं करनी थी बल्कि इसे दंगा से जुड़े मामले की तफ्तीश में गड़बड़ी के कारणों की पड़ताल और इसके जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करनी थी. इसे दंगा पीड़ितों के पुनर्वास की स्थिति का आकलन कर हालात में सुधार के उपाय सुझाने थे. लेकिन इससे भी बड़ा काम यह सौंपा गया था कि दंगा-पीड़ित परिवारों के किसी दबाव या संकट में कम कीमत पर सम्पत्ति के विक्रय की घटनाओं की जांच कर उनकी वापसी के उपाय की सिफारिश करनी थी. यह बिहार में अपने ढंग का पहला प्रयास तो था ही, देश में भी शायद यह अपवाद जैसा है. रिपोर्ट में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण झा और पुलिस अधिक्षक केएस द्विवेदी की भूमिका की विस्तार से चर्चा की गई है. लेकिन आयोग ने इन दोनों अधिकारियों को उनकी अनुभवहीनता का लाभ दे दिया है. हालांकि उसने सरकार को कहा है कि संवेदनशील जिलों में अपेक्षाकृत अनुभवी अधिकारियों का पदस्थापन किया जाए.

भागलपुर में 1989 के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सांप्रदायिक दंगा भड़का था जो कमोवेश 1990 के मार्च तक चलता रहा. इन घटनाओं में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों घायल व बेघर हो गए. लंबे तनाव के कारण रेशम नगर भागलपुर से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था जिनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के थे, बुनकर थे. इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को भय दिखाकर माटी के मोल उनकी संपत्ति खरीद ली गई थी या उन्हें बेदखल कर दिया गया था. जांच आयोग को तीन दर्जन से अधिक ऐसी शिकायतें मिलीं जिनमें दंगा पीड़ित परिवारों पर दबाव डालकर या उनकी परेशानी का फायदा उठाकर औने-पौने दामों में उनकी सम्पत्ति ले ली गई. आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि ऐसी सम्पत्ति पीड़ित परिवारों को वापस मिले, इसकी कानूनी व्यवस्था की जाए. आयोग की इस सिफारिश के आलोक में नीतीश सरकार ने मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें राज्य के डीजीपी के साथ-साथ गृह, विधि व राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के सचिवों को रखा गया है. राज्य के वरिष्ठ नौकरशाहों की इस समिति को आयोग के अन्य सुझावों को लागू करने के बारे में उपाय ढूंढना है. आयोग ने और भी कई सिफारिशें की है. उसने दंगों से जुड़े मामलों की गलत, त्रुटिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण या लापरवाह पर्यवेक्षण के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार माना है. ऐसा माना जाता है कि इन कारणों से दंगों से जुड़े अनेक जिम्मेदार आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई और वे बरी हो गए. ऐसे अफसरों में एक आईपीएस शीलवर्द्धन सिंह केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्त हैं. कुछ अफसर झारखंड सरकार के कैडर में चले गए, कुछ बिहार में ही रह गए. पर, इनमें वैसे लोगों की संख्या काफी है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका देहांत हो चुका है. सभी चिह्नित अफसरों पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालाय झारखंड व बिहार सरकारों के संबंधित विभागों को लिखा गया है. जांच आयोग ने राज्य सरकार का एक संकट की ओर ध्यान दिलाया है. आयोग का कहना है कि दंगों से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए तीन आदलतों को अधिकृत किया गया है, लेकिन न्यायाधीशों की कमी के चलते मामलों के निष्पादन में

काफी वक्त लग रहा है. लंबे समय तक न्यायाधीशों के पद खाली रह जाते हैं. इससे निष्पादन-दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है. हालांकि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि उसने अपनी पहली रिपोर्ट में दंगा-पीड़ित परिवारों को मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश की थी और उसे मान लिया गया. आयोग ने दंगा पीड़ित परिवारों को पेंशन की रकम बढ़ाने पर भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की है.

भागलपुर दंगों को लेकर दो न्यायिक जांच आयोगों का गठन किया गया. पहला आयोग दंगों के तुरंत बाद गठित किया गया था. इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आरएन प्रसाद को सौंपी गई थी. लेकिन 1990 के मार्च में लालू प्रसाद की जनता दल सरकार बनने के बाद दो नए सदस्य आयोग में जोड़े गए-न्यायाधीश आरसीपी सिन्हा और न्यायाधीश एस शम्सुल हसन. 1995 में इस आयोग ने दो रिपोर्ट सौंपी. एक रिपोर्ट जस्टिस आरएन प्रसाद के और दूसरी रिपोर्ट जस्टिस आरसीपी सिन्हा और जस्टिस एस शम्सुल हसन की थी. लालू प्रसाद की सरकार ने इसी रिपोर्ट को माना था. हालांकि यह अब भी खोज का विषय है कि इसकी कितनी सिफारिशों को जमीन पर उतारा गया. यही वजह है कि जस्टिस एनएन सिंह की रिपोर्ट को लागू किए जाने को लेकर पटना के सत्ता गलियारे में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं. दंगा पीड़ितों की सम्पत्ति उन्हें वापस करने की व्यवस्था का ऐसा वायदा देश में किसी सरकार ने शायद पहली बार किया है. पर यह कहने और सुनने में जितना सहज लगता है, इसे लागू करना उतना ही कठिन है. आयोग भी मानता है कि इसे लागू करने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं. इसके लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करना होगा. दंगा पीड़ितों, जिनकी सम्पत्ति डराकर या दबाव डालकर खरीदी गई, को अपनी अचल सम्पत्ति वापस पाने के लिए अदालत जाना होगा, फिर उसे मुक्त कराया जा सकेगा. इस पूरे प्रकरण में कानून में संशोधन के संदर्भ में ही नहीं, अन्यथा तौर पर भी सरकार की भूमिका बड़ी हो जाती है. सरकार के स्तर पर थोड़ी भी शिथिलता या उदासीनता हुई तो दंगा-पीड़ितों का हक मारा गया. जिस तत्परता से आयोग का गठन किया गया और उसके विचार-बिन्दु में इस बात को रखा गया, फिर सरकार ने सिफारिश को लागू करने के उपायों की तलाश में सचिवों की समिति गठित की, वही तत्परता आगे बनी रहेगी तभी इस काम को पूरा किया जा सकता है. क्या यही तत्परता बनी रहेगी? यह यक्ष प्रश्न है. इसका उत्तर बिहार की भावी राजनीति में निहित है.

जस्टिस एनएन सिंह आयोग के गठन के घोषित होने के कारण तो निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण थे और सत्ता में दंगा-पीड़ितों के भरोसे को मजबूत करने के लिए जरूरी व दूरगामी असर के थे. इससे ऐसा हुआ भी. जिन लोगों का भागलपुर के पीड़ितों से साबका रहा है, वे यह मानते हैं. पर, आयोग गठन के पीछे मात्र यही निश्छल-भाव थे? बिहार की राजनीति के जानकार इसका उत्तर न में ही देंगे. यह माना जा रहा है लालू-राबड़ी राज में भागलपुर दंगों के कुछ आरोपियों को मिली राहत इस आयोग के गठन का प्रेरक तत्व थे. इनमें कुछ आरोपियों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के मधुर संबंध की चर्चा बिहार के राजनीतिक हल्कों में होती रही है. इस संबंध के बारे में अब भी सुनने में आता है. इन तथ्यों को सामने लाकर राजद सुप्रीमो को घेरने की तत्कालीन एनडीए की रणनीति का हिस्सा था यह, ऐसा माना जाता है. यह भी माना गया था कि एक विशिष्ट सामाजिक समूह ने दंगा पीड़ितों को डरा-धमका कर उनसे औने-पौने दाम पर सम्पत्ति हासिल कर ली. ऐसे भी वाकये सामने आए जब जान की रक्षा में घर-बार छोड़ कर भागे अल्पसंख्यक सुमदाय की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया गया, पीड़ित को कोई कीमत भी कभी नहीं दी गई. राज्य के विपक्षी राजनीतिक और बड़े प्रशासनिक हलकों में ऐसे आपराधिक कृत्य को लालू-राबड़ी राज का परिणाम माना गया था. राजनीति के जानकारों का मानना है कि आयोग का गठन लालू प्रसाद के माय समीकरण को विभाजित करने की तत्कालीन एनडीए की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था. इस रणनीति में तत्कालीन सरकार कितनी सफल हुई, यह कहना कठिन है. यह कहना भी कठिन है कि इससे माय कितना विभाजित हुआ. लेकिन यह तथ्य है कि गत संसदीय चुनाव में दंगा-प्रभावित तत्कालीन भागलपुर जिले के दोनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों- भागलपुर और बांका में राजद की जीत हुई थी. विधानसभा उपचुनाव में भागलपुर में महागठबंधन के कांग्रेसी उम्मीदवार ही विजयी हुए.

भागलपुर दंगों के संदर्भ में जांच आयोगों की अब तक की सभी रिपोर्ट आ चुकी हैं. जस्टिस एनएन सिंह की यह रिपोर्ट के साथ सरकार ने की गई कार्रवाई का ब्योरा भी विधान मंडल में पेश किया गया. ऐन चुनाव का मौका होने के बावजूद एक दिन की अखबारों की सुर्खियां बन कर यह रिपोर्ट राज्य की राजनीति के विमर्श से गायब हो गई है. महागठबंधन के दलों-जदयू, राजद, कांग्रेस और राकांपा- को तो जाने दीजिए, एनडीए के किसी दल ने भी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की है. दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मामूली सी मांग भी कहीं किसी कोने से नहीं आई. तथ्य तो यही है कि चुनाव के दहलीज पर आ जाने के कारण दोषी अधिकारियों को लेकर कोई राजनीतिक समूह कोई बात भी नहीं करना चहता. वस्तुतः कोई राजनेता नौकरशाही- नीचे से लेकर ऊपर तक की- को असंतुष्ट नहीं करना चाहता. चुनाव में क्या पता कहां कौन काम आए! ऐसे में कोई दल दंगा पीड़ितों को सम्पत्ति वापसी जैसे मुद्दो पर कैसे बात कर सकता है? आयोग की रिपोर्ट से साफ है कि डरा-धमका कर औने-पौने दाम पर दंगा पीड़ितों की सम्पत्ति कुछ दबंग सामाजिक समूह ने खरीदी है. इन्हीं समूहों ने अल्पसंख्यक समुदाय की सम्पत्ति को हड़पा भी. चुनाव के समय कौन राजनीति अपना वोट बिगाड़ना चाहेगी भला! सो, इस मसले पर पूरी राजनीति खामोश है. लेकिन यह कहना भी कठिन है कि चुनाव बाद बिहार की राजनीति इस मसले पर सक्रिय हो जाएगी. वस्तुतः यह मसला बर्रे का छत्ता है, कोई इस पर हाथ नहीं डालना चाहेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

चुनावी हलचल

अगला मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग से: अश्फाक

आज की राजनीति पर चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के संयोजक सतीश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार को लालू–नीतीश ने जातियों के विकास की आड़ में राज्य को विनाश की गर्त में धकेल दिया है. [illegible] – रजनीकान्त

नहीं चलेगी बड़े-छोटे भाई की राजनीति -उपेन्द्र

[illegible] – नसीम रब्बानी

विकास कार्यों को देंगे गति : डीएम

[illegible] कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए डीएम ने कहा कि जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे. सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ वाज़िब हकदारों को मिल सके इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जायेगा. स्थानीय समस्याओं के सवाल पर कहा कि निदान की दिशा में शीघ्र प्रयास शुरू किया जाएगा. डीएम ने कहा कि जिले में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से कराने को लेकर आम लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है. अमन व शांति से ही मुकाम को हासिल किया जा सकता है. – वाल्मीकि

दिल को रखें स्वस्थ्य

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ वन्दना कुमारी फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ

किशनगंज जिले की डॉ वन्दना कुमारी से बातचीत का क्रम जब शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि आजकल महिला डॉक्टर ज्यादातर गायनो का ही क्षेत्र चुनती हैं जबकि फिजिशियन एवं हर्ट स्पेशलिस्ट या अन्य क्षेत्र को युवतियां कम चुन रही हैं खासकर किशनगंज क्षेत्र में इसका अभाव दिख रहा है। उन्होंने हर्ट की बीमारियों से संबंधित जानकारी हमारे पाठको के लिए शेयर की। उनका मानना है कि हर्ट की समस्या बच्चों में जन्म से रहता तो है ही लेकिन इसका अनुवांशिक कारण 5 प्रतिशत है जबकि जन्म लेते वक्त शिशु को होने वाली समस्या सबसे बड़ा कारण है इसलिए सुझाव है कि महिलाएं डिलिवरी हमेशा डॉक्टर से ही करवायें घर पर बच्चों कि डिलिवरी न करवायें। दूसरा कारण बच्चों के केस में यदि बार–बार खांसी हो और जोड़ो में दर्द के लक्षण हों तो इसे हल्के में न लें और तुरंत इलाज करवायें और हर्ट से संबंधित जांच भी करवा लें। 90 प्रतिशत हार्ट डिजिज का कारण हाइपरटेंशन (ब्लड प्रेशर) और डायबिटिज है और यदि दोनों है तो हर्ट के बीमारी का चासेंज बढ़ जाता है। यदि एडल्ट एज में आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो संभल जायें और हर्ट चेक या इसीजी भी करवायें क्योंकि हर्ट रोगी की भी छाती में भारीपन महसूस होता है। छाती मे भारीपन महसूस होना और दर्द होना इसके लक्षण हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि प्रेग्नेन्सी से लेकर, बी.पी., डायबिटिज, के साथ साथ बार–बार खांसी की समस्या से बचें, सजग रहें तुरंत इलाज करवायें। ज्वाइन्ट पेन के साथ खांसी हर्ट की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। कैलोस्ट्रोल की मात्रा न बढ़ने दें और सादा खाना ही अपने जीवन में अपनायें। चित्रा भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट

नए चेहरे की तलाश में जनता

आरती सिंह | अरुण यादव | चौधरी मो. युसुफ | दिनेश चन्द्र यादव | चंद्रमणि प्रसाद | संजय सिंह | राजीव रंजन | रीतेश रंजन

2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की ओर से खगड़िया के सांसद दिनेश चंद्र यादव प्रत्याशी थे, तो मरहूम चौधरी मो. सलाउद्दीन के पुत्र चौधरी महबूब अली कैसर राजग गठबंधन के घटक दल लोजपा के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे. जैसे ही महबूब अली का नाम लोजपा की तरफ से घोषित हुआ तो जदयू की तरफ से दिनेश चंद्र यादव किनारे दिए गए. यह कहना गैरजरूरी है कि पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत वाली सीट सिमरी बख्तियारपुर से अपने नजदीकी कहे जाने वाले व्यक्ति अरुण कुमार यादव को जदयू का टिकट देकर विधानसभा भेजा. अब यह सीट भी खाली नहीं है.

विपिन यादव

किसी भी दल को सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों का चयन कर पाना काफी मुश्किल कार्य होगा. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कभी कांग्रेस के दिग्गज मरहूम चौधरी मो. सलाउद्दीन किया करते थे तो कभी कोशी में विकास पुत्र से नवाज़े जाने वाले खगड़िया के पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव भी इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे. 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की ओर से खगड़िया के सांसद दिनेश चंद्र यादव प्रत्याशी थे तो मरहूम चौधरी मो. सलाउद्दीन के पुत्र चौधरी महबूब अली कैसर राजग गठबंधन के घटक दल लोजपा के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे. जैसे ही महबूब अली का नाम लोजपा की तरफ से घोषित हुआ तो जदयू की तरफ से दिनेश चंद्र यादव किनारे दिए गए.

यह कहना गैरजरूरी है कि पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत वाली सीट सिमरी बख्तियारपुर से अपने नजदीकी कहे जाने वाले व्यक्ति अरुण कुमार यादव को जदयू का टिकट देकर विधानसभा भेजा. अब यह सीट भी खाली नहीं है. उधर, पांच से सात साल के अंदर प्राय: सभी दलों में इतने कार्यकर्ता सक्रिय हो गये कि आपस में ही मारा–मारी हो रही है. यह कहा जा सकता है कि दल के अंदर टिकट पाने के लिए विद्रोह मचा हुआ है. अब कुछ रास्ता आसान इसलिए भी हो गया है क्योंकि मुकाबला मुख्य रूप से दो राजनीतिक गठबंधनों के बीच होने जा रहा है. राजग गठबंधन और महागठबंधन.

'अबकी बार, बिहार में भाजपा की सरकार' के नारे से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश व उत्साह देखा जा रहा है. भाजपा से कई प्रमुख दावेदारों में सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के गांव सोनपुरा निवासी बाबू नथूनी सिंह की बड़ी बहू आरती सिंह भी प्रबल दावेदारों में हैं. आरती सिंह पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री जैसे पद का कुशलता पूर्वक दायित्व संभालने के बाद भू.ना.मंडल विश्वविद्यालय की सिंडिकेट सदस्य भी हैं. चर्चा है कि पार्टी स्तर से इस सीट के लिए उन्हें हरी झंडी भी मिल गयी है और गृह विधानसभा क्षेत्र होने के कारण आरती का जनसंपर्क भी काफी जोर–शोर से चल रहा है. कोशी क्षेत्र से प्रदेश भाजपा में महिलाओं की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली आरती सिंह इकलौती महिला है और पार्टी के प्रति इनकी समर्पण से जनाधार भी व्यापक हुआ है. वैसे भाजपा से अरविंद कुमार सिंह का भी नाम चल रहा है. लेकिन अरविंद ने कई दलों की शोभा बढाने के बाद भाजपा का दामन थामा है. जबकि विजय भाई भीएस, तरियामा के मुखिया दिलिप साह, सरौंजा निवासी अजय सिंह, सहरसा जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव रंजन आदि भी हाथ–पांव मार रहे हैं.राजग के घटक दल लोजपा भी स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव के परिणाम के बाद से जोश में दिख रही है. इस विधानसभा क्षेत्र में सोनवर्षा महाराज के वंशज राजनीति में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, अब इसी परिवार के एक आर शहजादे संजय सिंह भी अपना राजनीतिक कदम बढाते हुए लोजपा के जिला उपाध्यक्ष बने और दल के अंदर इस सीट पर ये भी दावेदारी कर रहे हैं.इस गणित में ये कहां तक आगे बढ पाते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. वैसे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा के अन्तर्गत पड़ती है और यहां के सांसद लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर हैं. कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद कैसर लोजपा के साथ खड़े हुए और उनका पूरा परिवार एकमत हैं. एसी चर्चा है कि कैसर भी चाहते हैं कि उनका पुत्र मो. युसुफ या उनके बड़े भाई चौधरी फारूख इस सीट से चुनाव लड़े. लेकिन यह सीट राजग गठबंधन के भाजपा की झोली में जाती है या लोजपा की यह तो चुनाव करीब आने के बाद पता चलेगा. वैसे विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने लोजपा को सीट व उमीदवार भी देने का भी काम किया है.अगर स्थिति विधान परिषद वाली रही तो कुछ भी हो सकता है. लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि प्रत्याशी भाजपा की होगी और सीट लोजपा की हो सकती है. तो शादी–ब्याह की तरह राजग में गोलट का फार्मूला भी काफी सटीक बैठ रहा है.इस फार्मूले का भी उपयोग इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किया जा सकता है.

वर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर लोजपा की सदस्यता ग्रहण किये. इस लिए कांग्रेस भूल कर भी दावा नहीं करना चाहेगी. हालांकी पार्टी के उभरते कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने का जोश है. पर,पार्टी की नीयत और कृपा किसके साथ होती है यह तो वक्त आने पर पता चलेगा. वैसे टिकट पाने के लिए सभी दलों के कार्यकर्ता लगे हैं.

महागठबंधन में जदयू से उम्मीदवार विधायक अरुण कुमार यादव है. उधर, राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री रहे दिनेश चंन्द्र यादव को भी सदन की जरूरत है. कोशी के जदयू में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात दिनेश चंन्द्र यादव के ईशारे पर ही चलती हैं. कोशी में जदयू कार्यकर्ताओं को उर्जा प्रदान करने के लिए उनका कहीं न कहीं से चुनाव लड़वाना पार्टी की भी प्राथमिकता होगी. इस वजह से इस सीट पर उनके भी चुनाव लड़ने का कयास लगाया जा रहा है. जबकि राजद से मो. जफर आलम की दावेदारी पहले भी बनी है. वैसे इस सीट पर वैश्य समाज अपनी दावेदारी मानता रहा है, पर मौका नहीं दिया गया. इस बार संभावना है कि अगर जदयू किसी वैश्य की ओर झांकेगी तो चन्द्रमणि प्रसाद को भी मौका दिया जा सकता है. वैश्य में इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला परिषद के उपाध्यक्ष रीतेश रंजन भी हैं. लेकिन उनका कोई अपना ठिकाना नहीं रह गया है. अब तक वे पूर्व सांसद आनंद मोहन, सांसद पप्पू यादव, खगड़िया के लोजपा सांसाद चौधरी महबूब अली कैसर के अलावा हाल के विधान परिषद चुनाव में विधायक नीरज कुमार सिंह की धर्मपत्नी नूतन सिंह के साथ भी रह चुके हैं. इसलिए उनके दल का तो अभी तक अता–पता ही नहीं है. वर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर लोजपा की सदस्यता ग्रहण किये. इस लिए कांग्रेस भूल कर भी दावा नहीं करना चाहेगी. हालांकी पार्टी के उभरते कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने का जोश है. पर,पार्टी की नीयत और कृपा किसके साथ होती है यह तो वक्त आने पर पता चलेगा. वैसे टिकट पाने के लिए सभी दलों के कार्यकर्ता लगे हैं. अब तो टिकट में भी पैसों का खेल–खेला जा रहा है. इसलिए कुछ भी कहना आसान नहीं होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

नवादा में भीतरघात व बागी का ख़तरा

पूर्णिमा देवी | पूर्णिमा यादव | अनिल सिंह | प्रदीप महतो | कौशल यादव

सुनील सौरभ

मगध प्रमंडल का नवादा जिला अपने दामन में पांच विधानसभा क्षेत्रों को लपेटे हुए है. बिहार का एक पिछड़ा जिला माने जाने वाला नवादा समाजवादी तथा जनसंघ–भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होने वाला जिला माना जाता रहा है. यहां की प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत भी काफी समृद्ध है. इस जिले का आधा क्षेत्र जंगल, पहाड़ों से आच्छादित है. समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण सम्पूर्ण जिले की कृषि व्यवस्था वर्षा पर निर्भर है. कौवाकोल के सेखोदेवरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब अपनी संस्था, ग्राम निर्माण मंडल की स्थापना कर ग्राम व कृषि विकास के लिए जागरूक करने का काम शुरू किया और कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हुई तो इस क्षेत्र के किसानों को अच्छी फसल का लाभ मिलने लगा. आजादी के तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय में शामिल हो गए. जब वह नवादा के एक आश्रम में रहना शुरू किए तो नवादा की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई. समाजवादी विचारधारा के लोगों को इस जमाने में चुनाव में अधिक सफलता मिली वहीं दूसरी तरफ विरोध में खड़े जनसंघ–भाजपा को भी सफलता मिली. तब कांग्रेस के एक दो बड़े नेता भी नवादा में अपना झंड़ा बुलंद करने में सफल रहे. इसी समाजवादी राजनीतिक जमीन का असर है कि अपने को समाजवादी विचारधारा का बताने वाला राजद और जदयू तथा जनसंघ की विचारधारा वाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन की सीधी लड़ाई नवादा जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, गोबिन्दपुर तथा रजौली में होने की संभावना है. 2010 के विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण था. इसमें एनडीए ने सभी पांचों सीटों पर कब्जा कर डाला था. नवादा, गोबिन्दपुर तथा वारिसलीगंज जदयू तो हिसुआ और रजौली सुरक्षित क्षेत्र भाजपा के खाते में गई थी.

उस समय भाजपा के साथ जदयू थी और राजद के साथ लोजपा थी. इस बार जदयू–भाजपा अलग–अलग हैं. जदयू के साथ राजद आ गई है, तो भाजपा के साथ लोजपा खड़ी है. भाजपा के साथ इस बार रालोसपा तथा और नए दल भी जुड़ गए हैं. 2010 में कांग्रेस ने अलग होकर चुनाव लड़ा था. इस बार कांग्रेस जदयू–राजद गंठबंधन के साथ जा चुनाव लड़ रही है. नवादा में मुख्य रूप से उन्हीं दो गठबंधनो के बीच ही कांटे का मुकाबला होने की संभावना है. लेकिन इसके साथ ही दोनो गठबंधनो के प्रत्याशियों को अपने–अपने दल तथा गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से भीतरघात किए जाने या बागी प्रत्याशी होकर खड़े होने की संभवना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है. नवादा से पूर्णिमा देवी जदयू की विधायक है. इनके पति कौशल यादव जदयू से गोबिन्दपुर से विधायक हैं. राजद के राजवल्लभ यादव चुनाव में उनके विरोध में लड़ते रहे हैं. अब गठबंधन होने से राजवल्लभ यादव को समस्या है कि सिटिंग के नाम पर नवादा सीट जदयू को मिल जाएगी. ऐसे में राजवल्लभ यादव भीतरघात करेंगे या फिर बागी होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर समय आने पर पाला बदल भाजपा में शमिल हो सकते हैं. इनके भाई स्व. कृष्णवल्लभ यादव नवादा से भाजपा के विधायक हुआ करते थे. उसके बाद वह पाला बदल कर लालू यादव के साथ हो गए थे. इसी प्रकार हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अनिल कुमार विधायक हैं. यहां से कांग्रेस की दावेदारी है. यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है. यहां से कांग्रेस की नीतू देवी संभावित प्रत्याशी हैं, जो पूर्व मंत्री और यहां के पूर्व विधायक आदित्य सिंह की पुत्रवधु हैं. वहीं दूसरी ओर राजद के अनिल मेहता भी हिसुआ से लड़ने की तैयारी में हैं. तय है कि दोनों में से एक बागी होंगे या भीतरघात करेंगे. यही स्थिति रजौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की है. यहां से भाजपा के कन्हैया कुमार विधायक हैं. राजद गठबंधन से नवादा जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशवीर संभावित प्रत्याशी हैं, तो भाजपा–कांग्रेस से चार बार विधायक रह चुके बनवारी राम इस बार कन्हैया कुमार के रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए तैयार बैठे हैं. वे किसी भी दल से टिकट लेने के लिए प्रयासरत हैं. वारिसलीगंज तथा गोबिन्दपुर में दोनों गठबंधनों के प्रत्याशियों को विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाजपा–लोजपा गठबंधन से यहां से पूर्व विधायक अरुणा देवी जो यहां के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं और एक मात्र प्रत्याशी हैं. इनके विरुद्ध यहां से जदयू के विधायक प्रदीप कुमार हैं. वहीं गोबिन्दपुर से जदयू के कौशल यादव विधायक है. भाजपा–लोजपा–रालोसपा गंठबंधन से यहां से इन्द्रदेव कुशवाहा को टिकट मिल सकता है. इन सभी स्थिति से स्पष्ट है कि दोनों गंठबंधनों के प्रत्याशियों को अपने ही लोगों से खतरा है. नवादा के प्रसिद्ध सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता तथा काकोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहउद्दीन कहते हैं कि इस जिले के जनप्रतिनिधि जीतकर विधानसभा पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन यहां के ऐतिहासिक, प्राकृतिक–सांस्कृतिक विरासत के विकास व संरक्षण की बात नहीं कर पाते हैं. देश का प्रसिद्ध जलप्रपात काकोलत, तक्षशीला के समकालीन प्राचीन विश्वविद्यालय अपसढ़, देवगढ़, मां सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी, चामुंडा मंदिर रूपौ, श्रृंगी ऋषि पहाड़, जेपी का सर्वोदय आश्रम, हजरत शाह वारसी का दरगाह, कौवाकोल का बोलता पहाड़ समेत दर्जनों ऐसे ऐतिहासिक प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल नवादा जिले में हैं, जिसकी विकास की चिंता राजनीतिक नेताओं को नहीं है. इन सभी का विकास हो गया, तो नवादा बिहार के पर्यटन नक्शे पर महत्वपूर्ण हो जाएगा. फिलहाल सभी दलों और गंठबंधन के नेता अपने–अपने संभावित क्षेत्रों में मतदाताओं की नब्ज तलाशने में लगे हैं. निश्चित है कि नवादा जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर रहेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

नरेन्द्र मोदी की गया में परिवर्तन रैली

आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड टूटे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा के नाम पर गया शहर में आने वाले सभी बाहरी रास्ते को सील कर दिया गया था. सभा स्थल गांधी मैदान से उन सभी बाहरी रास्तों की दूरी करीब 5 से 8 किलोमीटर है. सभी वाहनों को वहीं रोक दिया गया और लोग वहां से पैदल चलकर गांधी मैदान पहुंचे. मानपुर में मुफसिल मोड़ के पास ही नवादा खिजरसराय अतरी, नालन्दा से आने वालों वाहनों को रोक दिया गया. जहानाबाद पटना से आने वाले को पहश्वर–रामशिला के पास तो औरंगाबाद टेकारी से आने वालों को कुजापी डेल्हा तो शेरघाटी, औरंगाबाद, भभुआ, सासाराम से आने वालों को बोधगया के दोमुहान और केन्दुई के पास रोक दिया गया. लोगों का जोश जुनून ऐसा की सभी लोग 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी मैदान पहुंचे.

सुनील सौरभ

दक्षिण बिहार की राजनीतिक राजधानी और मगध का केंद्र बिंदु गया में 9 अगस्त 2015 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिवर्तन रैली में उमड़े जन सैलाब ने भीड़ के मामले में आजादी के बाद हुए तमाम रैली–सभा के रिकॉर्ड को तोड़ डाला. यह बात गया शहर के नई गोदाम के 72 वर्षीय महावीर प्रसाद, मानपुर के 68 वर्षीय रमेश सिंह से लेकर रैली में शामिल हर उम्र के लोगों की जुबान से निकल रही थी. उन सभी के पास भीड़ मापने का कोई पैमाना नहीं था. फिर भी 3 लाख से शुरू होकर 6 लाख की भीड़ का अंदाजा मोदी समर्थक लगा रहे थे, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भाजपा की ओर से गया में आयोजित की गई परिवर्तन रैली में भीड़ 3 लाख से कम नहीं थी. उसमें सभी लोगों का अपना–अपना फलसफा था कि चारों ओर से गया आने वाली ट्रेनों से करीब एक लाख लोग आए तो गया शहर के भी एक लाख से अधिक लोग नरेन्द्र मोदी को सुनने पहुंचे, तो वहीं सड़क मार्ग से भी मगध शाहाबाद के विभिन्न जिलों से कम से कम एक लाख लोग जरूर आएं होंगे. यह तर्क था रैली में शामिल अधिकांश मोदी समर्थकों का, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा के नाम पर गया शहर में आने वाले सभी बाहरी रास्ते को ही सील कर दिया गया था. सभा स्थल गांधी मैदान से उन सभी बाहरी रास्ते की दूरी करीब 5 से 8 किलोमीटर है. सभी वाहनों को वहीं रोक दिया गया और लोग वहां से पैदल चलकर गांधी मैदान पहुंचे. मानपुर में मुफसिल मोड़ के पास ही नवादा खिजरसराय अतरी, नालन्दा से आने वालों वाहनों को रोक दिया गया. जहानाबाद पटना से आने वाले को पहश्वर–रामशिला के पास तो औरंगाबाद टेकारी से आने वालों को कुजापी डेल्हा तो शेरघाटी, औरंगाबाद, भभुआ, सासाराम से आने वालों को बोधगया के दोमुहान और केन्दुई के पास रोक दिया गया. लोगों का जोश जुनून ऐसा की सभी लोग 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी मैदान पहुंचे. सबसे बड़ी बात थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 9 अगस्त 2015 को मगध बंद का आहवान किया था और बस मालिकों को चेतावनी दी थी कि जो भी बस चलाएगा या रैली के लिए बस देगा, उसे जन अदालत में सजा दी जाएगी, जिसके कारण नक्सली क्षेत्रों से वाहनों के काफिले तो नहीं आ सके, लेकिन इमामगंज, डुमरिया जैसे क्षेत्र से लोग पैदल–मोटरसाईकिल से सुबह 6 बजे ही सैकड़ों की संख्या में चल दिए. किसी तरह जीटी रोड शेरघाटी पहुंचे और यहां से वाहन से गया पहुंच रैली में भाग लिया. सबसे बड़ी बात यह थी कि रैली में आने वालों को सुरक्षा के नाम पर जितना रोकने का प्रयास किया गया, लोगों में उसका रिएक्शन होता गया और जोश जुनून में पैदल ही गया के गांधी मैदान में ऐसी भीड़ जमा हो गई, जिसमें गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अब तक हुए तमाम रैली–सभा का रिकार्ड तोड़ डाला. सब लोग यही कहते आए कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिवर्तन रैली को विफल करने का हर प्रयास किया, लेकिन जोश के आगे प्रशासन का होश ठिकाने लग गया. प्रशासन ने 9 अगस्त को गया शहर में ऑटो तथा निजी चार पहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दिया था. इसका कारण बताया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था. गया शहर के भाजपा व नरेन्द्र मोदी समर्थकों ने अपने–अपने प्रतिष्ठान को बंद कर गांधी मैदान पहुंच गए, हालांकि रविवार होने के चलते कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, लेकिन 9 अगस्त को पूरे गया शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसा नजारा था, तो गांधी मैदान जाने वाले सभी रास्तों में जनसैलाब था. जितनी भीड़ गांधी मैदान के अंदर थी, उतनी ही भीड़ गांधी मैदान के चारों ओर सड़क पर जमा थी. गया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो कभी बंद नहीं होती है वहां भी पुरी तरह सन्नाटा था. लोगों ने बताया कि सभी सब्जी विक्रेता नरेन्द्र मोदी का भाषण सुनने गांधी मैदान गए हैं. भले ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण से बहुत कुछ नहीं मिल सका, लेकिन मगध, शाहाबाद के जिले से आए लोगों ने 9 अगस्त 2015 को गया के गांधी मैदान को ऐतिहासिक दिन बना डाला.■

प्रशासन ने 9 अगस्त को गया शहर में ऑटो तथा निजी चार पहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दिया था. इसका कारण बताया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था. गया शहर के भाजपा व नरेन्द्र मोदी समर्थकों ने अपने–अपने प्रतिष्ठान को बंद कर गांधी मैदान पहुंच गए, हालांकि रविवार होने के चलते कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, लेकिन 9 अगस्त को पूरे गया शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसा नजारा था, तो गांधी मैदान जाने वाले सभी रास्तों में जनसैलाब था. जितनी भीड़ गांधी मैदान के अंदर थी, उतनी ही भीड़ गांधी मैदान के चारों ओर सड़क पर जमा थी.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

चुनावी हलचल

पोशाक राशि वितरित

वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड के पहाड़पुर तोई अंधड़ाबड़ चौक पर स्थित नीतीश कुमार स्मारक महाविद्यालय में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पढ़ाई कर रही बालिकाओं के बीच पोशाक राशि का वितरण किया गया. महाविद्यालय के संस्थापक मेजर डॉ. राजेश्वर पटेल एवं प्राचार्य प्रो. चन्द्रभूषण प्रसाद वर्मा ने संयुक्त रूप से पोशाक वितरण किया. मेजर डॉ. राजेश्वर पटेल ने कहा कि जब तक इस देश की लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है. प्राचार्य चन्द्रभूषण वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. पोशाक राशि प्राप्त करने वाली छात्राओं में सुमन कुमारी, सहला आफरीन, नीलम कुमारी, प्रीति कुमारी, पूजा कुमारी, मधु कुमारी, सपना कुमारी रहीं. इस मौके पर कॉलेज के व्याख्याता प्रो. मनोज कुमार सिंह, प्रो. अनल कुमार, प्रो. सुधीर कुमार मालाकार, प्रो. सत्यप्रकाश, प्रो. राजनाथ राय, डॉ. अजय कुमार, प्रो. प्रभू नाथ सिंह, प्रो. वरुण कुमार वरुण, प्रो. बेबी कुमारी, प्रो. रत्नेश कुमार रत्न, प्रो. कुन्दन कुमार वरुण, प्रो. बेबी कुमारी प्रो.रत्नेश कुमार रत्न, प्रो. कुन्दन कुमार सिंह, प्रो. कैलाशपति शर्मा, प्रो. जमीन अख्तर, प्रो. राजीव रंजन, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. लालबाबू राय ,दीपक कुमार, कुन्दन कुमार एवं जय कुमार उपस्थित रहे. **– सुधीर मालाकार**

सीमा बनी प्रदेश राजद उपाध्यक्ष

सीतामढ़ी शहर के कोट बाजार निवासी राजद नेत्री सीमा गुप्ता को प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के पुर्नगठित समिति में शामिल कर लिया है. पूर्व विधायक सह राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रेमा चौधरी ने सीमा गुप्ता को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष सह उत्तर बिहार प्रभारी बनाया है. उक्त मनोनयन पर सीमा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे एवं प्रदेश महिला राजद अध्यक्ष प्रेमा चौधरी को धन्यवाद दिया है. उधर नव मनोनीत उपाध्यक्ष सीमा को जिला राजद अध्यक्ष मो. शफीक खां, विधान पार्षद दिलीप राय, पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव, युवा राजद जिलाध्यक्ष चंद्रजीत प्रसाद यादव, गणेश गुप्ता, लक्ष्मी साह, हरिओम शरण नारायण, सन्नी श्रीवास्तव, राम जनम पासवान, जनक दास, वीर बहादुर यादव, डॉ निर्मल गुप्ता, डॉ लता गुप्ता, डॉ प्रतिमा आनंद, डॉ विभा ठाकुर, डॉ गौरी शंकर, डॉ सुनील कुमार, शीला देवी, आनंदी देवी, वीणा गुप्ता, अर्चना देवी, सरिता पासवान, नीलम यादव, समेत अन्य सभी ने बधाई दी है. **– आदित्यानंद**

भाजपा प्रत्याशी के लिए दावेदारी

सीतामढ़ी जिला समेत सूबे के अलग–अलग जिलों में पार्टी संगठन के लिए लगातार कार्य करने वाले प्रदेश भाजपा नेता सुफल झा भी इस साल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं. जिला में चल रही चुनावी चर्चा पर यकीन करें, तो लंबे अर्से से झा टिकट के दावेदारों में अगली कतार के नेता रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें चुनाव के समय पार्टी संगठन के अन्य कार्यों से दूसरे स्थान पर लगाया जाता रहा है. चर्चा के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनाव में सुफल झा जिले के किसी न किसी सीट से अपनी दावेदारी का प्रयास कर सकते है. हालांकि झा इस संबंध में कुछ भी बोलने से बचते हुए पार्टी नेतृत्व के फैसले को सर्वोपरि बताया. उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण पार्टी नेतृत्व के निर्देश का पालन पहली प्राथमिकता रही है. पार्टी जिस कार्य के लायक माने अपनी सेवा देने से परहेज नहीं करेंगे.■ **–विकास**

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न

सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari
वृहत अंकगणित के लेखक

60. किसी परीक्षा में 50 प्रश्न थे। सही हल के लिए 5 अंक प्राप्त होते हैं और गलत हल के लिए (–1) अंक मिलते हैं । एक छात्र ने 20 प्रतिशत गलत हल किया और 20 प्रतिशत प्रश्न हल नहीं किया। तो वह कितना अंक पायेगा ?
A) 130 B) 140 C) 150 D) 160

61. कुछ आदमी तथा घोड़े समान संख्या में कहीं जा रहे थे।आधे आदमी घोड़े पर बैठे थे और आधे घोड़े के साथ चल रहे थे। यदि जमीन पर कुल 70 पैर चल रहे थे तो घोड़ों की संख्या क्या थी?
A)10 B)12 C)14 D)16

62. किसी परीक्षा में 50 प्रश्न थे। सही हल के लिए 1 अंक, गलत हल के लिए -½ और शेष छोड़े गये प्रश्नों के लिए -¼ अंक निर्धारित थे। यदि परीक्षा में एक छात्र ने 34.5 अंक प्राप्त किये तो कितने प्रश्न सही हल किये?
A) 45 B)48 C)54 D) तय नहीं कर सकते

63. प्रश्न 33 में यदि वह 10 प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है तो कितना सही हल करता है?
A)45 B)48 C)54 D) तय नहीं कर सकते

64. एक छात्र किसी परीक्षा में शामिल होता है जिसमें 100 प्रश्न है। सही हल के लिए (+1) अंक मिलेगा। जबकि 1/10 प्रश्न गलत हल के लिए (–1/10) अंक, 1/5 प्रश्न गलत हल करने पर (–1/5) अंक और शेष गलत हल प्रश्नों के लिए (–1/2) अंक मिलेगा। जो प्रश्न हल नहीं किया गया हो उसमें कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। तो अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अन्तर क्या होगा?
A)100 B)120 C)140 D) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (36–38) : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित चार्ट के आधार पर दें–

किसी परीक्षा में तीन प्रकार के टेस्ट थे। जिसमें प्रश्नों की संख्या और निर्धारित अंक भी भिन्न थे। जैसे –

टेस्ट	प्रश्नों की संख्या	(+ अंक) सही हल के लिए	(–अंक) गलत हल के लिए
A	80	4	2
B	60	3	1.5
C	60	2	1

64. यदि कोई छात्र 100 प्रश्नों को हल करके 120 अंक प्राप्त करता है तो वह अधिकतम कितना प्रश्न गलत बनाता है?
A) 44 B)56 C)60 D) इनमें से कोई नहीं

65. एक छात्र कम से कम कितना प्रश्न हल करे कि उसे 130 अंक प्राप्त हो। (यदि प्रत्येक टेस्ट से कम से कम एक प्रश्न हल करना अनिवार्य हो?
A) 34 B)35 C) 36 D) इनमें से कोई नहीं

66. प्रश्न संख्या (37) के आधार पर कम से कम कितना गलत बनायें?
A) 0 B)1 C)2 D) इनमें से कोई नहीं

67. किसी पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे को उपहार देता है तो कुल कितने प्रकार से उपहार दिया जाएगा ?
A) 90 B)100 C)110 D)120

68. किसी पार्टी में 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे?
A) 45 B)46 C)50 D)55

69. किसी पार्टी में कुछ मित्र मिले और एक दूसरे से हाथ मिलाये। यदि कुल 66 बार हाथ मिले तो कितने मित्र आये?
A) 10 B)12 C)14 D)11

SMS द्वारा उत्तर 8002817092 पर भेजें

सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रथम दस विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा। शेष अगले अंक में

लौरिया विधान सभा क्षेत्र

एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर

नौसाद अहमद | मो. जावेद | परमानंद ठाकुर | संतोष राय | शंभू तिवारी

संजय कुमार सिंह

पश्चिमी चंपारण का लौरिया विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान माना जाता है. दो प्रखंड लौरिया व योगापट्टी को मिला कर बना यह विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक व सांस्कृतिक तौर पर भी काफी सजग है. यह विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप जैसी कई विरासतें यहां विद्यमान हैं. विधानसभा में अभी उस क्षेत्र का नेतृत्व भोजपुरी सिनेमा के सशक्त स्तंभ विनय बिहारी कर रहे हैं. विगत विधानसभा चुनाव में बिहारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ कर जदयू के तत्कालीन विधायक प्रदीप सिंह को शिकस्त दिया था. आकड़ो एवं परिस्थितियों पर अगर गौर किया जाए, तो यह सीट न तो एनडीए और न ही राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन के लिये सरल साबित होगी. भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र का काफी हिस्सा गंडक के दियरा क्षेत्र का है, जिसमें फसल की बोआई काफी दुरूह समझा जाता है. उस क्षेत्र में प्रमुख फसल के रूप में धान, गन्ना, दलहन व तिलहन की अधिक खेती होती है. उद्योग के रूप में लौरिया प्रखंड मुख्यालय में एक चीनी मिल है, जहां किसान अपना गन्ना देते हैं.

इस विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर गंडक नदी बहती है. जिसके दियरा क्षेत्र में आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण यह क्षेत्र अपराधियों की शरणस्थली के रूप में कुख्यात रहा है. विगत दशक में जिस समय बिहार में अपराध चरम पर था, लोग इस क्षेत्र के योगापट्टी को अपराध का विश्वविद्यालय मानते थे. बहरहाल अभी तो अपराध की धार कुंद बतायी जाती है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की माने तो अब भी उस दियारे का समुचित विकास नहीं हुआ, तो आश्चर्य नहीं होगा.

विगत चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उस विधानसभा क्षेत्र में कुल बूथों की संख्या-210 है. उस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या- 222947 है. जिसमें महिला मतदाता-101050 तथा पुरूष मतदाताओं की संख्या-121897 है. वर्ष 2005 के हुए विधानसभा चुनाव में तत्कालीन जदयू विधायक प्रदीप सिंह को 27500 मत मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी विनय बिहारी ने 38384 मत प्राप्त कर विजय हासिल किया. वर्तमान विधायक की माने तो उनके कार्यकाल में सबसे अधिक कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है. गंडक के पार के चार प्रखडों में जाने के लिए रतवल पुल बना है. जिसका लाभ नदी के दोनों पार के स्थानीय लोगों को मिला है. साथ ही विधानसभा क्षेत्र में छोटे-बड़े पुल-पुलिया व सड़क निर्माण कराया गया है. जिसके कारण उस क्षेत्र के गांवों के बीच आवागमन काफी सुगम हुआ है. बाढ़ से निजात के लिये चंपारण तटबंध समेत अन्य तटबंधों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है.

> विगत विधानसभा चुनाव से इतर इस बार तकरीबन सभी दलों में टिकट के लिए ज्यादा मारा-मारी है. तकरीबन हर राजनीतिक दल में टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है. संभावित प्रत्याशी अभी से टिकट के जुगाड़ में लग चुके हैं. जानकारों की माने तो टिकट कटने पर कई लोग निर्दलीय भी मैदान में उतरने का मन बना कर अपनी तैयारी में अभी से लग गए हैं. ऐसा लगता है कि वर्तमान विधायक विनय बिहारी इस बार हम के टिकट पर यहां से किस्मत आजमाएंगे.

विगत विधानसभा चुनाव से इतर इस बार तकरीबन सभी दलों में टिकट के लिये ज्यादा मारा-मारी है. तकरीबन हर राजनीतिक दल में टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है. संभावित प्रत्याशी अभी से टिकट के जुगाड़ में लग चुके हैं. जानकारों की माने तो टिकट कटने पर कई लोग निर्दलीय भी मैदान में उतरने का मन बना कर अपनी तैयारी में अभी से लग गए हैं. ऐसा लगता है कि वर्तमान विधायक विनय बिहारी इस बार हम के टिकट पर यहां से किस्मत आजमायेंगे. जदयू में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ देने की एवज में उनका हम का टिकट पक्का समझा जा रहा है. सबसे ज्यादा मारा-मारी जदयू, राजद, कांग्रेस के महागठबंधन में नजर आ रहा है. तीनों दलों के नेता इस सीट को अपने खाते में मान कर उसी अनुरूप चुनाव पूर्व की तैयारी में लग गए हैं. कांग्रेस की तरफ से पमानंद ठाकुर अपनी दावेदारी इस सीट पर कर रहे हैं. वहीं तेलपुर के पैक्स अध्यक्ष मो. जावेद भी, जो पूर्व में मुखिया भी रहे हैं. इस सीट पर अपने को दावेदार मान रहे हैं. वर्ष 2005 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मो. जावेद की माने तो गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में आएगी, क्योंकि कांग्रेस की यहां समृद्ध विरासत रही है. जिस आधार पर वह चुनाव की तैयारी में लगे हैं. जदयू के लोग भी 2001 एवं 2005 के चुनाव के आधार पर इस सीट पर अपना स्वभाविक दावा मानते हैं. पूर्व विधायक प्रदीप सिंह भी 2005 के रनर अप रहने को आधार मान अपने टिकट को कनफर्म मान रहे हैं. जदयू के ही सुनील कुशवाहा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं. पार्टी के लिये किये कार्य व क्षेत्र में जनता के बीच जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव को आधार मान वह अपना टिकट कनफर्म मान कर चल रहे है. उन्हे भरोसा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो जनता के बीच उनकी पकड़ के कारण यह सीट पार्टी के खाते में जाना तय है. राजद के स्थानीय नेता भी यहां से अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं. यहां की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले पूर्व प्रखंड प्रमुख शंभू तिवारी भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं. उनकी माने तो लौरिया सीट राजद के खाते में जाएगी तथा जनता के बीच उनकी पहुंच के कारण पार्टी उन्हें टिकट देगी. बकौल शंभू तिवारी अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह पार्टी के जनाधार व अपनी लोकप्रियता के बल पर इस सीट को जीत जाएंगे.

एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में भी दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है. भाजपा के बेतिया जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं. उन्हें पार्टी से टिकट मिलने का भरोसा है. भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो जनता के बीच पार्टी के लिये किये गये काम की बदौलत इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की जीत तय है. भाजपा के विजय गुप्ता भी अभी से टिकट मिलने पर लड़ने की बात करते हैं. निकाय चुनाव में पश्चिम चंपारण से एनडीए प्रत्याशी रहे संतोष कुमार राव उर्फ बबलू राव टिकट मिलने की आस में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं. भाजपा से ही पूर्व पेट्रोलियम सचिव आरएस पाण्डेय के पुत्र को भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है. एनडीए के घटक दल लोजपा के नेता भी इस सीट पर अपनी पार्टी का दावा जता रहे हैं. लोजपा नेता ई. नौसाद अहमद भी अपनी पार्टी की दावेदारी जताते हुए अपने को यहां से पार्टी का भावी प्रत्याशी मान रहे हैं. बहरहाल टिकट जिसे भी मिले लेकिन उन्हें अपने दल के लोगों से भी पार पाने की चुनौती रहेगी. कांग्रेस नेता पूर्व प्रमुख परमानंद ठाकुर, जनवादी नेता संतोष राय सरीखे लोग भी चुनाव लड़ने की मंशा से अभी से तैयारियों में लग गए हैं. तकरीबन हर राजनीतिक दलों में एक से ज्यादा प्रत्याशियों की मौजूदगी से आगामी विधानसभा चुनाव को काफी रोचक तथा कांटे का होने की संभावना जतायी जा रही है. लेकिन टिकट देने के पूर्व तकरीबन हर दल को संभावित उम्मीदवार के बीच से विधानसभा सीट निकालने वाले प्रत्याशी की पहचान करना काफी टेढ़ी खीर साबित होने वाली है.■

feedback@chauthiduniya.com

साक्षात्कार

विकास ही मेरा मिशन : रामबालक

बाल्मिकी कुमार

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक राम बालक सिंह ने पांच सालों में अपने क्षेत्र में विकास के ढ़ेर सारे कामों के माध्यम से इस इलाके की जनता के दिलों में अपनी मजबूत जगह बना ली है. दस साल मुखिया रहते हुए भी रामबालक सिंह जनता से लगातार जुड़े रहे पर विधायक बनने के बाद क्षेत्र व जनता की सेवा को उन्होंने अपना मिशन बना लिया. अपने कामों के माध्यम से उन्होंने न केवल पिछड़े विभूतिपुर का कायाकल्प किया बल्कि पूरे जिले को एक आदर्श प्रस्तुत किया. बतौर विधायक कुछ कार्य ऐसा किया है, जो जिला स्तर पर अब तक संभव नहीं हो सका है. उन्हें वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ मिला और तब जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ कर जीत मिली. जनभावना का सम्मान करते हुए क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा समेत अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन व्यापक स्तर पर कराया. उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक, बीएड, आईटीआई कॉलेज की स्थापना विभूतिपुर में कराने का काम किया है. शिक्षा के क्षेत्र में विभूतिपुर का रिकॉर्ड आज विकास की ओर बढ़ रहा है. बूढ़ी गंडक पर सेतू निर्माण के अलावा 30 बेड अस्पताल का निर्माण करा कर लोगों को राहत दिलाने का कार्य किया है. रामबालक सिंह कहते हैं कि मेरी पहल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायदा के मुताबिक वरूणा पुल से रसिया घाट तक तकरीबन 102 किलो मीटर सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाने का कार्य किया है. पिछले 15 साल बंद पड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज को पुनः चालू कराने का कार्य किया है. कस्तूरबा व आदर्श विद्यालय की स्थापना के साथ ही 17 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रतिनिधियों का कार्यकाल रक्त रंजित रहा है, जबकि उन्होंने क्षेत्र में अमन व भाईचारा की स्थापना कराने में अहम भूमिका निभाई है. वर्तमान में जदयू गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी समर में दो-दो हाथ करने को तैयार है. जनता का आदेश मिला तो एक बार फिर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास से बाज नहीं आएंगे. रामबालक सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के असली नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में बिहार देश और दुनिया में नंबर एक राज्य बनेगा.■

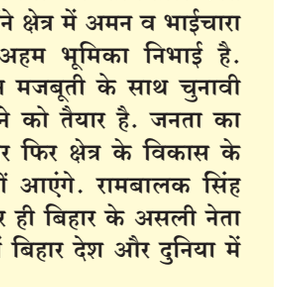

feedback@chauthiduniya.com

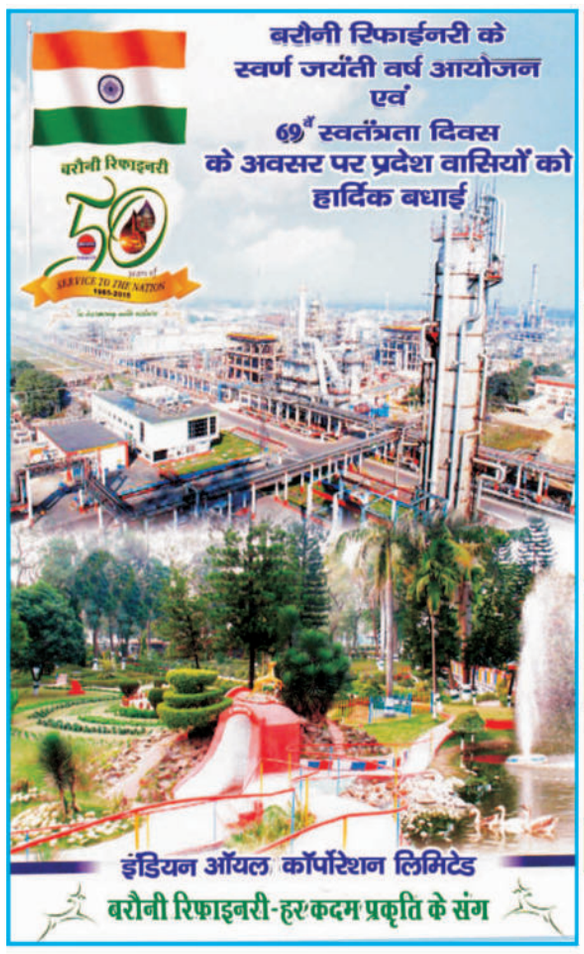

प्रस्तुति - सुरेश चौहान,
ब्यूरो चीफ, बेगूसराय
कार्यालय,
चौथी दुनिया,
बेगूसराय

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
24 अगस्त–30 अगस्त 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

राज्यपाल के चलते कानून ताक पर नहीं रख पा रहे अखिलेश

समाजवादी सरकार की नैतिक दुर्दशा

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्धारा लिए गए अनैतिक फैसले पर अपनी आपत्ति अवश्य जताते हैं. पहले अखिलेश द्धारा विधानपरिषद सदस्य के लिए भेजे गए नामों में से चार पर अपनी सहमति जताई और पांच नामों को लौटा दिया. इसके बाद सतर्कता विभाग के माध्यम से रवीन्द्र सिंह यादव को लोकायुक्त बनाने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी गई. राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1975 (संशोधन मार्च 2012) के नियम के तहत इसे देखा. कुछ बिन्दुओं पर सरकार से अलग से जानकारी मांगी और फाइल वापस कर दी.]

दिलीप अग्निहोत्री/सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक–दुदर्शा कर रखी है. जबसे राम नाईक ने प्रदेश में राज्यपाल का पद संभाला है, तब से उत्तर प्रदेश सरकार के अनैतिक फैसलों के बारे में कम से कम सांकेतिक प्रतिरोध तो अवश्य किया है. इस वजह से प्रदेश सरकार की करतूतें आम नागरिकों के समक्ष भी उजागर होती रही हैं. आप याद करें, प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में भी अखिलेश सरकार ने मनमानी करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने सूचना आयुक्तों की अखिलेश–पसंद की सूची कई बार सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी. विधान परिषद के लिए मनोनयन का मामला अभी भी लटका ही हुआ है. राज्यपाल ने केवल चार लोगों के नाम पर सहमति दी, लेकिन पांच नाम लौटा दिए. अखिलेश सरकार ने कई बार कोशिश की कि वह अपने गुर्गों को विधान परिषद तक पहुंचा दे, लेकिन राज्यपाल के संवैधानिक अड़ंगे से सरकार के निरंकुश रवैये पर अंकुश लग गया.

संविधान के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल द्वारा भेजी गई सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है. इसके अलावा राज्यपाल को कई विषयों पर स्वविवेक से भी फैसला करने का अधिकार है. राज्यपाल सचिवालय से जुड़े एक आला अधिकारी ने कहा कि यह संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत सावधान हैं. वह पुनर्विचार की शब्दावली लिखकर कभी किसी सिफारिश को लौटाते नहीं हैं. वह उन बिन्दुओं का साफतौर पर उल्लेख करते हैं, जिन संविधान के अनुरूप स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है. इसलिए उनके फैसले संविधान के प्रावधान और उसकी भावना पर आधारित होते हैं, उन पर पक्षपात या पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया जा सकता.

अभी हाल ही में राज्यपाल राम नाईक ने विधान परिषद के लिए नामित होने वाले सदस्यों की सूची पर बिन्दुवार जानकारी मांगी थी, क्योंकि राज्यपाल यह देखना चाहते थे कि संविधान में नामित सदस्यों के लिए जिस योग्यता का निर्धारण है, उस अनिवार्यता को कौन पूरा कर रहा है. इस बार राज्यपाल ने लोकायुक्त बनाने संबंधी सरकार की संस्तुति वापस लौटा दी है. सरकार ने लोकायुक्त चयन समिति में बदलाव किया था. उसके बाद रवीन्द्र सिंह यादव को लोकायुक्त बनाने की सिफारिश भेजी गई थी. लोकायुक्त का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है. भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच में वह बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है. बसपा शासन के अनेक मंत्री लोकायुक्त रिपोर्ट में ही दोषी करार दिए गए थे, लेकिन बाद में ऐसी तेजी दिखाई नहीं दी. संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यह आवश्यक है कि संविधान की भावना के अनुरूप एक पैनल का गठन हो और उसकी सहमति के बाद ही लोकायुक्त पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश की जाए. संविधान ईमानदार प्रशासन चाहता है, घोटालेबाजों व भ्रष्टाचार करने वालों को सजा की व्यवस्था विधि के तहत की गई है, लेकिन उसके पहले निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होती है. यह कार्य लोकायुक्त करता है. जाहिर है उसका निष्पक्ष होना अनिवार्य है. ऐसे में यह कार्य केवल राजनीतिक व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता. कई बार परस्पर विरोधी पार्टियां भी पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार पर आपस में सहमत लगती हैं. यही कारण है कि पुख्ता जांच व रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होती. सरकारें बदलती हैं, लेकिन वर्षों तक जांच रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई की सिफारिश ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है.

गौरतलब है कि सुप्रीमकोर्ट ने 23 जुलाई को तीस दिन के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने की अपेक्षा की थी. यह फैसला मुख्य सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर आया था. जनवरी से चल रही इस प्रक्रिया को चार अगस्त को कैबिनेट ने मंजूर किया और चार अगस्त को यह फैसला हुआ. इसके बाद सतर्कता विभाग के माध्यम से रवीन्द्र सिंह यादव को लोकायुक्त बनाने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी गई. राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1975 (संशोधन मार्च 2012) के नियम के तहत इसे देखा. कुछ बिन्दुओं पर सरकार से अलग से जानकारी मांगी और फाइल वापस कर दी. सरकार ने जो सिफारिश की थी, उसके साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ हुए विचार–विमर्श के दस्तावेज संलग्न नहीं थे. राज्यपाल ने इसी की जानकारी मांगी है.

यदि पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, तो राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी को उचित कहा जा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया सिफारिश से संलग्न नहीं बताई गई है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की चयन समिति ने तीन दौर की चर्चा के बाद हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह यादव का नाम प्रस्तावित किया. जबकि कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ ने मशविरे के लिए आए प्रस्ताव में चयन के तरीके पर एतराज जाहिर करते हुए पत्रावली वापस कर दी थी. इसके बाद से यह मामला लंबित था. पहली जुलाई को न्यायमूर्ति रवीन्द्र सिंह यादव सेवानिवृत्त भी हो गए थे. इसके बाद सरकार ने अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया.

यदि लोकायुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया देखें, तो साफ होगा कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत सभी प्रश्नों का जवाब चाहा. अधिनियम के अनुसार प्रशासनिक विभाग (सतर्कता) के मंत्री, मुख्यमंत्री व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष लोकायुक्त पद के लिए नाम का चयन करेंगे. उस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे. उनकी सलाह के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है. सहमत होने पर राज्यपाल नियुक्ति हेतु वारंट जारी करते हैं. इसके आधार पर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है. यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त पद संवैधानिक नहीं है. इसका गठन एक्ट के माध्यम से किया गया है, लेकिन इतने से ही उसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि यह संविधान की भावना पर आधारित है. इसी के अनुरूप एक्ट में प्रावधान किए गए है और इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्धारण किया गया है.

जाहिर है राज्यपाल ने न तो लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, न ही उसमें शामिल किसी व्यक्ति की मंशा पर प्रश्न उठाया है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान हुए पत्राचार से पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. कानूनविदों का भी कहना है कि लोकायुक्त पद की नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी व विवाद रहित होनी चाहिए. राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यपाल को लिखना पड़ा था पत्र

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट में संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय से ली गई मंजूरी का पालन करने में प्रदेश सरकार की ढिलाई पर राज्यपाल राम नाइक ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चन्द्रचूड़ और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा था. राज्यपाल ने विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या और वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा को भी पत्र लिख कर अपने स्तर पर कदम उठाने के लिए कहा था. एक लंबे अर्से से प्रदेश सरकार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद पर नई नियुक्तियां करने का मामला लटकाए हुई है. राज्यपाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार समय पर सरकार की सिफारिश का नहीं होना चिन्ता का विषय है. इस बारे में राजभवन की तरफ से 17 मार्च को राज्य सरकार को पत्र भेज कर अवगत कराया गया था. 24 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर सरकार को छह महीने के अंदर नई नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया था. राज्यपाल राम नाईक ने इन खाली पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने का मामला राष्ट्रपति के समक्ष भी उठाया था. ■

आठ साल तक रहेंगे लोकायुक्त

2012 से पहले उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट के मुताबिक लोकायुक्त का कार्यकाल छह साल तक होता था. 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने एक्ट में संशोधन कर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर आठ साल कर दिया. साथ ही लोकायुक्त कानून के सेक्शन 5(3) में भी संशोधन किया गया था. इसके मुताबिक लोकायुक्त पद पर कार्यकाल पूरा करने वाला व्यक्ति इस पद के लिए दोबारा भी चयनित किया जा सकता है. इस संशोधन पर सुप्रीमकोर्ट की भी मुहर लग चुकी है. ■

सरकार की तेजी काम न आई

प्रदेश के नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जितनी तेजी दिखा रही थी, उतनी ही तेजी से राजभवन के आगे मुंह के बल गिरी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक द्वारा मांगी गई सूचनाओं के साथ लोकायुक्त की नियुक्ति वाली फाइल दोपहर में दो बजे राजभवन भेजी और राज्यपाल ने फाइल का परीक्षण कर चार बजे उसे सरकार को वापस भी भेज दी. राज्यपाल ने अखिलेश से स्पष्ट कह दिया कि लोकायुक्त के चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा–3 के प्रावधानों के तहत पूरी नहीं की गई है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने लोकायुक्त के लिए सरकार की तरफ से केवल एक नाम भेजे जाने पर आपत्ति जताते हुए इसके लिए बाकायदा नामों का पैनल तैयार कर लोकायुक्त के चयन के लिए तीन सदस्यों की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था. लेकिन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की सलाह को दबाए रखा और अपनी मनमानी करते हुए फिर से रवींद्र सिंह यादव का एक नाम लोकायुक्त पद के लिए भेज दिया. लोकायुक्त की नियुक्ति का मसला संवैधानिक पेंच में बुरी तरह फंस जाने के बाद राज्य सरकार ने अब इस मसले पर कानूनी सलाह मशविरा लेना शुरू किया है, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ना चाहती है, जहां वह जिद किए बैठी है. ■

- सरकार की तेजी काम न आई
- लोकायुक्त का कार्यकाल आठ साल का होगा
- राज्यपाल अखिलेश के मनसूबों पर पानी फेर रहे हैं
- लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया सही नहीं है
- लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल राज्यपाल ने लौटाई

लंबे अर्से तक लोकायुक्त बने रहे मेहरोत्रा

न्यायमूर्ति एनके मोहरोत्रा की उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद पर 16 मार्च, 2006 को नियुक्ति हुई थी. एक्ट में संशोधन के बाद श्री मेहरोत्रा 15 मार्च 2014 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके. नए लोकायुक्त की नियुक्ति होने तक वह इस पद पर बने रहेंगे. जबकि सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त मेहरोत्रा का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने के अंदर नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. लेकिन अखिलेश सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और हैं. ■

भाजपा का यह कृत्य अन्य पार्टियों के लिए मददगार साबित हो रहा है. बीते लोकसभा चुनाव में तो यहां तक चर्चा थी कि भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा का जिला संगठन काम करता दिख रहा था, लेकिन वोट मांग रहा था दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के लिए. आज भी भाजपा के ज्यादातर जिम्मेदार लोग प्रदेश में सत्तासीन समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री के आस-पास ही दिखाई देते हैं. इससे आम जनता में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि चोर-चोर मौसेरे भाइयों में आखिर किस भाई पर भरोसा करें.

रायबरेली में भाजपा ख़त्म हो रही है

भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत पार्टी से करोड़ों लोगों को जोड़कर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन रायबरेली में इसके बिल्कुल उलट हो रहा है. वहां भाजपा का जनाधार घटता जा रहा है. पार्टी नेतृत्व के कोशिशों के बावजूद वहां के नेता पार्टी के जनाधार को बचाने में नाकाम हो रहे हैं.

पंकज सिंह

रायबरेली में भाजपा संगठन कई टुकड़ों में बंट चुका है. भाजपा की मृतप्राय इस इकाई को पुर्नजीवित करने के लिए प्रदेश के सदस्यता अभियान प्रभारी व महामंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कई बार ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन वे संगठन में जान फूंकने में विफल रहे. रायबरेली में भाजपा का संगठन दिशाहीन हो चुका है. पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि रायबरेली इकाई में न तो अनुशासन है और न ही कोई अभिभावक. आम शिकायत है कि जिलाध्यक्ष अजय त्रिपाठी अपने कुछ सिपहसालारों को लेकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं. वहीं अतुल सिंह, सुशील शर्मा, डा.धनंजय सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, पशुपतिनाथ बाजपेयी, अनीता श्रीवास्तव जैसे लोग जो भाजपा का झंडा लगाकर घूमते हैं, वे भी पार्टी के गैर-उत्पादक ही साबित हो रहे हैं. सदस्यता अभियान प्रभारी स्वतंत्रदेव सिंह की अगुआई में रायबरेली में सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से चला, लेकिन उसमें भी संगठन के कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं दिखाई दी. प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता अपने को हाईकमान की नजरों में स्थान बनाने की फिक्र में ही लगा रहता है. रायबरेली में भाजपा नए वोटरों को जोड़ने के बजाय अपना वोट बैंक खोने में कोई कोर कसर नही छोड़ रही है. भाजपा का यह कृत्य अन्य पार्टियों के लिए मददगार साबित हो रहा है. बीते लोकसभा चुनाव में तो यहां तक चर्चा थी कि भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा का जिला संगठन काम करता दिख रहा था, लेकिन वोट मांग रहा था दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के लिए. आज भी भाजपा के ज्यादातर जिम्मेदार लोग प्रदेश में सत्तासीन समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री के आस-पास ही दिखाई देते हैं. इससे आम जनता में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि चोर-चोर मौसेरे भाइयों में आखिर किस भाई पर भरोसा करें. सही भी है, आम जनता मतिभ्रम जैसी स्थिति में है. आम जनता भाजपा नेताओं के सामान्य ज्ञान पर मखौल उड़ाती नजर आती है. जब लोगों के समक्ष यह उजागर होता है कि भाजपाइयों को अपनी पार्टी के प्रेरणाश्रोत के जन्म दिवस और पुण्यतिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के भाजपा मंत्री व जिले के सम्पर्क महाभियान के प्रभारी वीरेन्द्र तिवारी की अगुवाई में जिलाध्यक्ष अजय त्रिपाठी, सदर विधानसभा प्रभारी अनुभव कक्कड़, विजय प्रताप सिंह, पप्पू लोहिया आदि दिग्गजों ने जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना डाली. जबकि डा. मुखर्जी की यह जयंती नहीं बल्कि उनकी पुण्यतिथि थी. इस बाबत जिलाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बाकायदा अपने लेटर पैड पर इन दिग्गजों के साथ-साथ सारे अखबारनवीसों के पास भी पत्र भेज दिया. आम जनता में भी खूब किरकिरी हुई.

- भाजपा नेता धन वसूली में लगे हैं.
- पार्टी नेता पर मारने की धमकी देने का आरोप.
- पार्टी संगठन कई गुटों में बंट चुका है.
- नेताओं को संस्थापक की जयंती तक नहीं मालूम.
- भाजपाई सपा सरकार के मंत्री के पीछे घूमते हैं.

राजनीति छोड़ रंगदारी वसूल रहे भाजपाई

रायबरेली में भाजपा संगठन को खड़ा करने और उसे ताकतवर बनाने की कवायद छोड़ कर भाजपा नेता धन उगाही के धंधे में लगे हैं. साफ-सुथरी छवि वाले प्रधानमंत्री की पार्टी के स्थानीय नेताओं पर रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने वाली जेएमसी कंपनी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी टैक्स मांगने और धमकी देने का आरोप है. इस मामले में भाजपा के स्थानीय नेता पुष्पेन्द्र सिंह पर बाकायदा दो अलग-अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं. पुलिस कहती है कि एम्स बनाने वाली कंपनी जेएमसी के प्रोजेक्ट मैनेजर कैलाश चन्द्र ने शहर कोतवाली थाने में भाजपा नेता पुष्पेन्द्र सिंह के विरुद्ध दो करोड़ रुपये की रंगदारी मागने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी. तहरीर में आरोप है कि भाजपा नेता ने रंगदारी न देने पर काम बंद करवाने की धमकी भी दी. यही नहीं पुष्पेन्द्र सिंह पर भदोखर थाने में कंपनी के एक अन्य कर्मचारी स्वप्नेश तिमोथी ने भी जान से मारने की धमकी की तहरीर दे रखी है. पुलिस ने भाजपा नेता पुष्पेन्द्र सिंह के विरुद्ध दोनों थानो में रिपोर्ट दर्ज कर जाच शुरू कर दी है. बताया जाता है कि भाजपा नेता पुष्पेन्द्र सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज रहे हैं. ■

रायबरेली के लिए यह कठोर सच है कि यहां के भाजपाई मठाधीश विपक्षी राजनीतिक दलो से भिड़ने के बजाय अपनों पर ही घात लगाते रहते हैं. बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी रायबरेली पहुंचे तो वहां जिली स्तर का कोई भी पदाधिकारी नजर नहीं आया. बसपा से भाजपा में आए एक नेता ने अपने समर्थकों के साथ बाजपेयी जी का स्वागत कर अपनी सक्रियता का परिचय दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूंजी निवेश और रोजगार की संभावनाएं तलाशने का प्रहसन शुरू

पंचायत चुनाव जीतने का दांव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और प्रतिष्ठा का सवाल बने पंचायत चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी तरह-तरह के पैंतरे अपना रही है. इसी के तहत अखिलेश तीन साल बीत जाने के बाद अब प्रदेश में पूंजी निवेश का माहौल बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं.

अंशुमान प्रांजल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले करीब साढ़े तीन साल प्रदेश में निवेश लाने के नाम पर विदेशों में तफरीह करते रहे और विभिन्न प्रदेशों में जा-जाकर सियासत का निवेश करते रहे. उत्तर प्रदेश की लचर ढांचागत व्यवस्था और फटीचर कानून व्यवस्था के कारण नगण्य पूंजी निवेश हुआ. अब अखिलेश सरकार जाते-जाते फिर से पूंजी निवेश की कवायद के नाम पर कुछ धंधा शुरू कर रही है. अभी पंचायत चुनाव सिर पर है और इस चुनाव को जीतना समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत जरूरी है. राजनीतिक-आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि पंचायत चुनाव के ठीक पहले पूंजी निवेश और रोजगार की भारी संभावनाओं के फिर से शुरू हुए चर्चे चुनाव जीतने का गुलगुला है, जो विधानसभा चुनाव के आते-आते काफी जोर पकड़ेगा, पर हासिल कुछ नहीं होने वाला. प्रदेशभर में पंचायत चुनाव की मुनादी हो चुकी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो जाएगी. ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश में पूंजी निवेश का माहौल बनाने के लिए मुम्बई में कवायद कर रहे हैं. अभी ही जुलाई महीने में मुख्यमंत्री ने अपने ही घर से तमाम परियोजनाओं का करार और बटन दबा कर उद्घाटन करते हुए कहा कि नई निवेश नीति बनने के बाद प्रदेश में नौ नए मेगा प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं. इन नौ प्रोजेक्ट में चार पूर्वांचल व मध्यांचल में हैं. इनसे अगले पांच साल में करीब 7500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 22 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया और प्रदेश के आम नागरिकों को एक और झांसा दिया. जब सरकार के साढ़े तीन साल पूरे हो गए तब यह कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में निवेश की औपचारिकताएं अगले पांच साल में पूरी होंगी. कब पैसा लगेगा, कब प्रोजेक्ट शुरू होगा, कब लोगों को रोजगार मिलेगा और तब तक अखिलेश सत्ता-सुख भोगते रहें. आपको याद ही होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोबाइल हैंडसेट कंपनी स्पाइस के नुमाइंदों के साथ करार करते हुए कहा था कि कंपनी 500 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश में मोबाइल कारखाना लगाएगी. स्पाइस ग्रुप के चेयरमैन दिलीप मोदी की खूब आवभगत भी हुई, लेकिन कंपनी का काम कहां चल रहा है, कारखना कहां खड़ा हो रहा है इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

राज्य सरकार एसोचेम की रिपोर्ट का हर तरफ ढोलक बजा-बजा कर निवेश जुटाने का उपक्रम करती दिखती है, लेकिन निवेश नदारद है. इससे एसोचेम की रिपोर्ट की साख पर भी असर पड़ा है. एसोचेम के महासचिव डीएस रावत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ अधिक ही प्रभावित थे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बहुत बेहतर हुआ है और प्रदेश में बड़ी तीव्र गति से निवेश आ रहा है. एसोचेम के महासचिव यूपी में निवेश का कोई आंकड़ा तो प्रस्तुत नहीं कर पाए. रावत ने यूपी के ब्रांड अम्बैसेडर का प्रहसन खेलते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी अब उल्टा प्रदेश नहीं रहा. यूपी में सुधार की बात आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट या अध्ययन के आधार पर कहा या यह केवल धारणा है? रावत ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया. बहरहाल, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के नवीन अवसरों को तलाशने के लिए किए जा रहे प्रयास के क्रम में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 10 सितम्बर को मुम्बई में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शरीक रहेंगे. उक्त सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव सहित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शीर्ष नेतृत्व, उद्यमी एवं निवेशकगण भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक भावी निवेशकों के साथ प्रस्तावित एजेण्डा के अनुसार बातचीत की जाएगी. उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म नीति को कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा और सम्मेलन के जरिये प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. श्री रंजन ने कहा कि निवेशक सम्मेलन में राज्य सरकार के कई उद्देश्यों की पूर्ति होगी. उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से राज्य के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं को हाई-लाइट किया जाएगा. ■

दावे तो बहुत, पर सच क्या है!

सरकारी फ्रंट से लेकर राजनीतिक फ्रंट तक सपा यूपी में पूंजी निवेश के खूब ढिंढोरे पीटती रही है, लेकिन प्रदेश को हकीकत में जमीनी स्तर पर क्या प्राप्त हुआ, इस बारे में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं दिखा. राजनीतिक फ्रंट संभालते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर काफी पूंजी निवेश हुआ है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं. इसके लिए आवश्यक वातावरण बनाने के लिए उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष बल दिया है. चौधरी बताते हैं कि समाजवादी सरकार को प्रदेश में 8700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों से मिले हैं. रिलायंस, आईटीसी, एस्सेल, एमिटी, फोर्टिस, गेल, एग्रो, डंकन गोयनका, श्री सीमेंट्स जैसे समूहों ने राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए हैं. इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं में 42,500 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में हुए निवेशक सम्मेलन के अच्छे परिणाम आए और अब मुम्बई में होने जा रहे निवेशक सम्मेलन के भी अच्छे परिणाम आएंगे. उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है और इसी क्रम में निवेशक मित्र योजना और औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली शुरू की गई है. राजेंद्र चौधरी के मुताबिक सरकार को प्रदेश में 8700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों से मिले हैं, लेकिन उनके उद्योग कहां-कहां शुरू हुए और उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, इस बारे में राजेंद्र चौधरी कुछ नहीं कहते. सरकारी दावा यह है कि 2012-13 और 2013-14 में राज्य में 11872.58 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें कुल 7,76831 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और 1,49,729 परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे. निवेश मित्र योजना के तहत अब प्रदेश में सभी लघु मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिससे मानव हस्तक्षेप में कमी हो और उद्यम स्थापित करने के लिए सभी सूचनाएं समय से उपलब्ध होंगी. भविष्य में रोजगार कब उपलब्ध होंगे और उद्योग की स्थापना में कितना समय लगेगा, इसका आकलन करना और निर्धारित समय में उद्योग खड़ा करने की पूंजीपतियों के समक्ष अनिवार्य शर्त रखने जैसा कोई सरकारी प्रावधान नहीं है और न ही इसे मॉनीटर करने की कोई मुकम्मल शासनिक व्यवस्था है. ■

सबसे गंदी राजधानियों में देहरादून

ब्यूरो कार्यालय

केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में स्वच्छ भारत को लेकर प्रदेशों की राजधानियों की रैंकिग पेश की गई है, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देश की सबसे गंदी तीन राजधानियों में शामिल है. देहरादून की साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम पर है और निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, केन्द्र में भाजपा की सरकार है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद स्वच्छ भारत मिशन का खूब जोर-शोर से प्रचार प्रसार किया था. यही नहीं तब भाजपा नेताओं ने भी भारत स्वच्छता मिशन को लेकर खूब उत्साह दिखाया था और खूब फोटो भी खिंचवाए थे. 2014-15 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय का सर्वे भाजपाईयों की पोल खोल रहा है. अभियान की प्रदेश में हकीकत क्या है. केंद्र की इस रैंकिंग में उत्तरखंड की राजधानी देहरादून को अंतिम तीन में यानी 360वां रैंक मिला है. इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर और बिहार की राजधानी पटना है, जबकि राजधानियों की श्रेणी में बैंगलोर पहले स्थान पर है. इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के 61, पश्चिम बंगाल के 60, महाराष्ट्र के 43, मध्य प्रदेश के 32, गुजरात के 30, आंध्र प्रदेश के 30, तमिलनाडु के 29, राजस्थान के 28, बिहार के 27, कर्नाटक के 26, हरियाणा के 20, पंजाब के 16, तेलंगाना के 11, ओडिशा के 10, झारखंड के 10, छत्तीसगढ़ के 9 और केरल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों से 6-6 शहर शामिल किए गए थे. सर्वेक्षण में देश के 476 शहरों की स्वच्छ भारत श्रेणी में कर्नाटक के मैसूर शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. इसके अलावा कर्नाटक राज्य के ही तीन और शहर प्रमुख दस शहरों की श्रेणी में है. प्रमुख 100 शहरों में स्थान पाने वाले पश्चिम बंगाल के 25 शहर व कस्बों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इन श्रेणियों के तहत खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन शामिल है. इस संदर्भ में मैसूर शहर ने न्यूनतम स्तर पर खुले में शौच जैसी व्यवस्था और बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाने में प्रमुख भूमिका निभाई. दक्षिणी राज्यों के मामले में प्रमुख 100 शहरों में से 39 शहर रहे हैं, इसके उपरांत पूर्व से 27, पश्चिम से 15, उत्तर से 12 और पूर्वोत्तर राज्यों से 7 शहर रहे हैं. सबसे नीचे के 100 शहरों में उत्तर से 74 शहर, पूर्व से 21, पश्चिम से 3 और दक्षिण से 2 शहर रहे हैं. 10 प्रमुख शहरों की श्रेणी में मैसूर, त्रिचिरापल्ली (तमिलनाडु), नवी मुंबई, कोच्चि (केरल), हसन, मंडेया और बैंगलोर (कर्नाटक), तिरूवनन्तपुरम (केरल), हलीसहर (पश्चिम बंगाल) और गंगटोक (सिक्किम) हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव आते ही जनता की भावना भूनाने के लिए राजधानी गैरसैंण-गैरसैंण का जुमला उछाल दिया जाता है. 2017 के चुनाव को देखते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर कांग्रेस में ही उठे लेटर वॉर के कारण सियासी संग्राम शुरू हो गया है. गैरसैंण में 21 सितम्बर 2015 से एक हफ्ते के विधानसभा सत्र के आयोजन की घोषणा क्या हुई कि कांग्रेसियों में ही इस आयोजन को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजन को फिजूलखर्ची करार दिया है.

कानून व्यवस्था में बदहाल प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली

सत्ता की प्राथमिकताएं कुछ और हैं

उत्तर प्रदेश में आईपीएस के सबसे अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार मस्त है. यूपी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के 129 पद खाली हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देशभर में आईपीएस अधिकारियों के कुल 4,754 पदों में से 906 पद खाली हैं.

रामभरोसे लाल

उत्तर प्रदेश सरकार को सच सुनना पसंद नहीं. इसीलिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को खुलेआम धमकिया देने जाने से लेकर किस्म-किस्म की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं. दूसरी तरफ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर भी सरकार अपने सारे उत्पीड़नात्मक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन यूपी सरकार इसे दुरुस्त करने के बजाय अपनी अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करने में मशगूल है. कानून व्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए प्रदेश में अर्से से खाली पड़े आईपीएस के सैकड़ों पदों पर अधिकारियों को तैनात करना होगा. अब मायावती काल की तरह कोई अफसर समाजवादी सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहता. आधिकारिक तथ्य है कि देश में आईपीएस के 900 से भी ज्यादा पद खाली हैं और इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल है. उत्तर प्रदेश में आईपीएस के सबसे अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार मस्त है. यूपी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के 129 पद खाली हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देशभर में आईपीएस अधिकारियों के कुल 4,754 पदों में से 906 पद खाली हैं. देश में कुल 3,848 पदों पर आईपीएस अधिकारी तैनात हैं. इसके अलावा आईपीएस के वर्ष 2014 बैच के 145 प्रोबेशनर भी हैं. पश्चिम बंगाल में आईपीएस के 98 पद, ओडीशा में 79 पद, महाराष्ट्र में 62 और कर्नाटक में 59 पद खाली हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में आईपीएस के खाली पदों की संख्या करीब डेढ़ सौ है. केंद्रशासित प्रदेश कैडर में आईपीएस अधिकारियों के कुल मंजूर पदों की संख्या 295 है और इस कैडर में 53 पद खाली हैं. उत्तर प्रदेश में आईपीएस के खाली पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न तो केंद्र सरकार पर कोई दबाव बनाया जा रहा और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत आम जनता के लिए चिंता का विषय है. इसके लिए सरकार को अनिवार्य कदम उठाने की जरूरत है. लेकिन आईपीएस के खाली पदों को लेकर सरकार मौन साधे बैठी थी. वह तो गनीमत है कि सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत जानकारी मांगने के बाद इसका खुलासा हुआ और लोगों को पता चला कि प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 129 पद खाली हैं. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन पदों का फौरन भरा जाना अत्यंत जरूरी है. आरटीआइ एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने गृह मंत्रालय में आरटीआइ दाखिल की थी. गृह मंत्रालय के उप सचिव (पुलिस) एवं जनसूचना अधिकारी जीसी यादव ने उन्हें इसका जवाब भेजा. आरटीआइ के जरिए ही यह जानकारी मिलती है कि देशभर में भारतीय पुलिस सेवा के कुल 906 पद खाली पड़े हैं, जिनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में खाली हैं. उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में आईपीएस अधिकारियों की कमी अत्यंत चिंता का विषय है. प्रदेश की लचर कानून-व्यवस्था ने पूरे शासनिक-प्रशासनिक तंत्र को बदनाम कर रखा है. एक तरफ उत्तर प्रदेश में आईपीएस के 517 पद में से 129 से अधिक पद रिक्त हैं, तो दूसरी तरफ चौंकाने वाली सूचना यह है कि जून 2014 में ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इन कमियों को स्वीकृत करते हुए अपने अधिकारियों से इस खाई को पाटने के लिए खाका तैयार करने को कहा था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और राज्य सरकार भी निश्चिंत बैठी हुई है. ■

- यूपी में आईपीएस के लगभग डेढ़ सौ पद खाली हैं.
- सपा सरकार में लगभग 622 से अधिक पुलिस कर्मियों पर हमले हुए.
- आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का उत्पीड़न कर रही है सरकार.
- सरकार से जनता की उम्मीदें टूटने लगी हैं.

जब पुलिस पर होंगे हमले, तो कानून व्यवस्था का क्या होगा!

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के दुस्साहस और कानून व्यवस्था की दयनीय हालत का इसी से पता चलता है कि पुलिस वाले भी अपराधियों के हमलों का शिकार हो रहे हैं. आम लोग तो त्रस्त हैं ही. उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हो रहे हमलों के आधिकारिक आंकड़े देखेंगे तो आपको हैरत होगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हो रहे विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार खुद यह स्वीकार कर चुकी है कि सपा के शासनकाल में अपराधियों ने पुलिस पर साढ़े छह सौ हमले किए. सरकार इसे 622 हमले बताती है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल है. बदमाशों के हाथों पुलिसवाले शहीद हो रहे हैं और सरकार उसका ब्यौरा नहीं देती. जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है. वरिष्ठ पत्रकार अजमत जमील सिद्दीकी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं. अब यह जनमत बन रहा है कि अखिलेख यादव उत्तर प्रदेश को संभाल पाने में सक्षम साबित नहीं हुए, वे मुख्यमंत्री के तौर पर फेल हैं. सारे विवादों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आता रहा, तो स्वाभाविक है कि कानून व्यवस्था पर इसका असर आएगा और अराजकता फैलेगी. जब मंत्रियों का नाम भ्रष्टाचार के अलावा किसी को पिटवाने, पत्रकार की हत्या कराने, जमीन पर कब्जे कराने, पशुओं की तस्करी कराने, बलात्कार करने, सार्वजनिक स्थल पर दंगा-फसाद करने और अपराधियों जैसे सारे कारनामों को अंजाम देने में रहेगा, तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार-बार अखिलेश यादव को आगाह करते रहे और उनकी सरकार के मंत्रियों की करतूतों और नेताओं की हरकतों के बारे में बताते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की नसीहतों की तरफ ध्यान नहीं दिया. इससे प्रदेशभर में अराजकता का माहौल सृजित हो गया. सिद्दीकी कहते हैं कि जब मंत्रियों और नेताओं को गुंडागर्दी की छूट मिलेगी तो अपराधी दुस्साहसी तो हो ही जाएंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश के मंत्रियों को कानून का खौफ नहीं रहा है. सारे नियम-कानून केवल आम आदमी पर ही लागू हो रहे हैं. पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को सरकार ने किस तरह संरक्षण दिया, वह सबके सामने है. भ्रष्टाचार के पर्यायवाची यादव सिंह की सरकारी हिफाजत में मुख्यमंत्री का असली रंग सामने आ चुका है. भ्रष्टाचार के दूसरे संकेत-पुरुष खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मिल रहा सीधा सत्ताई-संरक्षण भी तो राज-काज की गंदी हरकतों की तरफ ही तो इशारा कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

राधे मां एवं सचिन उर्फ सच्चिदानन्द गिरी जूना अखाड़े से निलंबित

अवधेशानन्द गिरी

जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि राधे मां एवं सचिन उर्फ सच्चिदानन्द गिरी को जूना अखाड़े ने निलंबित कर दिया गया वह अब तक निलंबित ही हैं. सनातन धर्म की मूल भवना त्याग, तपस्या एवं समाज सेवा को नकार कर मनी, माफिया के दबाव में राजनेताओं के प्रभाव में आकर संत समाज अपनी मूल भावना से भटक रहा है, जिसे लेकर पूरे धर्म नगरी हरिद्वार में मौलिक संतों अखाड़ों में असंतोष व्याप्त है. अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता संत हठयोगी जी मानते हैं कि जिस भावना से सनातन धर्म को बचाने का काम अदिगुरू शंकराचार्य जी ने करते हुए धर्म ध्वजा लहराई इसे मटियामेट करने के लिए षड़यंत्र चल रहा है. ऐसे संत इसी का एक उदाहरण हैं. श्रीजयराम सस्थाओं के पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का मानना है कि सनातन धर्म मानस की पंक्ति-निर्मल मन सो मोहि पावा, जासू कपट क्षल छिद्र न भावा पर आधारित है. कपटी, लम्पट, दागी को इसमें पूरी तरह निषेध है. ब्रह्मचारी जी ने जूना पीठाधीश्वर के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है.

गिरी जी का मानना है कि अखाड़े ने अभी इनको बर्खास्त नहीं किया है. बर्खास्तगी का निर्णय अखाड़े की कार्यकारिणी ले सकती है. गौरतलब है खबर फैली थी कि राधे मां को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है. चर्चा है कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में राधे मां को क्लीनचिट दी थी. इसके बावजूद अखाड़े ने अभी तक उनके पद को निलंबित ही रखा है. विवादों में आईं राधे मां के बारे में अंतिम फैसला इस समय नासिक में मौजूद अखाड़े की कार्यकारिणी ले सकती है.

टेलीफोन पर दिल्ली से स्वामी अवधेशानंद गिरि ने बताया कि प्रकरण के सामने आने के बाद अखाड़े ने राधे मां एवं सचिन उर्फ सच्चिदानन्द गिरी को निलंबित कर दिया था. निलंबन कर जांच समिति गठित की गई थी. जिसकी रिपोर्ट अखाड़े की कार्यकारिणी के पास है. रिपोर्ट पर कार्यकारिणी को ही फैसला करना है. निर्णय होने तक राधे मां एवं सचिन उर्फ सच्चिदानन्द गिरी निलंबित रहेंगी और जूना अखाड़े अथवा कुंभ के किसी आयोजन में अखाड़े के साथ भाग नहीं लेंगी. जूना अखाड़े ने 31 जुलाई 2012 की आधी रात में राधे मां को चुपचाप हरिद्वार के अखाड़े में महामंडलेश्वर पद की उपाधि प्रदान की थी. इसकी खबर जब संत जगत को लगी तो रोष जताया गया. अखाड़े की कार्यकारिणी के बाद राधे मां एवं सचिन उर्फ सच्चिदानन्द गिरी को निलंबित कर दिया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

गैरसैंण में विधानसभा सत्र पर हंगामा क्यों

राजकुमार शर्मा

पंद्रह साल पहले जब उत्तराखंड बना तब सभी राजधानी के लिए गैरसैंण के नाम पर सहमत थे, लेकिन भाजपा-कांग्रेस दोनों दलों के स्थानीय नेताओं ने अपनी सुविधा के लिहाज से दून घाटी को अस्थाई राजधानी बना लिया. चुनाव आते ही जनता की भावना भूनाने के लिए राजधानी गैरसैंण-गैरसैंण का जुमला उछाल दिया जाता है. 2017 के चुनाव का देखते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर कांग्रेस में ही उठे लेटर वॉर के कारण सियासी संग्राम शुरू हो गया है. गैरसैंण में 21 सितम्बर 2015 से एक हफ्ते के विधानसभा सत्र के आयोजन की घोषणा क्या हुई कि कांग्रेसियों में ही इस आयोजन को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजन को फिजूलखर्ची करार दिया है. उनका कहना है कि टेंट में सत्र का आयोजन करना काफी खर्चीला होगा. बहुगुणा के इस तरह के लेटर बम से कांग्रेसी सियासत में घमासान हो गया है. दूसरी तरफ, वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल गैरसैंण के खुले समर्थन में आ गए हैं. डिप्टी स्पीकर व क्षेत्रीय विधायक डा. अनुसूया प्रसाद मैखुरी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण एजेंडे की शुरुआत की थी. मुख्यमंत्री हरीश रावत भी गैरसैंण मसले को गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि गैरसैंण से पूरे पर्वतीय जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इसलिए सत्र का आयोजन निश्चित ही सराहनीय कदम है. वैसे जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र व हिमाचल में भी अन्य स्थानों पर सत्र आयोजित होते रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

केंद्र की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हरीश नाराज

रेनू शर्मा

स्टिंग ऑपरेशन में फंसे मुख्यमंत्री हरीश रावत के पूर्व सचिव मोहम्मद शाहिद पर केंद्र की ओर से की गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे एक तरफा बताया. इन्होंने कहा कि केंद्र का यह फैसला संघ व राज्य के रिश्तों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा में हिम्मत है, तो वह दावा करे कि स्टिंग उसी ने कराया और वह सौ फीसद सही है. साथ ही सीडी से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए, ताकि मुकदमा दर्ज कर जांच करायी जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मामले की न्यायिक जांच या अन्य उच्च स्तरीय जांच के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रकरण को ले जाने के लिए भी तैयार हैं. पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश पर आईएएस अधिकारी मोहम्मद शाहिद को कार्यमुक्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्टिंग प्रकरण की जांच का हवाला देते हुए केंद्र से उन्हें कार्यमुक्त करने में असमर्थता व्यक्त की थी, केंद्र सरकार द्वारा एक तरफा उन्हें वापस बुला लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने एफएल-2 के संबंध में कथित स्टिंग प्रकरण को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वे सरकार के फैसले से मेल ही नहीं खाते. ऐसे में इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है. उन्होंने बताया कि प्रकरण पर भाजपा की ओर से राजभवन को जो सीडी दी गई वह भी ओरिजिनल नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठा प्रचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सही है, तो जांच में सहयोग करे और असली सीडी उपलब्ध कराए, ताकि इसकी फारेंसिक जांच हो सके और मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जाए. उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा का काम केवल आरोप लगाना है. सरकार तथ्यों की जांच करती है. भाजपा का दायित्व है कि वह समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराए. यदि दस्तावेज उपलब्ध कराए गए तो निश्चित रूप से जांच होगी. केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर शाहिद को तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया था. पत्र में अल्टीमेटम भी दिया गया है कि यदि शाहिद ने 11 अगस्त को शाम पांच बजे तक केंद्र में ज्वाइनिंग नहीं दी, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस मोहम्मद शाहिद की उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी थी. इस संबंध में मुख्य सचिव को केंद्र की ओर से 27 जुलाई को पत्र मिला था. 28 जुलाई को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. 1998 बैच गुजरात कैडर के आइएएस मोहम्मद शाहिद 13 जुलाई 2016 तक उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति पर थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश ने कहा कि सिस्टम लागू होने से विकास की नई-नई जानकारियां किसानों तक पहुंचेगी और गांवों की स्थिति भी सुधरेगी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनेगा. खेती अधिक लाभदायक और उन्नत होगी. उन्होंने कहा कि इसको लांच करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है. सूचना अपने में एक ताकत है. अखिलेश-ऐप के जरिए अब लोग बेहतर ढंग से अपडेट रह सकेंगे. यह उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के मुकाबले डिजिटल सक्रिय बनाने में एक बड़ा कदम होगा.

बच्चों की गुमशुदगी पर अधिकारियों की मुस्कान

केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2011 से 2014 के बीच देश में तीन लाख 28 हजार बच्चे लापता हुए. एक लाख बच्चे हर साल देश भर से गायब हो रहे हैं. इनमें चालीस हजार बच्चों का अपहरण हो रहा है. 44 हजार बच्चे गायब हो रहे हैं. एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है.

वैष्णवी वंदना

- हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है
- तीन साल के भीतर तीन लाख 28 हजार बच्चे लापता हुए
- बच्चों की गुमशुदगी के मामले में यूपी नंबर एक पर है
- दुनिया में सबसे अधिक बालश्रमिक भारत में हैं
- बच्चों का कद सामान्य से कम हो रहा है

कोई बच्चों के नाम पर नोबेल पुरस्कार ले रहा है, तो कोई पानी के नाम मैगसेसे. हर तरफ पैसे और पुरस्कारों की छीन-झपट मची हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बच्चों की त्रासदी कम नहीं हो रही है. प्रदेश से बच्चे अंधाधुंध लापता हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वे बच्चे आखिर कहां जा रहे हैं? हालांकि केंद्र सरकार ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एक योजना शुरू भी की, लेकिन सरकार का यह प्रयास बिल्कुल औपचारिकता मात्र साबित हुआ, क्योंकि इस योजना को महज एक महीने के लिए चलाया गया. जबकि इसके लगातार चलाए जाने की जरूरत है. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही बताती है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक बच्चे गायब हो रहे हैं. लापता बच्चों के जो आंकड़े सामने हैं, वह भयावह हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2011 से 2014 के बीच देश में तीन लाख 28 हजार बच्चे लापता हुए. एक लाख बच्चे हर साल देश भर से गायब हो रहे हैं. इनमें चालीस हजार बच्चों का अपहरण हो रहा है. 44 हजार बच्चे गायब हो रहे हैं. एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है. उत्तर प्रदेश में हालात बदतर हैं. यहां सबसे अधिक बच्चे असुरक्षित हैं. आंकड़े के मुताबिक अकेले यूपी में सर्वाधिक बच्चे गायब हुए. दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है. बच्चों की गुमशुदगी के मामले में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है. आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही अंतराल में उत्तर प्रदेश से 9,857 बच्चे लापता हुआ. मध्य प्रदेश में लापता हुए बच्चों की संख्या 8,247 थी, जबकि महाराष्ट्र में लापता बच्चों की तादाद 6,410 रही.

केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लापता बच्चों की तलाश के लिए आपरेशन मुस्कान नाम से एक योजना शुरू की. यह ऑपरेशन स्माइल की तर्ज पर चलाया गया, लेकिन यह मात्र एक महीने के लिए चला. गृह विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पाण्डा के ने यह स्वीकार किया कि यह मात्र एक महीने का विशेष अभियान था जो एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया. एक महीने के लिए चलाई गई इस योजना में महिला एवं बाल विकास से समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के साथ-साथ पुलिस की महिला सेल और प्रदेश में कार्यरत सभी 35 एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को शामिल किया गया था. इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए, लेकिन यह एक महीने चल कर थम गया. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व गाजियाबाद में एक महीने का विशेष अभियान आपरेशन स्माइल चलाया गया था. इस अभियान की सफलता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पूरे देश में इस तरह का विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया था, लेकिन राज्य सरकारों ने एक महीने की औपचारिता पूरी कर बच्चों का मसला वैसे ही अधर में छोड़ दिया.

अब केंद्र सरकार ने लापता बच्चों को तलाश कर उन्हें अभिभावकों को सुपुर्द किये जाने के विशेष अभियान में अच्छा काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने का भी फैसला किया है. केंद्र ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से इस बारे में आख्या मांगी है. प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पाण्डा की अध्यक्षता में इस सिलसिले में एक उच्चस्तरीय बैठक भी हुई और अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की गई. गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने खास तौर पर बच्चों को अगवा करने वाले गिरोहों का पता लगाने और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. पाण्डा ने कहा कि लापता बच्चों की तलाश के कार्य को दैनिक कार्य की भांति नहीं लिया जाएगा. पिछले दिनों हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह सचिव कमल सक्सेना, डीजी मानवाधिकार एवं प्रभारी महिला सम्मान प्रकोष्ठ, सुतापा सान्याल, विशेष सचिव गृह मिनिस्ती एस, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एचसी अवस्थी, पुलिस महानिरीक्षक अपराध आरके स्वर्णकार, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन जकी अहमद समेत कई अधिकारी सम्मिलित थे.

विचित्र विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार ताकीद किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकारें लापता बच्चों को लेकर संवेदनशील नहीं है. उल्टे गलत-सलत आंकड़े पेश कर अदालत को गुमराह करने की भी कोशिशें चल रही हैं. अदालत ने न केवल सरकार को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि 2013-15 के दौरान 25,834 बच्चे लापता हुए, जबकि इसके उलट राज्यसभा में कहा गया था कि 79,721 बच्चे लापता हुए. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि 15 साल गुजर जाने के बाद भी जेजे एक्ट के तहत एडवाइजरी बोर्ड का गठन नहीं किया गया. सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि तीन वर्षों में तकरीबन दो लाख से अधिक बच्चे लापता हुए. इनमें से अधिकतर बच्चों का इस्तेमाल बाल मजदूरी और देह व्यापार जैसे धंधों में हो रहा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कह चुका है देश में हर साल 40 हजार से अधिक बच्चे गुम होते हैं. एक जिम्मेवार राष्ट्र और संवेदनशील समाज के लिए यह शर्मनाक है. पिछले साल सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तथ्य पेश किया कि देश में बच्चों का अपहरण करने वाले कई गैंग सक्रिय हैं, लेकिन इन गैंगों की पहचान नहीं की गई है. नतीजतन गायब होते बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है. देश का कानून बच्चों को हिफाजत देने में अक्षम साबित हुआ है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में व्यवस्था है कि मानव तस्करी और बालश्रम के अलावा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वीकार चुका है कि उसके पास बालश्रम के ढेर सारे मामले दर्ज हैं. भारत बच्चों की तस्करी वाले दुनिया के खतरनाक देशों में शुमार हो चुका है. भारत दुनिया में 14 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा बाल श्रमिकों वाला देश है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में तकरीबन बीस करोड़ से अधिक बच्चे जोखिम भरे काम करते हैं और उनमें से सर्वाधिक संख्या भारतीय बच्चों की ही है. यूनिसेफ के मुताबिक, विश्व में करीब दस करोड़ से अधिक लड़कियां विभिन्न खतरनाक उद्योग-धंधों में काम कर रही हैं. अराजक तत्व सुनियोजित तरीके से बच्चों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की सप्लाई में भी कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी के बच्चों पर आफत

एक तरफ प्रदेश के बच्चों की गुमशुदगी अभिभावकों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों को मिल रहे प्रदूषित पोषण से उत्तर प्रदेश के बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है, वे नाटे होते जा रहे हैं. अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो यूपी के बच्चे बौने होते जा रहे हैं. क्रोधित एक अभिभावक ने कहा कि नेताओं के चरित्र की तरह हमारे बच्चे आकृति में बौने हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के बच्चों का बौने होते जाना कोई हवा-हवाई बात नहीं बल्कि बाल विकास मंत्रालय के एक सर्वे की चौंकाने वाली रिपोर्ट है. मामला सामने आने के बाद बच्चों को पहले हॉटकुक खिलाया गया और फिर लंबाई बढ़ाने वाला भोजन दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ. सामान्यत: तीन साल के लड़के की लंबाई 94.9 सेंटीमीटर और लड़की की 93 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण में लड़कों की लंबाई 89 सेंटीमीटर व लड़कियों की 88 सेंटीमीटर ही मिली है. सर्वे में लखनऊ और इलाहाबाद के बच्चों की लंबाई सामान्य पाई गई, लेकिन बरेली और शाहजहांपुर में दस फीसदी से अधिक बच्चों की लंबाई सामान्य से कम मिली है. इन जिलों के 3.22 लाख बच्चों की लंबाई नापी गई, यहां तीन साल की लड़कियों की औसत ऊंचाई 90-91 सेंटीमीटर के बीच मिली. वहीं पीलीभीत में तीन साल के लड़कों की ऊंचाई 89 सेंटीमीटर व लड़कियों की 87 से 88 सेंटीमीटर पाई गई. इसी तरह बदायूं में भी 45 हजार बच्चों की लंबाई नापी गई, जिसमें से तीन साल के 40 फीसदी बच्चों की लंबाई 88 से 89 सेंटीमीटर के बीच मिली. चार साल के बच्चों की लंबाई 100.2 सेंटीमीटर मिली है, जबकि इस उम्र में 102.9 सेंटीमीटर होनी चाहिए. लड़कियों की लंबाई 101 सेंटीमीटर के बजाय 99.1 सेंटीमीटर मिली है. इसके अलावा यूपी के कई जिलों में सर्वे किया गया, जिसमें बच्चों की ऊंचाई और वजन कम मिला, यदि इन बच्चों का वजन और इनकी लंबाई लगातार गिरती रही तो यह कुपोषण की श्रेणी में आ जाएंगे. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस सर्वे के खुलासे से पहले सभी जनपदों की ओर से भेजे गए बच्चे के वजन और लंबाई के आंकड़ों का तुलनात्मक मिलान किया गया, तब आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी किए गए. सर्वे से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि बच्चों के बौने होने का प्रमुख कारण दूषित भोजन, पानी और वातावरण है, जिस पर न सरकारों का कोई ध्यान है और प्रशासन का. खाद्य पदार्थों में खतरनाक मिलावटें आम बात है, लेकिन इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है. दूध शत-प्रतिशत अशुद्ध है, जिसे पीकर प्रदेश के नौनिहाल आदर्श बौने बन रहे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेता विदेशों में जाकर वहां की खेती-किसानी, वहां के शुद्ध दूध और वहां के शुद्ध भोजन की प्रशंसा करते नहीं अघाते, लेकिन उन्हें अपने प्रदेश की दारुण हालत देखकर कतई शर्म नहीं आती. खाद्य पदार्थ में मिलावट गंभीर अपराध है. चीन समेत की देश में इस अपराध की सजा मौत है. लेकिन भारतवर्ष में मिलावट की छूट है और खरीदार की मौत है. ■

मरते किसानों के प्रदेश में अखिलेश-ऐप

उत्तर प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों या अपराध के शिकार आम लोगों को राहत पहुंचाने और उनसे संवाद स्थापित करने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब अपने नाम से व्हाट्स-ऐप की तर्ज पर अखिलेश-ऐप लाकर उसके माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित करेंगे.

सूफी यायावर

अखिलेश-ऐप के जरिये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वे प्रचार-प्रसार भी करेंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 13 अगस्त को खुद ही समाजवादी-अखिलेश के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया. अपने नाम का मोबाइल-एप्लिकेशन लॉन्च करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सोशल मीडिया जनता से संवाद कायम करने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है. स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण में इसकी सशक्त भूमिका हो सकती है. युवा पीढ़ी को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी. इससे जनता के साथ समाजवादी पार्टी के गहरे रिश्तों को और मजबूती मिल सकेगी. लोगों की दिक्कतों और जरूरतों की जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया जन-प्रतिनिधियों के लिए भी बेहद उपयोगी है.

अखिलेश ने कहा कि संचार क्रांति से दुनिया में बहुत बदलाव आ गया है. टाइप राइटर से लेकर कम्प्यूटर और टेलीफोन से लेकर एप्लिकेशन तक का सफर तकनीक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है. लेकिन सूचना देना ही इसका एकमात्र इस्तेमाल नहीं है. इससे हमारी जिन्दगी और रहन सहन में भी बहुत बदलाव आ सकता है. हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नई तकनीक का जुड़ाव बहुत फायदेमंद साबित होगा.

अखिलेश ने कहा कि सिस्टम लागू होने से विकास की नई-नई जानकारियां किसानों तक पहुंचेगी और गांवों की स्थिति भी सुधरेगी. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनेगा. खेती अधिक लाभदायक और उन्नत होगी. उन्होंने कहा कि इसको लांच करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है. सूचना अपने में एक ताकत है. अखिलेश-ऐप के जरिए अब लोग बेहतर ढंग से अपडेट रह सकेंगे. यह उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के मुकाबले डिजिटल सक्रिय बनाने में एक बड़ा कदम होगा.

इस एप्लिकेशन के माध्यम से समाजवादी पार्टी की खबरें, प्रेस विज्ञप्तियां और मुख्यमंत्री के सोशल नेटवर्क के विषयवस्तु की भी जानकारी मिल सकेगी. इस एप्लिकेशन को समाजवादी पार्टी की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है. यह एप्लिकेशन तीन तरह के प्लेटफार्म आईओएस ऐप्पल, ऐंड्रॉयड तथा विंडोज पर उपलब्ध है. यह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें समाजवादी सरकार के डाटा, जनहित के सभी कार्य, समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, वीडियो एवं सोशल नेटवर्किंग साईट भी रहेंगी. समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल क्षेत्र में प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि वे लोगों को जोड़ने के लिए ईमेल, वेबसाइट, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि का इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकें. पार्टी इन माध्यमों की उपयोगिता सन् 2017 के चुनावों में कारगर तरीके से करना चाहती है, ताकि समाजवादी सरकार की उपलब्धियां और पार्टी का प्रचार आसानी से लोगों तक पहुंच सके.

समाजवादी सरकार द्वारा इस तरह का दिवास्वप्न दिखाए जाने के बरक्स जमीनी हकीकत यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यूपी का किसान आत्महत्याएं कर रहा है और जो जीवित है वह हताश है और खून के आंसू रो रहा है. प्राकृतिक आपदा में किसानों की हजारों-लाखों की फसल बर्बाद होती है, तो सरकार किसान को सौ रुपये का चेक थमा देती है और उस पर सपा के नेता दावा करते हैं कि उनकी पार्टी किसानों का भला कर रही है, किसानों के करोड़ों रुपये चीनी मिलों पर बकाया हैं, लेकिन उसके भुगतान की कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होती. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने नाम से मोबाइल-एप्लिकेशन लॉन्च करने या अपने घर से बड़ी-बड़ी योजनाओं के शिलान्यास का बटन दबाते रहते हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह झुंझलाते रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com